



# सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

खण्ड 77] प्रयागराज, शनिवार, 7 जनवरी, 2023 ई० (पौष 17, 1944 शक संवत्) [संख्या 1

### विषय-सूची

हर भाग के पन्ने अलग-अलग किये गये हैं, जिससे इनके अलग-अलग खण्ड बन सके।

विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा	विषय	पृष्ठ संख्या	वार्षिक चन्दा
सम्पूर्ण गजट का मूल्य		रु०			रु०
भाग 1— विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस	1-20	3075	भाग 4— निदेशक, शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश	..	975
भाग 1—क नियम, कार्य-विधियाँ, आज्ञायें, विज्ञप्तियाँ इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया	1-10	1500	भाग 5—एकाउन्टेन्ट जनरल, उत्तर प्रदेश		975
भाग 1—ख (1) औद्योगिक न्यायाधिकरणों के अभिनिर्णय			भाग 6—(क) बिल, जो भारतीय संसद में प्रस्तुत किये गये या प्रस्तुत किये जाने से पहले प्रकाशित किये गये		975
भाग 1—ख (2)—श्रम न्यायालयों के अभिनिर्णय			(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		
भाग 2—आज्ञायें, विज्ञप्तियाँ, नियम और नियम विधान, जिनको केन्द्रीय सरकार और अन्य राज्यों की सरकारों ने जारी किया, हाई कोर्ट की विज्ञप्तियाँ, भारत सरकार के गजट और दूसरे राज्यों के गजटों का उद्धरण	..	975	भाग 6—क—भारतीय संसद के ऐक्ट		
भाग 3—स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़पत्र, खण्ड क—नगरपालिका परिषद्, खण्ड ख—नगर पंचायत, खण्ड ग—निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड घ—जिला पंचायत	1-28	975	भाग 7—(क) बिल, जो राज्य की धारा सभाओं में प्रस्तुत किये जाने के पहले प्रकाशित किये गये		
			(ख) सिलेक्ट कमेटियों की रिपोर्ट		975
			भाग 7—क—उत्तर प्रदेशीय धारा सभाओं के ऐक्ट		
			भाग 7—ख—इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अनुविहित तथा अन्य निर्वाचन सम्बन्धी विज्ञप्तियाँ	..	
			भाग 8—सरकारी कागज-पत्र, दवाई हुई रुई की गाठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आँकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आँकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि	1-13	975
			स्टोर्स-पर्वज विभाग का क्रोड़ पत्र	..	1425

## आवश्यक सूचना

1—गजट के न मिलने की सूचना गजट में प्रकाशित होने से 15 दिन के अन्दर निदेशक, मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज को प्राप्त होनी चाहिये। उसके बाद के परिवादों की कोई सुनवाई न होगी। केवल गजट की वही प्रतियां पुनः बगैर कीमत भेजी जा सकेंगी जो डिलीवरी न होने के कारण वापस आई हों।

2—सम्पूर्ण गजट के ग्राहकों को असाधारण गजट की सम्पूर्ति की जाती है। असाधारण गजट नवीन राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ से वितरित होता है। अतः असाधारण गजट के सम्बन्ध में यदि कोई पत्र-व्यवहार करना हो तो कृपया उक्त पते पर ही करें। सम्पूर्ण गजट का वार्षिक एवं अर्द्धवार्षिक चन्दा 20 सितम्बर, 1997 से क्रमशः रु0 3,075.00 एवं रु0 1,560.00 हो गया है।

3—गजट के प्रत्येक भाग का वार्षिक चन्दा प्रत्येक के सामने अलग-अलग अंकित है। भाग-1 का वार्षिक चन्दा रु0 1,500.00 तथा छमाही चन्दा रु0 780.00 है। स्टोर्स-पर्चेज का वार्षिक चन्दा रु0 1,425.00 तथा अर्द्धवार्षिक चन्दा रु0 750.00 है। इसके अतिरिक्त प्रत्येक भाग का वार्षिक चन्दा रु0 975.00 तथा अर्द्धवार्षिक रु0 555.00 है।

प्रत्येक गजट अथवा गजट (साधारण अथवा असाधारण) के भागों के वार्षिक एवं अर्द्धवार्षिक चन्दे की राशि में यदि कोई परिवर्तन किन्हीं अपरिहार्य कारणोंवश होता है तो उसकी सूचना अलग से दी जायेगी।

4—उत्तर प्रदेश राजपत्र (गजट) के स्थायी ग्राहकों को सूचित किया जाता है कि वे अर्द्धवार्षिक और वार्षिक चन्दा समाप्त होने की तारीख से एक मास पूर्व ही अपना नवीन चन्दा गजट के लिये इस कार्यालय को भेज देने की कृपा करें, जिससे गजट के भेजने का क्रम टूटने न पावे और नियमित रूप से उन्हें हम गजट भेजते रहें। इससे ग्राहकों को भी असुविधा नहीं होगी और वे निश्चित समय पर गजट प्राप्त कर सकेंगे।

इस सम्बन्ध में, मैं यह भी सूचित करना आवश्यक समझता हूँ कि पूर्ण वर्ष के ग्राहक अब जनवरी से दिसम्बर तक के लिये ही बनाये जायेंगे। इनके बीच के महीनों में चन्दा प्राप्त होने पर ग्राहकों का नाम उसी वर्ष के जुलाई से दिसम्बर तक के लिये तथा जैसी स्थिति होगी, अंकित किया जायेगा।

ग्राहकों से यह भी निवेदन है कि वे अपने पत्रों का उत्तर शीघ्र पाने के लिये पत्र-व्यवहार करते समय अपनी ग्राहक संख्या अवश्य लिखें अन्यथा उत्तर देने में इस कार्यालय को कठिनाई या विलम्ब हो सकता है।

अनिल पाठक,  
निदेशक,  
मुद्रण एवं लेखन-सामग्री, विभाग,  
उ0प्र0, प्रयागराज।

**भाग 1**

विज्ञप्ति-अवकाश, नियुक्ति, स्थान-नियुक्ति, स्थानान्तरण, अधिकार और दूसरे वैयक्तिक नोटिस।

**विधान परिषद् सचिवालय, उत्तर प्रदेश**

सेवानिवृत्ति

17 सितम्बर, 2022, ई0

सं0 2306(1)(अधिष्ठान)/वि0प0-267/84—कुमारी मीनाक्षी लोहानी, सूचना अधिकारी, विधान परिषद्, सचिवालय, उत्तर प्रदेश अपनी 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के पश्चात् दिनांक 30 सितम्बर, 2023 के अपराह्न से सेवानिवृत्त हो जायेंगी।

आज्ञा से,  
डा0 राजेश सिंह,  
प्रमुख सचिव।

**सचिवालय प्रशासन**

अनुभाग-1

पदोन्नति

04 अगस्त, 2022, ई0

सं0 20-1001(099)/1884/2020-1—श्री राज्यपाल महोदय, उ0प्र0 सचिवालय के अधिकारी श्री राजेश लाल श्रीवास्तव, उप सचिव (लेखा), राजनैतिक पेंशन एवं होमगार्ड्स विभाग को संयुक्त सचिव (लेखा) के पद {वेतनमान रु0 37,400-67,000 (ग्रेड-वेतन रु0 8,700) पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-13} पर पदोन्नति की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2—श्री राजेश लाल श्रीवास्तव को प्रोन्नति के पद पर योगदान देने की तिथि से ही संयुक्त सचिव (लेखा) के पद पर प्रोन्नत माना जायेगा।

3—श्री राजेश लाल श्रीवास्तव के तैनाती का आदेश पृथक् से निर्गत किया जायेगा।

**तैनाती**

सं0 20-1001(099)/84/2022-1/I/198702/2022—तात्कालिक प्रभाव से श्री प्रभाकर चन्द्र मिश्र, उप सचिव, राजस्व विभाग को एतद्वारा स्थानान्तरित करते हुये उप सचिव, प्राविधिक शिक्षा विभाग के पद पर तैनात किया जाता है।

2—श्री प्रभाकर चन्द्र मिश्र को निर्देशित किया जाता है कि नवीन तैनाती/आवंटित विभाग में बिना प्रतिस्थानी की प्रतीक्षा किये तत्काल योगदान आख्या प्रस्तुत करें।

10 अगस्त, 2022, ई0

**तैनाती**

सं0 20-1001(099)/87/2022-1/I/200534/2022—तात्कालिक प्रभाव से श्री शिव गोपाल सिंह, संयुक्त सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग को स्थानान्तरित कर एतद्वारा संयुक्त सचिव, कारागार प्रशासन एवं सुधार विभाग के पद पर तैनात किया जाता है।

2—श्री शिव गोपाल सिंह, संयुक्त सचिव को निर्देशित किया जाता है कि नवीन तैनाती/आवंटित विभाग में तत्काल योगदान आख्या प्रस्तुत करें।

आज्ञा से,  
रचना गुप्ता,  
संयुक्त सचिव।

**गोपन विभाग**

अनुभाग-1

कार्यालय-ज्ञाप

31 अगस्त, 2022 ई0

सं0 981/22-पच्चीस-1-7/2/7/95-सी0एक्स0(1)-मा0 न्यायमूर्ति श्री अरविन्द कुमार मिश्र-I, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के तालिका में उल्लिखित अवधियों के अवकाश की, माननीया राज्यपाल एतद्वारा स्वीकृति प्रदान करती हैं :

क्रमांक	अवकाश की अवधि तथा प्रकृति
1	2
1	दिनांक 21-02-2022 से दिनांक 25-02-2022 तक का 05 (पांच) दिन का पूर्ण भत्ते पर देय अवकाश।
2	दिनांक 02-03-2022 से दिनांक 05-03-2022 तक का 04 (चार) दिन का पूर्ण भत्ते पर देय अवकाश।
3	दिनांक 11-03-2022 01 (एक) दिन का पूर्ण भत्ते पर देय अवकाश।
4	दिनांक 31-03-2022 से दिनांक 01-04-2022 तक का 02 (दो) दिन का पूर्ण भत्ते पर देय अवकाश।
5	दिनांक 07-04-2022 का 01 (एक) दिन का पूर्ण भत्ते पर देय अवकाश।
6	दिनांक 22-04-2022 का 01 (एक) दिन का पूर्ण भत्ते पर देय अवकाश।

आज्ञा से,  
कृष्ण गोपाल,  
विशेष सचिव।

**गृह विभाग  
(पुलिस सेवायें)**

अनुभाग-1

प्रोन्नति

07 जनवरी, 2022 ई0

सं0 4012/छ:पु0से0-1-2021-रिट-29/2021-मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में रिट याचिका संख्या-ए-11409/2021 शैलेन्द्र कुमार शर्मा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य योजित की गयी। मा0 उच्च न्यायालय द्वारा योजित याचिका में दिनांक 27 सितम्बर, 2021 को आदेश पारित किया गया, जिसका प्रभावी अंश निम्नवत् है :

After hearing learned counsel for the parties and going through the record, it is evident that once petitioners have been exonerated and minor penalty of censure inflicted on them have been revoked then they are entitled to be considered for promotion, for which purpose respondents are directed to convene review DPC on the same parameters on which DPC was convened on February 18, 2021 and consider the case of the petitioners afresh on the basis of fresh material and pass appropriate orders within 30 days from the date of receipt of computer downloaded copy in PDF form of this order strictly in accordance with law.

In above terms, writ petition is disposed of.

2-मा0 उच्च न्यायालय के उक्त आदेश के अनुपालन में याची श्री शैलेन्द्र कुमार सिंह, ज्येष्ठता क्रमांक-56 एवं श्री उमेश कुमार पाण्डेय, ज्येष्ठता क्रमांक-76 के दण्डादेश निरस्त किये जाने के फलस्वरूप प्रत्यावेदन दिनांक 30 सितम्बर, 2021 के क्रम में शासन के पत्र दिनांक 20 अक्टूबर, 2021 अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन से आख्या/प्रस्ताव प्राप्त किया गया। अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन द्वारा अपने पत्र दिनांक 27 अक्टूबर, 2021 द्वारा

उपलब्ध करायी गयी आख्या पर सम्यक् विचारोपरान्त शासन द्वारा निर्णय लेते हुये शासन के पत्र दिनांक 09 नवम्बर, 2021 द्वारा याचीगणों से सम्बन्धित ब्राडशीट मूलरूप में मा0 उच्च न्यायालय में लम्बित विभिन्न रिट याचिकाओं एवं विशेष अपीलों/अवमाननावाद में मा0 उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय के अधीन रिव्यू डीपीसी कराये जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही कराये जाने का अनुरोध किया गया।

3-शासन के उक्त प्रस्ताव पर मा0 उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 27 सितम्बर, 2021 के अनुपालन में चयन वर्ष 2020-2021 में निरीक्षक पुलिस उपाधीक्षक प्रोन्नत कोटे में अनुपूरक डीपीसी कराये जाने हेतु विभागीय चयन समिति की दिनांक 15 दिसम्बर, 2021 को अपरान्ह 04.00 बजे उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज, मुख्यालय में सम्पन्न बैठक में सम्यक् विचारोपरान्त की गयी संस्तुति उ0प्र0 लोक सेवा आयोग, प्रयागराज के पत्र संख्या 61/10/पी0/सेवा-1/2020-2021, दिनांक 22 दिसम्बर, 2021 द्वारा उपलब्ध करायी गयी।

4-चयन वर्ष 2020-2021 में निरीक्षक पुलिस से पुलिस उपाधीक्षक प्रोन्नत कोटे में पुलिस उपाधीक्षक पद पर उपलब्ध 02 रिक्तियों के सापेक्ष लोक सेवा आयोग, उत्तर प्रदेश के अधीन गठित विभागीय चयन समिति की बैठक दिनांक 15 दिसम्बर, 2021 के क्रम में मा0 आयोग की संस्तुति के परिप्रेक्ष्य में निम्नलिखित पुलिस निरीक्षकों की पुलिस उपाधीक्षक साधारण वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड वेतन रु0 5,400/- पुनरीक्षित पे-मैट्रिक्स, लेवल-10, रु0 56,100-1,77,500 में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से प्रोन्नत करने की श्री राज्यपाल महोदया एतद्द्वारा सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती है :

क्र0 सं0	ज्येष्ठता क्रमांक	नाम
1	2	3
1	56	श्री शैलेन्द्र कुमार शर्मा
2	76	श्री उमेश कुमार पाण्डेय

प्रश्नगत चयन मा0 उच्च न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या ए-11409/2021 शैलेन्द्र कुमार शर्मा व अन्य बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य तथा प्रकरण में यदि अन्य कोई याचिका लम्बित हो तो प्रश्नगत चयन उक्त याचिका में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन रहेगा।

5-उपर्युक्त प्रोन्नत आदेश में सम्मिलित कार्मिकों की तैनाती से पूर्व पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0/अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि उक्त कार्मिकों के विरुद्ध किसी भी प्रकार की विभागीय/अनुशासनिक कार्यवाही एवं ई0ओ0डब्लू0/ए0सी0ओ0/सी0बी0सी0आई0डी0/सतर्कता जांच आदि प्रचलित/लम्बित नहीं है। इस सम्बन्ध में अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन, उ0प्र0, लखनऊ स्वयं संतुष्ट हो लेंगे और यदि पुलिस उपाधीक्षक के पद पर प्रोन्नत किसी कार्मिक के विरुद्ध कोई भी प्रतिकूल तथ्य संज्ञान में आता है तो तत्काल सम्बन्धित कार्मिक की प्रोन्नति प्रतिबन्धित करते हुये उसकी सूचना शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

6-पुलिस उपाधीक्षक के पद पर प्रोन्नत कार्मिकों की तैनाती का आदेश निर्गत किये जाने से पूर्व अपर पुलिस महानिदेशक, प्रशासन, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रोन्नत कोटे में रिक्ति वास्तविक रूप से उपलब्ध है। प्रोन्नति कोटा में वास्तविक रूप से रिक्तियां उपलब्ध होने पर ही प्रोन्नत आदेश के सापेक्ष तैनाती का आदेश पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 द्वारा निर्गत किया जायेगा।

7-उपर्युक्त प्रोन्नत अधिकारी 02 वर्ष की अवधि तक परिवीक्षाधीन रहेंगे।

आज्ञा से,  
अवनीश कुमार अवस्थी,  
अपर मुख्य सचिव।

## अनुभाग-2

## सेवानिवृत्ति

23 सितम्बर, 2022 ई0

सं0 941 / डीजी / छ:पु0से0-2-2022-भारतीय पुलिस सेवा (उत्तर प्रदेश संवर्ग) के निम्नलिखित अधिकारी वर्ष, 2023 में अधिवर्षता आयु पूर्ण कर विभिन्न तिथियों को सेवानिवृत्त होंगे :

क्र0 सं0	अधिकारी का नाम	बैच	जन्म-तिथि	सेवानिवृत्ति की तिथि
1	2	3	4	5
1	श्री स्वामी प्रसाद	आई0पी0एस0-एस0पी0एस0-2007	05-01-1963	31-01-2023
2	श्री संजय कुमार-II	आई0पी0एस0-एस0पी0एस0-0	09-01-1963	31-01-2023
3	श्री गोपाल लाल मीना	आई0पी0एस0-आर0आर0-1987	10-01-1963	31-01-2023
4	श्री महेंद्र यादव	आई0पी0एस0-एस0पी0एस0-2008	13-01-1963	31-01-2023
5	श्री सौमित्र यादव	आई0पी0एस0-एस0पी0एस0-2007	16-01-1963	31-01-2023
6	श्री सुधीर कुमार सिंह	आई0पी0एस0-एस0पी0एस0-2008	29-01-1963	31-01-2023
7	श्री नरेन्द्र प्रताप सिंह	आई0पी0एस0-एस0पी0एस0-0	06-02-1963	28-02-2023
8	श्री ब्रज भूषण	आई0पी0एस0-आर0आर0-1991	07-02-1963	28-02-2023
9	डा0 राजेन्द्र पाल सिंह	आई0पी0एस0-आर0आर0-1987	25-02-1963	28-02-2023
10	डा0 देवेन्द्र सिंह चौहान	आई0पी0एस0-आर0आर0-1988	20-03-1963	31-03-2023
11	श्री अनिल कुमार अग्रवाल	आई0पी0एस0-आर0आर0-1988	29-04-1963	30-04-2023
12	डा0 राज कुमार विश्वकर्मा	आई0पी0एस0-आर0आर0-1988	10-05-1963	31-05-2023
13	श्री राम लाल वर्मा	आई0पी0एस0-एस0पी0एस0-2004	11-05-1963	31-05-2023
14	श्री चंद्र प्रकाश-I	आई0पी0एस0-आर0आर0-1989	21-05-1963	31-05-2023
15	श्री मानिक चंद सरोज	आई0पी0एस0-एस0पी0एस0-2011	30-05-1963	31-05-2023
16	श्री सुरेंद्र बहादुर	आई0पी0एस0-एस0पी0एस0-2010	05-06-1963	30-06-2023
17	श्री सभा राज	आई0पी0एस0-एस0पी0एस0-2007	07-06-1963	30-06-2023
18	श्री मिर्जा मंजर बेग	आई0पी0एस0-एस0पी0एस0-2010	01-07-1963	30-06-2023
19	श्री जय प्रकाश	आई0पी0एस0-एस0पी0एस0-2010	01-07-1963	30-06-2023
20	श्री बालेंदु भूषण सिंह	आई0पी0एस0-एस0पी0एस0-2008	15-07-1963	31-07-2023
21	श्री संतोष कुमार सिंह-II	आई0पी0एस0-एस0पी0एस0-2008	15-07-1963	31-07-2023
22	श्री सर्वेश कुमार राना	आई0पी0एस0-एस0पी0एस0-2008	25-07-1963	31-07-2023

1	2	3	4	5
23	श्री देवेन्द्र नाथ	आई0पी0एस0-एस0पी0एस0-2011	01-08-1963	31-07-2023
24	श्री अनिल कुमार	आई0पी0एस0-एस0पी0एस0-2007	10-08-1963	31-08-2023
25	श्री ब्रजेश सिंह	आई0पी0एस0-एस0पी0एस0-0	09-10-1963	31-10-2023
26	श्री भगीरथ पी0 जोगदंड	आई0पी0एस0-आर0आर0-1991	28-10-1963	31-10-2023
27	श्री अंजू गुप्ता	आई0पी0एस0-यूकेडी-1990	05-11-1963	30-11-2023
28	श्री पूनम श्रीवास्तव	आई0पी0एस0-एस0पी0एस0-2004	28-12-1963	31-12-2023
29	श्री अनंत देव	आई0पी0एस0-एस0पी0एस0-2006	30-12-1963	31-12-2023
30	श्री सत्येंद्र कुमार सिंह	आई0पी0एस0-एस0पी0एस0-2002	01-01-1964	31-12-2023

आज्ञा से,  
कुमार प्रशान्त,  
विशेष सचिव।

## औद्योगिक विकास विभाग

अनुभाग-4

नियुक्ति

13 सितम्बर, 2022 ई0

सं0 1590/77-4-22-12यूपीसीडा/22-उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) में कनिष्ठ सहायक के पद पर कार्यरत स्व0 रहे ऋषि कनौजिया पुत्र स्व0 श्रीराम कनौजिया की मृत्यु होने के फलस्वरूप मृतक आश्रित कोटे के अन्तर्गत कनिष्ठ सहायक के पद पर नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यूपीसीडा के पत्रांक 5793/एसआईडीए/स्था0पी0एफ0ग0 579, दिनांक 24 मार्च, 2022 द्वारा की गयी संस्तुति के क्रम में उत्तर प्रदेश सेवाकाल में मृत सरकारी सेवक के आश्रितों की भर्ती नियमावली, 1974 (यथासंशोधित) को औद्योगिक विकास प्राधिकरणों के लिये अंगीकृत किये जाने के सम्बन्ध में निर्गत शासनादेश दिनांक 30 जून, 2021 में उल्लिखित प्राविधान के दृष्टिगत श्री रवि कनौजिया पुत्र स्व0 श्रीराम कनौजिया को मृतक आश्रित के रूप में उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) में कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से कनिष्ठ सहायक के पद पर वेतनमान रु0 5,200-20,200 एवं ग्रेड पे रु0 2,000.00 में अस्थायी रूप से निम्नलिखित शर्तों के अधीन एतद्वारा नियुक्ति प्रदान की जाती है—

(1) श्री रवि कनौजिया को 02 वर्ष की परीक्षा अवधि पर रखा जायेगा।

(2) श्री रवि कनौजिया द्वारा मृतक सरकारी सेवक के परिवार के अन्य सदस्यों का अनुरक्षण किया जायेगा, जो कि स्वयं का अनुरक्षण करने में असमर्थ हैं और उक्त मृत सरकारी सेवक पर उसकी मृत्यु के ठीक पूर्व आश्रित थे। यदि श्री रवि कनौजिया द्वारा अनुरक्षण करने से इंकार किया जाता है तो उनकी सेवायें उत्तर प्रदेश सरकारी सेवक (अनुशासन एवं अपील) नियमावली, 1999 के अनुसरण में समाप्त की जा सकती है।

(3) श्री रवि कनौजिया द्वारा 01 वर्ष के भीतर ही कम्प्यूटर प्रचालन में सी0सी0सी0 प्रमाण-पत्र के साथ हिन्दी टंकण में 25 शब्द प्रति मिनट की अपेक्षित गति प्राप्त कर ली जायेगी और यदि वह ऐसा करने में विफल रहते हैं तो उनकी सामान्य वार्षिक वेतनवृद्धि रोक ली जायेगी तथा कम्प्यूटर प्रचालन में अपेक्षित प्रमाण-पत्र और टंकण में अपेक्षित गति प्राप्त करने के लिये उन्हें 01 वर्ष की अग्रेतर अवधि प्रदान की जायेगी और यदि बढ़ायी गयी अवधि में भी वह कम्प्यूटर प्रचालन में अपेक्षित प्रमाण-पत्र और टंकण में अपेक्षित गति प्राप्त करने में विफल रहते हैं तो उनकी सेवायें समाप्त कर दी जायेंगी।

(4) श्री रवि कनौजिया की सेवायें उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण केन्द्रीयित सेवा नियमावली, 2018 से संचालित होंगी।

2—उपर्युक्त शर्तों के अधीन उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) में अपनी योगदान आख्या नियुक्ति-पत्र प्राप्त होने की तिथि से 30 दिन के अन्दर अवश्य प्रस्तुत करना होगा अन्यथा नियुक्ति-पत्र निरस्त मान लिया जायेगा।

आज्ञा से,  
अरविन्द कुमार,  
अपर मुख्य सचिव।

### वित्त विभाग

[सेवायें]

अनुभाग-1

सेवानिवृत्ति

04 अगस्त, 2022 ई0

सं0 10-20099/532/2022-23-I/198426/2022—राष्ट्रीय बचत निदेशालय, उ0प्र0 के अन्तर्गत कार्यरत श्री अरूण प्रकाश द्विवेदी, उप निदेशक, राष्ट्रीय बचत, विन्ध्याचल मण्डल, मीरजापुर 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूर्ण करने के फलस्वरूप दिनांक 31 दिसम्बर, 2022 के अपरान्ह में वित्तीय नियम संग्रह खण्ड-2 भाग-2 से 4 के मूल नियम-56 (क) के अन्तर्गत सेवानिवृत्त हो जायेंगे।

आज्ञा से,  
मोहम्मद शाहिद,  
विशेष सचिव।

### वित्त (लेखा परीक्षा) विभाग

अनुभाग-2

पदोन्नत/तैनाती

25 अगस्त, 2022 ई0

सं0 10-25001(002)/2/2022-4-I/205191/2022—उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा सेवा समूह 'क' (वेतनमान रु0 37,400-67,000, ग्रेड-वेतन रु0 8,900) पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल-13-क) में पदोन्नति हेतु मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में दिनांक 04 अगस्त, 2022 को संपन्न विभागीय चयन समिति की बैठक में की गई संस्तुति पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा चयन वर्ष, 2021-22 की रिक्ति के सापेक्ष श्री अजय कुमार सिंह, संयुक्त निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0 को निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, उ0प्र0, प्रयागराज के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नत करते हुये तैनात किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती हैं।

2—उक्त पदोन्नति मा0 उच्च न्यायालय के समक्ष प्रचलित रिट याचिका संख्या 19395/2020 श्याम सिंह बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित होने वाले अन्तिम निर्णय के अधीन होगी।

3—श्री अजय कुमार सिंह द्वारा अपने पद का तत्काल कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

आज्ञा से,  
प्रशान्त त्रिवेदी,  
अपर मुख्य सचिव।



07 सितम्बर, 2022 ई0

सं0 05/2022/आडिट-2-I/210066/2022-फाइल संख्या-10-25001/595/2021-4—उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा सेवा समूह 'क' (ज्येष्ठ वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड-वेतन रु0 7,600) पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल-12) में पदोन्नति हेतु दिनांक 22 जून, 2022 को संपन्न विभागीय चयन समिति की बैठक में की गई संस्तुति पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा श्री अनिल कुमार जैन, उप निदेशक, सहारनपुर मण्डल, सहारनपुर को संयुक्त निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नित प्रदान करने तथा संयुक्त निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, प्रयागराज (निदेशालय) के रिक्त पद पर तैनात किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती हैं।

2—श्री अनिल कुमार जैन, संयुक्त निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, प्रयागराज (निदेशालय) के पद पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगे।

सं0 06/2022/आडिट-2-I/210327/2022-फाइल संख्या-10-25099/1265/2021-4—उत्तर प्रदेश स्थानीय निधि लेखा परीक्षा सेवा समूह 'क' (वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड-वेतन रु0 6,600) पुनरीक्षित पे मैट्रिक्स लेवल-11) में पदोन्नति हेतु दिनांक 22 जून, 2022 को संपन्न विभागीय चयन समिति की बैठक में की गई संस्तुति पर सम्यक् विचारोपरान्त श्री राज्यपाल द्वारा श्री रत्नेश्वर भारती, जो सम्प्रति लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ में लेखाधिकारी के पद पर प्रतिनियुक्ति के आधार पर तैनात हैं, को उप निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग के पद पर कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से पदोन्नित प्रदान करने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान की जाती हैं। श्री रत्नेश्वर भारती, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ में पूर्ववत् लेखाधिकारी के पद पर बने रहेंगे।

2—श्री रत्नेश्वर भारती, उप निदेशक, स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय, लखनऊ में लेखाधिकारी के पद पर तत्काल कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक शासन को उपलब्ध करायेंगे।

आज्ञा से,  
हरिश्चन्द्र,  
विशेष सचिव।

### श्रम विभाग

अनुभाग-4

सेवानिवृत्ति

01 अगस्त, 2022 ई0

सं0 1151(1)/36-4-2022-77/1993 टी0सी0—श्रमायुक्त संगठन, उ0प्र0 के अन्तर्गत कार्यरत अधिकारियों, जिनका सेवा विवरण नीचे अंकित है, स्तम्भ-6 में अंकित तिथि को 60 वर्ष की अधिवर्षता आयु पूरी कर लेने के उपरान्त सेवानिवृत्त हो चुके हैं/हो जायेंगे :

क्र0सं0	अधिकारी का नाम	पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	जन्म-तिथि	सेवानिवृत्त की तिथि
1	2	3	4	5	6
1	श्री एस0 पी0 शुक्ला	अपर श्रमायुक्त	कानपुर	15-12-1962	31-12-2022
2	श्री हरिश्चन्द्र सिंह	सहायक श्रमायुक्त	उन्नाव	30-10-1962	31-10-2022
3	श्री लालता प्रसाद	सहायक श्रमायुक्त	मेरठ सम्बद्ध गाजियाबाद	01-03-1962	28-02-2022
4	श्रीमती हेमा टेम्टा	सहायक श्रमायुक्त	कासगंज	27-08-1962	31-08-2022
5	श्री सुभाष चन्द्र मिश्र	गतिप्रेक्षण अधिकारी	मुख्यालय	01-08-1962	31-07-2022

आज्ञा से,  
प्रेम प्रकाश सिंह,  
विशेष सचिव।

**नमामि गंगे एवं ग्रामीण जलापूर्ति विभाग**

अनुभाग-4

नियुक्ति

05 अगस्त, 2022 ई0

सं0 864(1)/76-4-2022—श्री अनिल कुमार गुप्ता, सहायक अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग को नियमित चयनोपरान्त अधिशासी अभियन्ता, लघु सिंचाई विभाग के पद पर वेतनमान रु0 15,600-39,100, ग्रेड-वेतन रु0 6,600, पे मैट्रिक्स लेवल-11 में योगदान करने की तिथि से पदोन्नति प्रदान करते हुये 01 वर्ष की विहित परीक्षा पर रखने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2—श्री अनिल कुमार गुप्ता, लघु सिंचाई विभाग अग्रिम आदेशों तक पूर्ववत् अपने दायित्वों का निर्वहन करते रहेंगे।

3—उक्त अधिशासी अभियन्ता का तैनाती आदेश पृथक् से निर्गत किया जायेगा।

आज्ञा से,  
अखण्ड प्रताप सिंह,  
विशेष सचिव।

**महिला एवं बाल विकास विभाग**

अनुभाग-1

अधिसूचना

17 अगस्त, 2022 ई0

सं0 769(1)/60-1-22-1/13(69)/04—उ0 प्र0 किशोर न्याय (बालकों की देख-रेख और संरक्षण) नियम, 2019 के नियम, 88 के उपनियम-11 में विहित उपबन्धों के आलोक में राज्यपाल महोदय द्वारा श्री वी0 के0 माथुर, सेवानिवृत्त, मा0 न्यायमूर्ति की अध्यक्षता में गठित चयन समिति द्वारा उपलब्ध करायी गयी प्रतीक्षा सूची की वैद्यता को छः मास की अवधि के लिये बढ़ाये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

आज्ञा से,  
अनामिका सिंह,  
सचिव।

**राजस्व विभाग**

अनुभाग-8

शुद्धि-पत्र

16 सितम्बर, 2022 ई0

सं0 I/214495/1-रा0-8/1-8001(002)/1/2022—शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या—आई/212609/2022-रा0-8/1-8001(002)/1/2022, दिनांक 13 सितम्बर, 2022 द्वारा श्री तरुण कुमार मिश्र, संयुक्त संचालक चकबन्दी को तात्कालिक प्रभाव से अपर संचालक चकबन्दी (प्रा0) पर पदोन्नत करते हुये चकबन्दी निदेशालय में तैनात किया गया था। उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 13 सितम्बर, 2022 में त्रुटिवश पे मैट्रिक्स लेवल-13, के स्थान पर वेतनमान 1,18,500-2,14,100 पे मैट्रिक्स लेवल-13, ग्रेड पे रु0 8,700 अंकित हो गया है।

2—अतः उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 13 सितम्बर, 2022 में अंकित (वेतनमान 1,18,500-2,14,100 पे मैट्रिक्स लेवल-13, ग्रेड पे रु0 8,700) के स्थान पर पे मैट्रिक्स लेवल-13 पढ़ा जाये।

3—उक्त कार्यालय ज्ञाप दिनांक 13 सितम्बर, 2022 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाये। उक्त आदेश दिनांक 13 सितम्बर, 2022 के शेष तथ्य यथावत् रहेंगे।

## अनुभाग-14

## अधिसूचना

14 अक्टूबर, 2022 ई0

सं0 577/एक-14/2022—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-43 की उपधारा (3) के साथ पठित उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 1901) की धारा 48 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल यह घोषणा करती हैं कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित जिला फर्रुखाबाद के तीन ग्रामों, जो सरकारी अधिसूचना संख्या 1620/1-14-94-52(2)/90-9-90, दिनांक 31 अगस्त, 1994 द्वारा सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रियाओं के अधीन रखे गये थे, मैं उक्त संक्रियायें, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से बन्द की जाती हैं।

## अनुसूची

क्र0सं0	जिला	तहसील	परगना	ग्राम
1	फर्रुखाबाद	सदर	पहाड़ा	कटरी शिकारपुर
2	..	अमृतपुर	परमनगर	संतोषापुर
3	..	..	..	तेरा अकबरपुर

आज्ञा से,  
सुधीर गर्ग,  
प्रमुख सचिव।

## DEPARTMENT OF RAJASWA

## Anubhag-14

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no. 577/1-14/2022, dated October 14, 2022 :

## NOTIFICATION

October 14, 2022

**No. 577(i)/1-14/2022**—In exercise of the powers under section 48 of the Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901 (U. P. Act, no. 3 of 1901) read with Sub-section (3) of section 43 of the Uttar Pradesh Revenue Code, 2006 (U. P. Act, no. 8 of 2012), the Governor is pleased to declare that Survey and Record operations in three Villages of District Farrukhabad mentioned in the Schedule below, which were placed under the said operations *vide* Government Notification no. 1620/1-14-94-52(2)/90-9-90, dated August 31, 1994, are closed with effect from the date of publication of this notification in the Gazette.

## SCHEDULE

Sl. no.	District	Tehsil	Pargana	Village
1	Farrukhabad	Sadar	Pahara	Katari Shikarpur
2	Farrukhabad	Amritpur	Paramnagar	Santoshapur
3	Farrukhabad	Amritpur	Paramnagar	Tera Akbarpur

By order,  
SUDHIR GARG,  
Principal Secretary.

सं० 578/1-14/2022—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-43 की उपधारा (3) के साथ पठित उत्तर प्रदेश भू-राजस्व अधिनियम, 1901 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 3 सन् 1901) की धारा 48 के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल यह घोषणा करती हैं कि नीचे अनुसूची में उल्लिखित जिला मथुरा के तीन ग्रामों, जो सरकारी अधिसूचना संख्या 819/1-14/2001-52(32)/90-169, दिनांक 23 अप्रैल, 2001 द्वारा सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रियाओं के अधीन रखे गये थे, में उक्त संक्रियायें, इस अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से बन्द की जाती हैं।

### अनुसूची

क्र०सं०	जिला	तहसील	परगना	ग्राम
1	मथुरा	मांट	मांट	इरौली गूजर खादर
2	"	"	"	सुरीर कलां खादर
3	"	"	"	मखदूमपुर खादर

आज्ञा से,  
सुधीर गर्ग,  
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no. 578/1-14/2022, dated October 14, 2022 :

### NOTIFICATION

October 14, 2022

**No. 578(i)/1-14/2022**—In exercise of the powers under section 48 of the Uttar Pradesh Land Revenue Act, 1901 (U. P. Act, no. 3 of 1901) read with Sub-section (3) of section 43 of the Uttar Pradesh Revenue Code, 2006 (U. P. Act, no. 8 of 2012), the Governor is pleased to declare that Survey and Record operations in three Villages of District Mathura mentioned in the Schedule below, which were placed under the said operations *vide* Government Notification no. 819/1-14/2001-52(32)/90-169, dated April 23, 2001, are closed with effect from the date of publication of this notification in the Gazette.

### SCHEDULE

Sl. no.	District	Tehsil	Pargana	Village
1	Mathura	Mant	Mant	Irauli Goojar Khadar
2	Mathura	Mant	Mant	Sureer Kalan Khadar
3	Mathura	Mant	Mant	Makhdoompur Khadar

By order,  
SUDHIR GARG,  
Principal Secretary.

सं0 579/1-14/2022—उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता, 2006 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-8 सन् 2012) की धारा-43 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल यह घोषणा करती हैं कि अधिसूचना के गजट में प्रकाशित किये जाने के दिनांक से जिला मथुरा का ग्राम अर्थात् अहिल्यागंज खादर, परगना एवं तहसील सदर सर्वेक्षण एवं अभिलेख संक्रियाओं के अधीन रखा जायेगा।

आज्ञा से,  
सुधीर गर्ग,  
प्रमुख सचिव।

In pursuance of the provisions of clause (3) of Article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no. 579/1-14/2022, dated October 14, 2022 :

#### NOTIFICATION

October 14, 2022

**No. 579(i)/1-14/2022**—In exercise of the powers under Sub-section (1) of section 43 of the Uttar Pradesh Revenue Code, 2006 (Uttar Pradesh Act no. 8 of 2012), the Governor is pleased to declare that the Village namely Ahilyaganj Khadar Paragna and Tehsil-Sadar of District-Mathura shall be placed under Survey and Record operations with effect from the date of publication of this notification in the Gazette.

By order,  
SUDHIR GARG,  
Principal Secretary.

### सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग

अनुभाग-1

नियुक्ति

18 अक्टूबर, 2022 ई0

सं0 887/18-1-22-25(85)/2017—उ0 प्र0 उद्योग सेवा श्रेणी-2 के सहायक आयुक्त उद्योग के पद पर कार्यरत निम्न तालिका में अंकित अधिकारी को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से उपायुक्त उद्योग, के अस्थायी पद पर वेतन बैंड-3 रु0 15,600 से 39,100 ग्रेड वेतन रु0 6,600/ पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स लेवल-11, में पदोन्नत करते हुये 01 वर्ष की परिवीक्षा अवधि पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करती हैं :

क्रमांक	अधिकारी का नाम	ज्येष्ठता क्रमांक
1	श्री सुरेन्द्र कुमार	39

2—सम्बन्धित अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि वह अपने नवप्रोन्नत पद पर कार्यभार ग्रहण कर उसकी सूचना तत्काल शासन को उपलब्ध करायें। उक्त अधिकारी की तैनाती के आदेश पृथक् से निर्गत किये जायेंगे।

आज्ञा से,  
अमित मोहन प्रसाद,  
अपर मुख्य सचिव।

**संस्कृति विभाग**

अधिसूचना

03 अक्टूबर, 2022 ई०

सं० 2230/चार-2022—उत्तर प्रदेश प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों का परिरक्षण अधिनियम, 1956 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-7, सन् 1957) के अधीन उत्तर प्रदेश में प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों पर यथा प्रयोज्य एन्शियेंट मानूमेन्ट्स प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 (अधिनियम संख्या-7, सन् 1904) की धारा-3 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल महोदय नीचे अनुसूची में वर्णित प्राचीन स्मारकों/स्थानों का संरक्षित स्मारक घोषित करने की अधिसूचना जारी करने का प्रस्ताव करते हैं :

**अनुसूची**

क्र० सं०	राज्य	जिला	तहसील और ग्राम	स्मारक/ स्थान का नाम	संरक्षण के अधीन ली जाने वाली राजस्व गाटा संख्याएँ	क्षेत्रफल एकड़/ हेक्टेयर	सीमायें
1	2	3	4	5	6	7	8
1	उत्तर प्रदेश	गोरखपुर	ग्राम-डीहाघाट, चौरी-चौरा	कुषाण कालीन स्तूप	260	0.0850	उत्तर—गाटा सं० 261 एवं 262 पूर्व— गाटा सं० 255 दक्षिण— गाटा सं० 259 पश्चिम— गाटा सं० 264

**सूचना**

उपर्युक्त अधिसूचना जारी किये जाने के सम्बन्ध में आपत्तियां यदि कोई हों, प्रमुख सचिव, उ०प्र० सरकार, संस्कृति विभाग, बापू भवन, उ०प्र० सचिवालय, लखनऊ को सम्बोधित और लिखित रूप में भेजी जानी चाहिये। केवल उन्हीं आपत्तियों पर विचार किया जायेगा जो इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से एक माह के भीतर प्राप्त होंगी।

आज्ञा से,  
मुकेश कुमार मेश्राम,  
प्रमुख सचिव।

**Sanskrit Anubhag**

NOTIFICATION

October 03, 2022

The Governor is pleased to order the publication of the following English Translation of notification no. 2230/IV-2022, dated October 03, 2022 for general information.

No. 2230/IV-2022--In exercise of the powers under Sub-section (1) of section 3 of the Ancient Monuments Preservation Act, 1904 (Act no. VII of 1904), as re-enacted by section 3 of the U.P. Ancient and Historical Monuments and Archaeological sites and Remains Act, 1956 (U.P. Act no. VII of 1957), the Governor is pleased to declare the Ancient monuments described in the schedule below to be the protected monuments within the meaning the said Act no. VII of 1901.

**SCHEDULE**

Sl. no.	State	District	Tehsil and Village	Name of the Monuments / Sites	Revenue plots to be taken under protection	Area	Boundries
1	2	3	4	5	6	7	8
						<i>Hactares</i>	
1	Uttar Pradesh	Gorakhpur	Village-Dihaghat Tehsil-Chauri-Chaura	Kushan Kaleen Stupa	260	0.0850	North--Revenue Plot No. 261 and 262. East--Revenue Plot No. 255. South--Revenue Plot No. 259. West--Revenue Plot No. 264.

**INTIMATION**

Objection, if any, to the issue of this notification may be sent in writing and shall be addressed to the Principal Secretary, Uttar Pradesh Shashan, Sanskriti Anubhag, Lucknow, U.P. State Archaeology Department Kaiserbagh, Lucknow or District Magistrate, Gorakhpur with in one month from the date of the publication of this notification.

By order,  
MUKESH KUMAR MESHRAM,  
Principal Secretary.

03 अक्टूबर, 2022 ई०

सं० 2278/चार-2022—उत्तर प्रदेश प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों का परिरक्षण अधिनियम, 1956 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-7, सन् 1957) के अधीन उत्तर प्रदेश में प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों पर यथा प्रयोज्य एन्शियेंट मानूमेन्ट्स प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 (अधिनियम संख्या-7, सन् 1904) की धारा-3 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल महोदय नीचे अनुसूची में वर्णित प्राचीन स्मारकों/स्थानों का संरक्षित स्मारक घोषित करने की अधिसूचना जारी करने का प्रस्ताव करते हैं :

**अनुसूची**

क्र० सं०	राज्य	जिला	तहसील और ग्राम	स्मारक/स्थान का नाम	संरक्षण के अधीन ली जाने वाली राजस्व गाटा संख्यायें	क्षेत्रफल एकड़/हेक्टेयर	सीमायें
1	2	3	4	5	6	7	8
1	उत्तर प्रदेश	वाराणसी	ग्राम-भदैन	श्री जगन्नाथ मंदिर अस्सी	3302/3	0.696	पूर्व— गाटा सं० 3303 दक्षिण— गाटा सं० 3301 पश्चिम— रास्ता उत्तर—रास्ता अस्सी घाट।

## सूचना

उपर्युक्त अधिसूचना जारी किये जाने के सम्बन्ध में आपत्तियां यदि कोई हों, प्रमुख सचिव, उ०प्र० सरकार, संस्कृति विभाग, बापू भवन, उ०प्र० सचिवालय, लखनऊ को सम्बोधित और लिखित रूप में भेजी जानी चाहिये। केवल उन्हीं आपत्तियों पर विचार किया जायेगा जो इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से एक माह के भीतर प्राप्त होंगी।

आज्ञा से,  
मुकेश कुमार मेश्राम,  
प्रमुख सचिव।

## NOTIFICATION

October 03, 2022

The Governor is pleased to order the publication of the following English Translation of Notification no. 2278/IV-2022, dated October 03, 2022 for general information.

No. 2278/IV-2022--In exercise of the powers under Sub-section (1) of section 3 of the Ancient Monuments Preservation Act, 1904 (Act no. VII of 1904), as re-enacted by section 3 of the U.P. Ancient and Historical Monuments and Archaeological sites and Remains Act, 1956 (U.P. Act no. VII of 1957), the Governor is pleased to declare the Ancient monuments described in the schedule below to be the protected monuments within the meaning the said Act no. VII of 1901.

## SCHEDULE

Sl. no.	State	District	Tahsil and Village	Name of the Monuments / Site	Revenue plots to be taken under protection	Area	Boundries
1	2	3	4	5	6	7	8
						<i>Hactares</i>	
1	Uttar Pradesh	Varanasi	Village-Bhadeni	Sri Jagannath Mandir, Assi	3302/3	0.696	East--Gata No. 3303 South--Gata No. 3301 West--Road North--Road Assi Ghat.

## INTIMATION

Objection, if any, to the issue of this notification may be sent in writing and shall be addressed to the Principal Secretary, Uttar Pradesh Shashan, Sanskriti Anubhag, Lucknow, U.P. State Archaeology Department Kaiserbagh, Lucknow or District Magistrate, Gorakhpur with in one month from the date of the publication of this notification.

By order,  
MUKESH KUMAR MESHRAM,  
Principal Secretary.



03 अक्टूबर, 2022 ई0

सं0 2279/चार-2022—उत्तर प्रदेश प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों का परिरक्षण अधिनियम, 1956 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या-7, सन् 1957) के अधीन उत्तर प्रदेश में प्राचीन एवं ऐतिहासिक स्मारकों तथा पुरातत्वीय स्थानों और अवशेषों पर यथा प्रयोज्य एन्शियेंट मानूमेन्ट्स प्रिजर्वेशन एक्ट 1904 (अधिनियम संख्या-7, सन् 1904) की धारा-3 की उपधारा (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करके, राज्यपाल महोदय नीचे अनुसूची में वर्णित प्राचीन स्मारकों/स्थानों का संरक्षित स्मारक घोषित करने की अधिसूचना जारी करने का प्रस्ताव करते हैं :

**अनुसूची**

क्र० सं०	राज्य	जिला	तहसील और ग्राम	स्मारक/स्थान का नाम	संरक्षण के अधीन ली जाने वाली राजस्व गाटा संख्यायें	क्षेत्रफल एकड़/हेक्टेयर	सीमायें
1	2	3	4	5	6	7	8
1	उत्तर प्रदेश	सोनभद्र	ग्राम—बिछिया गौसा (विजयगढ़), तहसील—राबर्ट्सगंज	इष्टिका मंदिर	23 ग	2.4150	पूर्व—बजरंगी आदि का मकान दक्षिण—कामेश्वर एवं राम जतन का आदि का मकान पश्चिम—सड़क व गाटा सं० 26 उत्तर—गाटा सं० 21, 24 एवं 25 तथा सड़क।

**सूचना**

उपर्युक्त अधिसूचना जारी किये जाने के सम्बन्ध में आपत्तियां यदि कोई हों, तो प्रमुख सचिव, उ०प्र० सरकार, संस्कृति विभाग, बापू भवन, उ०प्र० सचिवालय, लखनऊ को सम्बोधित और लिखित रूप में भेजी जानी चाहिये। केवल उन्हीं आपत्तियों पर विचार किया जायेगा जो इस अधिसूचना के जारी होने के दिनांक से एक माह के भीतर प्राप्त होंगी।

आज्ञा से,  
मुकेश कुमार मेश्राम,  
प्रमुख सचिव।

**NOTIFICATION**

October 03, 2022

The Governor is pleased to order the publication of the following English Translation of notification no. 2279/IV-2022, dated October 03, 2022 for general information.

No. 2279/IV-2022--In exercise of the powers under Sub-section (1) of section 3 of the Ancient Monuments Preservation Act, 1904 (Act no. VII of 1904), as re-enacted by section 3 of the U.P. Ancient and Historical Monuments and Archaeological sites and Remains Act, 1956 (U.P. Act no. VII of 1957), the Governor is pleased to declare the Ancient monuments described in the schedule below to be the protected monuments within the meaning the said Act no. VII of 1901.

**SCHEDULE**

Sl. no.	State	District	Tehsil and Village	Name of the Monuments / Site	Revenue plots to be taken under protection	Area	Boundries
1	2	3	4	5	6	7	8
						<i>Hactares</i>	
1	Uttar Pradesh	Sonbhadra	Village-Bichiya gosa (Vijaygarh) Tehsil-Robertsganj	Istika Temple	33 Ga.	2.4150	East--House of Bajrangi and other. South--House of Kameshwar, Ramjatan and other. West--Road and Gata no. 26. North--Gata No. 21, 24, 25 and Road.

**INTIMATION**

Objection, if any, to the issue of this notification may be sent in writing and shall be addressed to the Principal Secretary, Uttar Pradesh Shashan, Sanskriti Anubhag, Lucknow, U.P. State Archaeology Department Kaiserbagh, Lucknow or District Magistrate, Gorakhpur with in one month from the date of the publication of this notification.

By order,  
MUKESH KUMAR MESHRAM,  
Principal Secretary.

**लोक निर्माण विभाग**

अनुभाग-8

तैनाती

30 जून, 2022 ई०

सं० 837/23-8-2022--तात्कालिक प्रभाव से लोक निर्माण विभाग के अधोलिखित तालिका के स्तम्भ-2 में अंकित अधिशासी अभियन्ता (सिविल) को स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती स्थान से स्थानान्तरित करते हुये स्तम्भ-4 में अंकित स्थान/खण्ड में एतद्द्वारा तैनात किया जाता है :

**तैनाती**

क्र० सं०	नाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	2	3	4
	सर्वश्री-		
1	राजेन्द्र कुमार त्रिपाठी	निर्माण खण्ड-2, लो०नि०वि०, आजमगढ़	निर्माण खण्ड-2, लो०नि०वि०, कानपुर नगर।
2	सतीश कुमार रावत	अधिशासी अभियन्ता (नियोजन-2), लखनऊ	निर्माण खण्ड-1, कानपुर देहात।
3	राजेन्द्र कुमार	नव पदोन्नत अधिशासी अभियन्ता सम्बद्ध प्रमुख अभियन्ता, लखनऊ	प्रान्तीय खण्ड, जौनपुर।

1	2	3	4
	सर्वश्री—		
4	राजीव कुमार राय (दिव्यांग)	सम्बद्ध कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ	निर्माण खण्ड-3, बाराबंकी।
5	जितेन्द्र पाल सिंह	निर्माण खण्ड-2, आगरा	निर्माण खण्ड-1, मुजफ्फरनगर।
6	शुभ नारायण	निर्माण खण्ड-1, लो०नि०वि०, बस्ती	राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, लखीमपुर खीरी।
7	सुनील दत्त	निर्माण खण्ड-2, फतेहपुर	प्रान्तीय खण्ड, मिर्जापुर।
8	विनोद कुमार राय	निर्माण खण्ड-3, उरई	राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, सुल्तानपुर।
9	अशोक कुमार वर्मा	निर्माण खण्ड-1, बहराईच	प्रान्तीय खण्ड, लखीमपुर खीरी।
10	संजीव कुमार वर्मा	प्रान्तीय खण्ड, रामपुर	निर्माण खण्ड-2 (प्र०प०), बहराईच।
11	अरविन्द कुमार	निर्माण खण्ड-1, लो०नि०वि०, चित्रकूट	निर्माण खण्ड-2, फतेहपुर।
12	विमल कुमार	निर्माण खण्ड-1, लो०नि०वि०, कन्नौज	प्रतिनियुक्ति पर उपशा।
13	अमर सिंह	प्रान्तीय खण्ड, बदायूं	प्रतिनियुक्ति पर उ०प्र० राजय सेतु निगम लि०।
14	अजय भास्कर	निर्माण खण्ड-1, लो०नि०वि०, मुजफ्फरनगर।	निर्माण खण्ड, मैनपुरी।
15	सतपाल सिंह	प्रान्तीय खण्ड, मुजफ्फरनगर	सम्बद्ध प्रमुख अभियन्ता कार्यालय, लखनऊ
16	दीपक कुमार चौधरी	निर्माण खण्ड-3 (प्र०प०), आजमगढ़	निर्माण खण्ड-1, बाराबंकी।
17	बृजेन्द्र कुमार चौधरी	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, फतेहगढ़	निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०, सहारनपुर।
18	देवेन्द्र मणि	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, गोण्डा	निर्माण खण्ड, महाराजगंज।
19	अनिल कुमार पुत्र श्री पी० लाल	निर्माण खण्ड-1, लो०नि०वि०, पीलीभीत	प्रान्तीय खण्ड, मुजफ्फरनगर।
20	हर दयाल अहिरवार	निर्माण खण्ड-1, हरदोई	प्रान्तीय खण्ड, उन्नाव।
21	अरुण कुमार सिंह	राष्ट्रीय मार्ग खण्ड-1, लो०नि०वि०, वाराणसी	प्रान्तीय खण्ड, बस्ती।
22	सुभाष चन्द्र	निर्माण खण्ड-1, रायबरेली	निर्माण खण्ड-1, बांदा।
23	गगन	राष्ट्रीय मार्ग खण्ड, मुरादाबाद	निर्माण खण्ड-1, पीलीभीत।
24	प्रवीण कुमार	प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०, गोरखपुर	भवन सेल, लखनऊ।

1	2	3	4
	सर्वश्री—		
25	सुनील सागर	प्रान्तीय खण्ड, बिजनौर	निर्माण खण्ड-2 (प्र0प0), आगरा।
26	अनिल कुमार जाटव	प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, औरैया	निर्माण खण्ड-1, लखीमपुर खीरी।
27	कमल किशोर	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, देवरिया	निर्माण खण्ड-3, वाराणसी।
28	अरविन्द कुमार	प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0, कर्वी (चित्रकूट)	निर्माण खण्ड-3, गोरखपुर।
29	संजीव कुमार सिंह	निर्माण खण्ड, लो0नि0वि0, बलिया	निर्माण खण्ड, देवरिया
30	देवपाल (अनु0 जाति)	सम्बद्ध कार्यालय प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ	निर्माण खण्ड-2, मिर्जापुर।

2—उक्त अधिशासी अभियन्तागण को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक शासन एवं प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ को उपलब्ध करायेंगे।

### कार्यालय-ज्ञाप

30 जून, 2022 ई0

सं0 838/23-8-2022—तात्कालिक प्रभाव से लोक निर्माण विभाग के अधोलिखित तालिका के स्तम्भ-2 में अंकित अधिशासी अभियन्ता (विद्युत/यांत्रिक) को जनहित में स्तम्भ-3 में अंकित वर्तमान तैनाती स्थान से स्थानान्तरित करते हुये स्तम्भ-4 में अंकित स्थान/खण्ड में एतद्वारा तैनात किया जाता है :

### तैनाती

क्र0 सं0	नाम	वर्तमान तैनाती	नवीन तैनाती
1	2	3	4
	सर्वश्री—		
1	मुराद अहसन	यांत्रिक खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सहारनपुर	अनुरक्षण खण्ड-2वी, लखनऊ (अति0 कार्यभार किंग जार्ज चिकित्सा विश्वविद्यालय, उ0प्र0)
2	संदीप कुमार सक्सेना	तकनीकी प्रकोष्ठ-15, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ	सम्बद्ध मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ (विशेषज्ञता के दृष्टिगत विभाग में चल रहे आई0टी0/ऐप कार्यों में योगदान करने एवं शासन स्तर भी डिजिटलाईजेशन कार्यों में सहायोग देने हेतु)
3	प्रदीप कुमार	स्टाफ आफीसर, 17वां वृत्त (वि/यां0), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ	टी0ए0सी0 सिंचाई विभाग में प्रतिनियुक्ति पर।
4	ओम प्रकाश	विद्युत खण्ड, लोक निर्माण विभाग, मेरठ	यांत्रिक खण्ड, लोक निर्माण विभाग, सहारनपुर।

2—उक्त अधिशासी अभियन्तागण को निर्देशित किया जाता है कि वे तत्काल नवीन तैनाती के स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर कार्यभार प्रमाणक शासन एवं प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष, लोक निर्माण विभाग, लखनऊ को उपलब्ध करायेंगे।

आज्ञा से,  
राजेश कुमार अग्रवाल,  
संयुक्त सचिव।



# सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 7 जनवरी, 2023 ई० (पौष 17, 1944 शक संवत्)

### भाग 1-क

नियम, कार्य विधियां, आज्ञायें, विज्ञप्तियां इत्यादि, जिनको उत्तर प्रदेश के राज्यपाल महोदय, विभिन्न विभागों के अध्यक्ष तथा राजस्व परिषद् ने जारी किया।

### HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

#### [ ACCOUNTS (C-3) SECTION ]

#### NOTIFICATION

*Dated: August 26, 2022*

**No. 22**—The following System Manager is hereby granted the benefits of Second Financial Upgradation Under A.C.P. Scheme *i.e.* immediate next higher Grade Pay to the Grade pay being paid before the date of admissibility of said Second Financial Upgradation *w.e.f.* the date mentioned against his name in terms of G.O. no. Ve.Aa.-2-773/X-62(M)/2008 dated 05 November, 2014.

Sl. No.	Emp. No.	Name S/Sri	Date of Grant of Second Financial Upgradation under A.C.P. Scheme
1	551	Apoorva Agha	01.01.2022

**No. 23**—The following Deputy Registrar-cum-Private Secretary Grade-III is hereby granted the benefits of Third Financial Upgradation Under A.C.P. Scheme *i.e.* immediate next higher Grade Pay to the Grade pay being paid before the date of admissibility of said Third Financial Upgradation *w.e.f.* the date mentioned against his name in terms of G.O. no. Ve.Aa.-2-773/X-62(M)/2008 dated 05 November, 2014.

Sl. No.	Emp. No.	Name S/Sri	Date of Grant of Third Financial Upgradation under A.C.P. Scheme
1	1518	Ramayan Prasad Shukla	03.04.2022

**No. 24**—The following Private Secretary Grade-I is hereby granted the benefits of Second Financial Upgradation Under A.C.P. Scheme *i.e.* immediate next higher Grade Pay to the Grade Pay being paid before the date of admissibility of said Second Financial Upgradation *w.e.f.* the date mentioned against his name in terms of G.O. no. Ve.Aa.-2-773/X-62(M)/2008 dated 05 November, 2014.

Sl. No.	Emp. No.	Name S/Sri	Date of Grant of Second Financial Upgradation under A.C.P. Scheme
1	3592	Ashish Prasad	04.03.2022 (A.N.)

**No. 25**—The following System Analyst is hereby granted the benefits of Second Financial Upgradation Under A.C.P. Scheme *i.e.* immediate next higher Grade Pay to the Grade Pay being paid before the date of admissibility of said Second Financial Upgradation *w.e.f.* the date mentioned against his name in terms of G.O. no. Ve.Aa.-2-773/X-62(M)/2008 dated 05 November, 2014.

Sl. No.	Emp. No.	Name S/Sri	Date of Grant of Second Financial Upgradation under A.C.P. Scheme
1	2008	Rajiv Gupta	01.01.2022

By order of the Court,  
**Ashish Garg,**  
Registrar General.

## HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD

### [ ADMINISTRATIVE 'G' SECTION ]

#### NOTIFICATION

*Dated: December 08, 2022*

#### Allahabad High Court (Right to Information) Rules, 2006.

**No. 935/2022/Admin.'G', Allahabad**—In partial modification of the earlier Court's Notification No. 63/2008/Admin. 'G' Dated : Allahabad 23<sup>rd</sup> May, 2008, in exercise of powers conferred by Section 5 & 19 of Right to Information Act, 2005 (22 of 2005), the Chief Justice, High Court of Judicature At Allahabad hereby designates the following Officers as Appellate Authority, Central Public Information Officer and Central Assistant Public Information Officer Under Section 5 and 19 of Right to Information Act, 2005, with immediate effect.

#### NOTIFICATION

#### (Right to Information) Rules, 2006

#### A. Allahabad High Court—

1	Appellate Authority	Registrar General
2	Central Public Information Officer	Registrar (Establishment)
3	Central Assistant Public Information Officer	(i) Assistant Registrar (Protocol & Nazarat). (ii) Assistant Registrar (Vigilance).

**B. Lucknow Bench of High Court—**

1	Appellate Authority	Registrar
2	Central Public Information Officer	Deputy Registrar (Establishment & Administration)
3	Central Assistant Public Information Officer	Assistant Registrar (Establishment & Administration).

**C. Subordinate Courts—****C-1. District Courts :**

1	Appellate Authority	District Judge of concerned Judgeship
2	Central Public Information Officer	Senior Most Additional District & Sessions Judge of concerned Judgeship.
3	Central Assistant Public Information Officer	Civil Judge (Senior Division) of concerned Judgeship.

**C-2. Family Courts :**

i. For the Family Court, where **two or more** Additional Principal Judges are posted :—

1	Appellate Authority	Principal Judge, Family Court
2	Central Public Information Officer	Senior Most Additional Principal Judge
3	Central Assistant Public Information Officer	Senior Most Ministerial Staff posted in Family Court.

ii. For the Family Courts, where **only one** Additional Principal Judge is posted :—

1	Appellate Authority	Principal Judge, Family Court
2	Central Public Information Officer	Additional Principal Judge
3	Central Assistant Public Information Officer	Senior Most Ministerial Staff posted in Family Court.

iii. For the Family Courts, where **only** Principal Judge is posted :—

1	Appellate Authority	Registrar General
2	Central Public Information Officer	Principal Judge, Family Court
3	Central Assistant Public Information Officer	Senior Most Ministerial Staff posted in Family Court.

**HIGH COURT OF JUDICATURE AT ALLAHABAD****[ CONFIDENTIAL 'B' SECTION ]****NOTIFICATION****CONFIRMATION***Dated: December 12, 2022*

**No. C-871/CF(B)/2022**—The following Judicial Officers are hereby confirmed in the Uttar Pradesh Nyayik Sewa :—

Sl. No.	Name of Officers (S/Sri/Smt./Km.)
1.	Navneet Kumar Bharti
2.	Anshu Shukla
3.	Anshu Mali Pandey
4.	Ruchi Srivastava
5.	Tahreem Khan
6.	Apeksha Singh
7.	Yogesh Kumar Yadav
8.	Ashutosh Tiwari
9.	Shabina Khan
10.	Anand Kumar Upadhyay
11.	Aashish Pandey
12.	Rajiv Mukul Pandey
13.	Arti Dwivedi
14.	Amir Suhail
15.	Renu Yadav
16.	Sachin Kumar Dixit
17.	Saumya Giri
18.	Nidhi Yadav-I
19.	Nishchal Shukla
20.	Anand Mishra
21.	Abhinav Jain
22.	Pradipti Singh
23.	Garima Singh-II
24.	Peeyush Tripathi



Sl. No.	Name of Officers (S/Sri/Smt./Km.)
25.	Abhinav Tiwari
26.	Preetimala Chaturvedi
27.	Ambareesh Tripathi
28.	Indresh
29.	Diksha Shree
30.	Satyabir Singh
31.	Amit Kumar- I
32.	Anupam Kumar Tripathi
33.	Harkiran Kaur
34.	Satish Kumar Magan
35.	Divya Chaudhary
36.	Anisha
37.	Priya Saxena
38.	Anshuman Dhunna
39.	Shivani Tyagi
40.	Nitivan Nigam
41.	Abhishek Tripathi-I
42.	Anupam Dixit
43.	Pragati Singh- I
44.	Abhishek Kumar Vyas
45.	Shweta Srivastava-II
46.	Anita-II
47.	Sucheta Chaurasia
48.	Pradeep Kumar Kushwaha
49.	Ambrish Kumar Srivastava
50.	Ila Chaudhary
51.	Deepak Nath Saraswati
52.	Parag Yadav
53.	Amod Kanth
54.	Shobit Bansal

Sl. No.	Name of Officers (S/Sri/Smt./Km.)
55.	Arif Nisamuddin Khan
56.	Diwakar Kumar
57.	Niraj Kumar Tripathi
58.	Abhishek Khare
59.	Prabhash Tripathi
60.	Shikha Yadav
61.	Nancy Dhunna
62.	Prag Dutt Shukla
63.	Manas Vatsa
64.	Chandan Kumar Singh
65.	Ujjwal Upadhyay
66.	Amit Kumar-II
67.	Gargi Sharma
68.	Tapasya Tripathi
69.	Siddiqui Saima Jarrar Alam
70.	Asma Sultana
71.	Virek Aggarwal
72.	Ishrat Parveen Faruqui
73.	Rashmi Chand
74.	Shraddha Deva
75.	Pragya Singh-III
76.	Kshitish Pandey
77.	Mahendra Kumar Pandey
78.	Anoop Kumar Pandey
79.	Mukta Tyagi
80.	Anupam Dubey
81.	Anuj Kumar Thakur
82.	Archana Tiwari-II
83.	Mohd. Zulqarnain Alam
84.	Kumud Upadhyay

Sl. No.	Name of Officers (S/Sri/Smt./Km.)
85.	Kamayani Dubey
86.	Suvrat Pathak
87.	Shantanu Tyagi
88.	Urooj Fatima
89.	Vidushi Meha
90.	Ranjini Shukla
91.	Prashant Mishra-II
92.	Akash Verma
93.	Vikash Kumar Singh
94.	Anuradha Shukla
95.	Sushama
96.	Shailesh Kumar Maurya
97.	Nitika Rajan
98.	Krishn Pratap Singh
99.	Mayank Prakash
100.	Arpita Yadav
101.	Shwetsa Chandra
102.	Avinash Chandra Gautam
103.	Roma Gupta
104.	Sneha
105.	Shital Priyadarshi
106.	Kurnika Awadh
107.	Anupam Singh
108.	Ranjana Saroj
109.	Anubhav Katiyar
110.	Ram Gopal Yadav
111.	Deependra Kumar Gupta
112.	AlokYadav
113.	Smriti Chaurasia
114.	Neelam Saroj

Sl. No.	Name of Officers (S/Sri/Smt./Km.)
115.	Vineeta Singh-II
116.	Devendra Pratap Singh
117.	Mona Singh
118.	Narendra Kumar
119.	Chhavi Kumari
120.	Dr. Vivek Kumar-II
121.	Sumit Kumar- I
122.	Vineet Kumar Yadav
123.	Partibha
124.	Suryabhan Kumar Verma
125.	Nitisha Singh
126.	Virendra Kumar-IV
127.	Mohd. Sajid-I
128.	Amit Kumar-III
129.	Smita Goswami
130.	Danvir Singh
131.	Gajendra Singh
132.	Anjali Rani
133.	Satyendra Kumar Chaudhary
134.	Pallavi Singh
135.	Ankita Dhama
136.	Nyaydhish Pankaj
137.	Gyanendra Kumar-I
138.	Shahnaz Ansari
139.	Sadhana Giri
140.	Praveen Kumar
141.	Balram Das
142.	Ranjeet Kumar Verma
143.	Priyanka Rani
144.	Arun Kumar- I

Sl. No.	Name of Officers (S/Sri/Smt./Km.)
145.	Prafful Kumar Chaudhary
146.	Sarvesh Singh Yadav
147.	Swatantra Singh Rawat
148.	Anita Singh
149.	Abhishek Jaiswal
150.	Sumit Chaudhary
151.	Naseha Waseem
152.	Vipin Yadav
153.	Akshaydeep Yadav
154.	Leelu
155.	Kanhaiya Ji
156.	Alok Verma
157.	Priti Bhushan
158.	Arjun
159.	Anchal Kasana
160.	Brahmpal Singh
161.	Sunil Kumar Nagar
162.	Sandeep Singh-I
163.	Mohd. Sajid-II
164.	Vikas Chaudhary
165.	Sandeep Paarcha
166.	Mritunjay Kumar
167.	Vijay Bhan
168.	Swati Chandra
169.	Balwant Kumar Bharati
170.	Saurav Singh
171.	Mahendra Singh Paswan
172.	Avadhesh Kumar-III
173.	Sawan Kumar Vikas
174.	Arun Kranti Yashodas

Sl. No.	Name of Officers (S/Sri/Smt./Km.)
175.	Priyanka
176.	Naveen Kumar
177.	Arpit Singh
178.	Rameshwar Dayal
179.	Shruti Verma
180.	Ravi Kumar Sagar
181.	Preeti Moga
182.	Gyanendra Kumar-II
183.	Vimlesh Saroj
184.	Ajay Kumar-IV
185.	Anuj Kumar Jauher
186.	Shailendra Nath
187.	Atul Kumar Nayak
188.	Neeraj Gond
189.	Surekha
190.	Chetna Tyagi

By order of the Court,  
Ashish Garg,  
*Registrar General.*



# सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 7 जनवरी, 2023 ई० (पौष 17, 1944 शक संवत्)

### भाग 3

स्वायत्त शासन विभाग का क्रोड़-पत्र, खण्ड-क-नगरपालिका परिषद्, खण्ड-ख-नगर पंचायत,  
खण्ड-ग-निर्वाचन (स्थानीय निकाय) तथा खण्ड-घ-जिला पंचायत।

### खण्ड-घ-जिला पंचायत

कार्यालय आयुक्त, लखनऊ मण्डल, लखनऊ

20 दिसम्बर, 2022 ई०

सं० 3315/21ए-06/2021-22-उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 जो उ०प्र० पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 द्वारा संशोधित है, की धारा 239 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, लखनऊ द्वारा जनपद लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्रान्तर्गत बनने वाले सभी प्रकार के भवनों के निर्माण कार्य को नियंत्रित एवं विनियमित करने के संबंध में प्रचलित उपविधि में संशोधन सम्बन्धी उपविधि बनायी गयी है। मेरे द्वारा उपविधि की पुष्टि कर दी गयी है एवं उक्त अधिनियम की धारा 242(2) के अन्तर्गत प्रकाशित की जाती है। यह उपविधि गजट में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होगी।

### उपविधि भाग-1

1-अधिनियम का तात्पर्य उ०प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित) से है।

2-"ग्राम्य क्षेत्र" का तात्पर्य जिले में स्थित प्रत्येक नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, छावनी तथा नगर निगम क्षेत्र के अतिरिक्त उस क्षेत्र को हटाते हुए जो कि किसी विकास प्राधिकरण या यू०पी०एस०आई०डी०सी०, लीडा (LIDA), अधिसूचित क्षेत्र, (notified area) या उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद् द्वारा अधिग्रहित किया गया हो एवं जिसके अधिग्रहण की सूचना पूर्ण विवरण सहित यथा ग्राम का नाम, गाटा/खसरा संख्या, अधिग्रहीत क्षेत्रफल आदि गजट में प्रकाशित की जा चुकी हो।

3-विनियमन का मतलब भवन के मूल निर्माण एवं बने हुए भवन में अतिरिक्त निर्माण एवं फेर-बदल की कार्यवाही को विनियमित करने से है।

4-मानचित्र से तात्पर्य भवन के ड्राइंग, डिजाइन एवं विशिष्टियों के अनुसार कागज/इलेक्ट्रानिक्स डिवाइस पर बने उस नक्शे से है, जो कि पंजीकृत वास्तुविद् के द्वारा बनाकर प्रस्तुत किया गया हो एवं डिजाइन योग्य (Eligible) अभियन्ता द्वारा तैयार किया गया हो।

5-निर्माण कार्य का तात्पर्य किसी भवन में निर्माण करना, पुनः निर्माण करना या उसमें सारवान विचलन करना या उसको ध्वस्त करने से है।

6-भवन की ऊंचाई का तात्पर्य संलग्न किसी नाली के टाप से लेकर उस भवन के सबसे ऊंचे बिन्दु तक नापी गयी लम्बवत् (Vertical) ऊंचाई से एवं ढलान वाली छत के लिए दो गहराईयों के बीच से है। भवन की ऊंचाई में मन्टी, मशीनरूम, पानी की टंकी, एन्टीना आदि की ऊंचाई सम्मिलित नहीं होगी।

7-छज्जा का तात्पर्य ऐसे ढलाननुमा या भूमि के क्षितिज के अनुसार बाहर निकले हुए भाग से है, जो कि सामान्यतया सूरज या बारिश से बचाव के लिए बनाया जाता है।

8-ड्रेनेज का तात्पर्य उस व्यवस्था से है, जिसका निर्माण किसी तरल पदार्थ जैसे रसोई, स्नानगृह, से विसर्जित पानी आदि को हटाने के लिए किया जाता है, इसके अन्तर्गत नाली व पाइप भी सम्मिलित हैं।

9-निर्मित भवन का तात्पर्य ऐसे भवन से है, जोकि परिभाषित ग्रामीण क्षेत्र में इन उपविधियों के लागू होने से पहले अस्तित्व में आ चुका है अथवा जिला पंचायत की स्वीकृति के बिना निर्मित किया गया हो।

10-तल (Floor Level) का तात्पर्य किसी मंजिल के उस निचले खण्ड से है, जहां पर सामान्यतः किसी भवन में चला फिरा जाता हो।

11-फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) का तात्पर्य उस भागफल से है, जो सभी तलों के आच्छादित कुल क्षेत्रफल को भू-खण्ड के क्षेत्रफल से भाग देने से प्राप्त होता है।

12-भू-आच्छादन (Ground Coverage) का तात्पर्य भू-तल पर बने सभी निर्माण द्वारा घेरे गये क्षेत्रफल से है।

13-ग्रुप हाउसिंग का तात्पर्य उस परिसर से है, जिसके अन्दर आवासीय फ्लैट अथवा स्वतंत्र आवासीय (Independent Apartment Unit) इकाई बनी हों तथा मूल सुविधाओं जैसे पार्किंग, पार्क, बाजार, जनसुविधायें आदि का प्रावधान हो।

14-ले-आउट प्लान का तात्पर्य उस नक्शे से है, जोकि किसी स्थल के समस्त भू-खण्ड, भवन खण्ड, मार्ग, खुली जगह, आने-जाने के बिन्दु, पार्किंग व्यवस्था, भू-निर्माण (Landscaping) अथवा विभिन्न आकार की प्लाटिंग की समस्त जानकारी व अन्य विवरण को इंगित करने वाले प्लान से है।

15-प्राविधिक (Technical) व्यक्ति का तात्पर्य निम्नलिखित से है-

(अ) अभियन्ता-अभियन्ता, जिला पंचायत, लखनऊ से है।

(ब) अवर अभियन्ता-इस उपविधि में अवर अभियन्ता का तात्पर्य उस अवर अभियन्ता से है जिसको अभियन्ता, जिला पंचायत द्वारा भवन के नक्शों की स्वीकृति की कार्यवाही के लिए निदेशित (Designated) किया गया हो।

16-कार्य अधिकारी का तात्पर्य कार्य अधिकारी, जिला पंचायत, लखनऊ से है।

17-अधिभोग (Occupancy) का तात्पर्य उस प्रयोजन से है, जिसके लिए भवन या उसका भाग प्रयोग में लाया जाना है, जिसके अन्तर्गत सहायक अधिभोग भी सम्मिलित है।

18-स्वामी का तात्पर्य व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह, कम्पनी, ट्रस्ट, पंजीकृत संस्था, राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के विभाग एवं अन्य प्राधिकरण जिसके/जिनके नाम में भूमि का स्वामित्व सम्बन्धित अभिलेखों में दर्ज है।

19-रेन वाटर हार्वेस्टिंग का तात्पर्य बरसात के पानी को उपयोग करके विभिन्न तकनीकों से भू-गर्भ जल के स्तर को ऊंचा उठाने से है।

20-सेटबैक का तात्पर्य किसी भवन के चारों तरफ यथास्थिति या मानक के अनुसार एवं बाउन्ड्री दीवार के बीच छोड़ी गयी खाली जगह अथवा रास्ते से है।



21—अपर मुख्य अधिकारी का तात्पर्य अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, लखनऊ से है।

22—जिला पंचायत का तात्पर्य अधिनियम की धारा-17 (1) में संघटित जिला पंचायत, लखनऊ से है।

23—अध्यक्ष का तात्पर्य अध्यक्ष, जिला पंचायत, लखनऊ से है।

24—बहु-मंजिली भवन (Multy Storey) भू-तल सहित चार मंजिल से अधिक अथवा 15 मीटर से अधिक ऊंचाई का भवन बहु-मंजिल कहलायेगा।

25—मंजिल का तात्पर्य भवन के उस भाग से है, जो किसी तल की सतह और इसके उपर के अनुवर्ती तल के बीच हो और यदि इसके ऊपर कोई तल न हों, तो वह स्थान जो तल और इसके ऊपर की छत के मध्य हो।

26—भवन का तात्पर्य ऐसी स्थायी प्रकृति के निर्माण अथवा संरचना से है, जो कि किसी भी प्रकार की सामग्री से निर्माण किया जाये, एवं उसका प्रत्येक भाग चाहे मानव प्रयोग या अन्यथा किसी प्रयोग में लाया जा रहा हो एवं उसके अन्तर्गत बुनियाद, कुर्सी क्षेत्र, दीवार, फर्श, छत, चिमनी, पानी की व्यवस्था, स्थायी प्लैटफार्म, बरान्डा, बालकनी, कार्नास या छज्जा या भवन का अन्य भाग जो किसी खुले भू-भाग को ढकने के उद्देश्य से बनाया जायेगा। इसके अन्तर्गत टैन्ट, शामियाना, तिरपाल आदि जोकि पूर्णतः अस्थायी रूप से किसी समारोह के लिये लगाये जाते हैं, वह भवन की परिभाषा में सम्मिलित नहीं होंगे।

27—आवासीय भवन के अन्तर्गत वे भवन सम्मिलित होंगे जिनमें सामान्यतः आवासीय प्रयोजन के प्राविधान सहित शयन सुविधा के साथ खाना बनाने तथा शौचालय की सुविधा हो। इसमें एक अथवा एक से अधिक आवासीय इकाई शामिल है।

28—व्यवसायिक/वाणिज्यिक भवन के अन्तर्गत वे भवन या भवन का वह भाग जो दुकानों, भण्डारण, बाजार, व्यवसायिक वस्तुओं के प्रदर्शन, थोक या फुटकर बिक्री, व्यवसाय से सम्बन्धित कार्य-कलाप, होटल, पेट्रोल पम्प, कन्वीनिएन्स स्टोर्स एवं सुविधाएं जो माल व्यवसायिक माल की बिक्री से अनुशांगिक हों और उसी भवन में स्थित हों सम्मिलित होंगे अथवा ऐसे भवन/स्थल जिनका प्रयोग धनोपार्जन हेतु किया जाना हो।

29—संकटमय भवन के अन्तर्गत भवन या भवन के वह भाग सम्मिलित होंगे जिनमें अत्यधिक ज्वलनशील या विस्फोटक सामग्री या उत्पाद का संग्रहण, वितरण, उत्पादन या प्रक्रम (प्रोसेसिंग) का कार्य होता हो या जो अत्यधिक ज्वलनशील हो या जो ज्वलनशील भाप या विस्फोटक पैदा करता हो या जो अत्यधिक कारोसिव, जहरीली या खतरनाक क्षार, तेजाब हो या अन्य द्रव्य पदार्थ, रासायनिक पदार्थ जिनमें ज्वाला, भाप पैदा होती हो, विस्फोटक जहरीले इरीटेन्ट या कॉरोसिव गैसों पैदा होती हो या जिनमें धूल के विस्फोटक मिश्रण पैदा करने वाली सामग्री या जिनके परिणामस्वरूप ठोस पदार्थ छोटे-2 कणों में विभाजित हो जाता हो और जिनमें तत्काल ज्वलन प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती हो, के संग्रहण, वितरण या प्रक्रम (प्रोसेसिंग) के लिए प्रयुक्त किया जाता हो।

30—भवन गतिविधि/भवन निर्माण का तात्पर्य किसी भवन के बनाने या पुनः बनाने या उसमें सारवान विचलन या ध्वस्त करने की कार्यवाही मानी जायेगी।

31—पार्किंग स्थल का तात्पर्य ऐसे चारदीवारी में बंद या खुले स्थान से है, जहां पर वाहन इकट्ठे रूप में खड़े हो सकते हैं, परन्तु इसके लिए आवश्यक है, कि उक्त स्थान पर आने-जाने के लिए एक सुगम एवं स्वतंत्र जोड़ने वाला मार्ग बना हो।

इन उपविधियों में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, परन्तु वे उक्त परिभाषाओं में सम्मिलित नहीं हैं, का तात्पर्य वही होगा, जो कि ऐसे शब्दों का National building Code एवं Bureau of Indian standards यथा संशोधित में माना जाता है। किसी विरोधाभास की स्थिति में अधिनियम के प्रावधान प्रभावी माने जायेंगे।

## उपविधि भाग-2

ये उपविधियां जिला पंचायत, लखनऊ के उक्त परिभाषित ग्रामीण क्षेत्र में जो कि इन उपविधियों के लिए परिभाषित किया गया है, में किसी भी व्यक्ति, ठेकेदार कम्पनी, फर्म या संस्था, सहकारी समिति, सोसाईटी, राजकीय विभाग द्वारा निर्माण कराये जाने वाले आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक भवन, शिक्षण संस्थान, फार्महाउस, ग्रुप हाऊसिंग, दुकानों, मार्केट, धर्मार्थ अथवा जनहितार्थ भवन इत्यादि का ले-आउट प्लान एवं/या भवन प्लान एवं निर्मित भवनों में परिवर्तन, परिवर्धन, विस्तार एवं भू-खण्डों के विकास आदि को नियन्त्रित एवं विनियमित करने की उपविधियां कहलायेंगी।

**(क) नक्शा स्वीकृत न कराने की परिस्थितियां**

ऐसे प्रकरण/निर्माण कार्य जिनमें उपविधियों के अन्तर्गत नक्शा स्वीकार कराना आवश्यक नहीं होगा—

1—उक्त परिभाषित “ग्राम्य क्षेत्र” में निम्नलिखित परिस्थितियों में भवन निर्माण, परिवर्तन, विस्तार की स्वीकृति हेतु प्रार्थना-पत्र की आवश्यकता नहीं होगी—

अ—ये उपविधियों कच्चे मकानों एवं गांव के मूल निवासी के शुद्धतया निजी आवास/कृषि कार्य हेतु बनाये जाने वाले 300 वर्ग मीटर क्षेत्रफल एवं दो मंजिल तक ऊँचे आवासीय भवनों पर लागू नहीं होंगी, परन्तु सुरक्षित डिजाइन व निर्माण की जिम्मेदारी मालिक की होगी एवं उक्त निर्माण/कार्यवाही करने से पूर्व जिला पंचायत को एक लिखित सूचना देनी होगी।

ब—सफेदी व रंग-रोगन के लिए।

स—प्लास्टर व फर्श मरम्मत के लिए।

य—पूर्व स्थान पर छत पुनःनिर्माण के लिए।

र—प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त भवन के हिस्से का पुनःनिर्माण।

व—मिट्टी खोदने या मिट्टी से गड़डा भरना।

**(ख) प्रार्थना पत्र, भू-अभिलेख व नक्शे**

उक्त ग्राम्य क्षेत्र में कोई नया निर्माण, पुराने भवन में परिवर्तन या परिवर्धन, विस्तार या भू-खण्ड के ले आउट की स्वीकृति का आशय रखने वाला स्वामी, इन उपविधियों के अनुसार, ऐसा करने से एक माह पहले अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत को एक आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख तथा सूचनाएं प्रस्तुत करेगा एवं पावती प्राप्त करेगा।

1—स्थल का नक्शा निम्नवत दिया जायेगा:—

ले—आउट प्लान का पैमाना 1 : 500 होगा।

की—प्लान का पैमाना 1 : 1000 होगा।

बिल्डिंग प्लान का पैमाना 1 : 100 होगा।

स्थल के चारों तरफ की सीमायें उनके नाम तथा समीपवर्ती भूमि का संक्षिप्त विवरण तथा भूमि मालिक का नाम एवं पूर्ण पता। समीपवर्ती मार्ग अथवा मार्गों का विवरण तथा निर्माणाधीन भवन से मार्ग की दूरी। स्थल के नक्शे के साथ भूमि के स्वामित्व का प्रमाण-पत्र जैसे विक्रय आलेख, दाखिल-खारिज, खतौनी (तीन माह से अधिक की न हो), पंजीकृत वसीयत, पंजीकृत दान विलेख (गिफ्ट डीड)।

2—प्रस्तावित भवन/परियोजना का नक्शा उपरोक्त वर्णित पैमाने के अनुसार होगा।

अ—प्रत्येक मंजिल के ढके हुए भाग का नक्शा, पूर्ण विवरण सहित।

ब—नक्शे पर पंजीकृत वास्तुविद् का पंजीकरण नंबर, नाम व पता पंजीय प्रमाण-पत्र की छायाप्रति सहित हस्ताक्षर युक्त।

स—नक्शे पर भू-स्वामी अथवा स्वामियों के नाम व पता सहित हस्ताक्षर।

य—भू-स्वामी अथवा स्वामियों द्वारा नक्शा स्वीकृति के लिये प्रार्थना-पत्र।

र—भवन/परियोजना के बनाने व उपयोग का उद्देश्य जैसे आवासीय, व्यवसायिक, शिक्षण, धर्मार्थ अथवा जनहितार्थ भवन।

ल—स्थल का की-प्लान, ले-आउट प्लान, फ्लोर प्लान, एलिवेशन, भवन की ऊँचाई, सैक्शन, स्ट्रक्चर विवरण, रेन वाटर हार्वेस्टिंग प्रणाली, बेसमेंट, लैंडस्केप प्लान, वातानुकूलित प्लांट, सीवेज-जल निस्तारण व्यवस्था, अग्नि निकास, जीने की स्थिति व अन्य विवरण।

व-नक्शे पर परियोजना का नाम, शीर्षक, भू-खण्ड का खसरा, ग्राम, तहसील सहित पूरा पता।

स-नक्शे पर भू-खण्ड का क्षेत्रफल, ग्राउंड कवरेज, हर तल का क्षेत्रफल, बेसमेंट का क्षेत्रफल आदि का विवरण।

3-बहु-मंजिली भवन (Multy Storey) भू-तल सहित चार मंजिल से अधिक अथवा 15 मीटर से अधिक ऊंचाई के भवन में नक्शे पर निम्नलिखित अतिरिक्त सूचना भी देनी होगी—

अग्नि शमन प्रणाली की व्यवस्था, आपात सीढ़ी व निकास, अग्नि सुरक्षा लिफ्ट, अग्नि अलार्म आदि का विवरण व ठिकाने (Location)। निर्माण कार्य एवं निर्माण में उपयोग की जाने वाली सामग्री की विशिष्टियाँ आदि।

### (ग) नक्शा स्वीकृति प्रदान न करने की परिस्थितियाँ

1-निम्नलिखित परिस्थितियों में भवन निर्माण, परिवर्तन, विस्तार की किसी भू-खण्ड पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी, यदि—

अ-प्रस्तावित भवन-उपयोग अनुमन्य भू-उपयोग से भिन्न है।

ब-प्रस्तावित निर्माण धार्मिक प्रकृति का है और उससे किसी समाज की धार्मिक भावनाएं आहत होती हों।

स-प्रस्तावित निर्माण का उपयोग लोगों की भावनाएं भड़काने का स्रोत (Source of Annoyance) अथवा आसपास रहने वालों के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव डालता हो।

### (घ) तकनीकी अनुदेश (Technical Instructions)

1-नक्शा/प्लान में निम्न अनुदेशों का पालन किया जायेगा—

क-एक आवास गृह में 4.50 व्यक्ति प्रति गृह माना (Consider) गया है।

ख-भवन के भू-तल पर स्टिल्ट पार्किंग (Stilt Parking) अधिकतम 2.40 मीटर ऊंचाई तक अनुमन्य होगी।

ग-लिंगल (Lintel) अथवा छत स्तर पर छज्जा अधिकतम क्रमशः 0.45 मीटर एवं 0.75 मीटर चौड़ा होगा।

घ-बेसमेंट का निर्माण भवन की सीमा से बाहर नहीं किया जाएगा। बेसमेंट की फर्श से सीलिंग तक की अधिकतम ऊंचाई 4.50 मीटर होगी तथा बाहर की नाली से बेसमेंट की अधिकतम ऊंचाई 1.50 मीटर होगी। स्ट्रक्चर स्थिरता के आधार पर बेसमेंट सन्निकट (Adjacent) प्लॉट से 2.0 मीटर दूरी तक निर्मित किया जा सकता है।

ङ-बहु मंजिली भवन में कम से कम एक सामान (Goods)/मालवाहक लिफ्ट का प्रावधान करना होगा।

च-राष्ट्रीय भवन संहिता (National Building Code) 2005 के प्रावधान के अनुसार गुप हाउसिंग के दो ब्लॉक में न्यूनतम 6.0 मीटर से 16 मीटर की दूरी होगी। भवन की 18 मीटर ऊंचाई तक 6.0 मीटर इसके पश्चात् प्रत्येक 3.0 मीटर अतिरिक्त ऊंचाई के लिए ब्लॉक की दूरी 1.0 मीटर बढ़ाई जायेगी। भू-खण्ड के डैड एन्ड (Dead End) पर ब्लॉक की अधिकतम दूरी 9.0 मीटर होगी।

छ-बहु मंजिली भवन में चार तलों के बाद एक सेवा तल अनुमन्य होगा। किसी भवन में अधिकतम तीन सेवा तल का प्रावधान किया जा सकता है। सेवा तल की अधिकतम ऊंचाई 2.40 मीटर होगी।

ज-भूमि की प्लॉटिंग में प्लॉटों के बीच कम से कम 9 मी0 चौड़ा रोड व मेन रोड 12 मी0 होगी तथा कोई भी परियोजना पहुच मार्ग एवं सम्पर्क मार्ग से जुड़ी होगी।

2-निम्नलिखित निर्माण/सुविधाओं के लिये भू-खण्ड का 10% क्षेत्रफल, भू-आच्छादन (Ground Coverage) में अतिरिक्त जोड़ा जा सकता है—

क-जेनरेटर कक्ष, सुरक्षा मंचान, सुरक्षा केबिन, गार्ड रूम, टॉयलेट ब्लॉक, ड्राईवर रूम, विद्युत् उप-केन्द्र आदि।

ख-मम्टी, मशीन रूम, पम्प हाउस, जल-मल प्लांट।

ग-ढके हुए पैदल पथ आदि।

3-क-आवासीय भवन में कमरे का आकार 2.40 मीटर एवं 9.50 वर्ग मीटर से कम न होना चाहिये।

ख-छत की सीलिंग की ऊँचाई 2.75 मीटर से कम न होनी चाहिये।

ग-ए0सी0 कमरे की ऊँचाई 2.40 मीटर से कम न होनी चाहिये।

घ-रसोई घर की ऊँचाई 2.75 मीटर, आकार 1.80 मीटर एवं 5.0 वर्ग मीटर से कम न होना चाहिये।

ङ-संयुक्त संडास (Toilet) का आकार 1.20 मीटर एवं 2.20 वर्गमीटर से कम न होना चाहिये।

च-खिड़की व रोशदान का क्षेत्रफल फर्श के क्षेत्रफल का 10% से कम न होना चाहिये।

छ-तीन मंजिल तक के भवन में सीढ़ी की चौड़ाई 1.0 मीटर एवं इससे अधिक ऊँचे भवन में 1.50 मीटर से कम न होनी चाहिये।

4-क-पार्क, टोट-लोट्स (Tot-Lots), लैंड स्केप (Landscape) आदि का क्षेत्रफल भू-खण्ड के क्षेत्रफल का 15% होगा।

ख-30 मीटर तक के मार्ग पर स्थित समस्त प्रकार के भवनों की अधिकतम ऊँचाई सड़क की विद्यमान चौड़ाई तथा अनुमन्य फ्रंट सेट-बैक के योग का डेढ़ गुना होगी।

ग-भू-कम्प रोधी व सुरक्षित डिजाईन की जिम्मेदारी वास्तुविद एवं उसके अन्तर्गत कार्यरत डिजाईनर की होगी तथा उसका सत्यापन एम0टेक0 स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा करा कार्यालय में उपलब्ध कराना होगा।

5-स्वीकृत किये गये भवन में जल आपूर्ति एवं मल-मूत्र एवं बेकार पानी के निस्तारण (Disposal) की व्यवस्था स्वामी द्वारा स्वयं की जायेगी जिला पंचायत का इसके लिए कोई उत्तरदायित्व व्यय अधिभार नहीं होगा।

6-बेसमेंट में इलेक्ट्रिक ट्रॉसफार्मर की स्थापना, ज्वलनशील, विस्फोटक सामग्री आदि का भण्डारण नहीं किया जा सकेगा।

### (ड) रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम

भवन एवं पक्की सड़कों के द्वारा भू-खण्ड के प्रत्येक 300 वर्गमीटर के भू-आच्छादन (Ground Coverage) पर एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होगा। प्रत्येक 1000 वर्गमीटर के भू-आच्छादन (Ground Coverage) पर एक अतिरिक्त वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करना होगा।

### (छ) भू-आच्छादन एवं फ्लोर एरिया रेशियो (FAR)

विभिन्न भवनों हेतु भू-आच्छादन एवं फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) के मानक निम्नवत होंगे:-

क्रमांक	भवन एवं भू-उपयोग	भू-आच्छादन प्रतिशत	फ्लोर एरिया रेशियो (FAR)	भवन की अधिकतम ऊँचाई सूची-1 के अनुसार जनपदों में	भवन की अधिकतम ऊँचाई अन्य जनपदों में
1	2	3	4	5	6
				मीटर	मीटर
1.	आवासीय भवन				
(i)	भू-खण्ड 500 वर्ग मीटर तक	80	3.00	15	15
(ii)	भू-खण्ड 501-2000 वर्ग मीटर तक	65	4.00	15	15
2.	ग्रुप हाउसिंग योजना, रैन बसेरा (Night Shelter)	50	3.00	30	21

1	2	3	4	5	6
				मीटर	मीटर
3.	औद्योगिक भवन—	60	1.00	18	12
4.	व्यावसायिक भवन				
(i)	व्यावसायिक केन्द्र, शॉपिंग मॉल्स, सुविधा (Convenient) शॉपिंग केन्द्र, होटल	40	2.50	30	21
(ii)	बैंक, सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स	40	1.50	24	18
(iii)	वेयर हाउस, गोदाम	60	1.50	18	15
(iv)	दुकानें एवं मार्केट	60	1.50	15	10
5.	संस्थागत एवं शैक्षणिक भवन—				
(i)	समस्त उच्च शिक्षण संस्थान, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालय, डिग्री कॉलेज आदि	50	1.50	24	15
(ii)	हायर सेकंडरी, प्राइमरी, नर्सरी स्कूल, क्रेच सेन्टर आदि	50	1.50	24	15
(iii)	हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, चिकित्सालय, लैब, नर्सिंग होम आदि	75	2.50	24	15
6.	धर्मार्थ अथवा जन-हितार्थ भवन	50	1.20	15	10
(i)	सामुदायिक केन्द्र, क्लब, बारात घर, जिमखाना, अग्निशमन केंद्र, डाकघर, पुलिस स्टेशन	30	1.50	15	10
(ii)	धर्मशाला, लॉज, अतिथि गृह, हॉस्टल	40	2.50	15	10
(iii)	धर्मकांटा, पेट्रोल पम्प, गैस गोदाम, शीतगृह	40	0.50	10	6
7.	कार्यालय भवन—				
	सरकारी, अर्धसरकारी, कॉर्पोरेट एवं अन्य कार्यालय भवन	40	2.00	30	15
8.	क्रीडा एवं मनोरंजन कॉम्प्लेक्स, शूटिंग रेंज, सामाजिक एवं सांस्कृतिक केंद्र	20	0.40	15	10
9.	नर्सरी	10	0.50	6	6
10.	बस स्टेशन, बस डिपो, कार्यशाला	30	2.00	15	12
11.	फार्म हाउस	10	0.15	10	6
12.	डेयरी हाउस	10	0.15	10	6
13.	मुर्गा, सुअर, बकरी फार्म	20	0.30	6	6
14.	ए0टी0एम0	100	1.00	6	6

**(छ) सेटबैक (Setback)**

क्र० सं०	भू-खण्ड का क्षेत्रफल	सामने (Front)	साईड (Side)	पीछे (Rear)	लैंड स्केपिंग (Land Scaping)	खुला स्थान
1	2	3	4	5	6	7
	वर्ग मीटर	वर्ग मीटर	मीटर	मीटर		प्रतिशत
1.	150 तक	3.0	0.0	1.5	एक वृक्ष प्रति 100 वर्ग मीटर	25
2.	151-300 तक	3.0	0.0	3.0	तदैव	25
3.	301-500 तक	4.5	3.0	3.0	तदैव	25
4.	501-2000 तक	6.0	3.0	3.0	तदैव	25
5.	2001-6000 तक	7.5	4.5	6.0	तदैव	25
6.	6001-12000 तक	9.0	6.0	6.0	तदैव	25
7.	12001-20000 तक	12.0	7.5	7.5	तदैव	50
8.	20001-40000 तक	15.0	9.0	9.0	तदैव	50
9.	40001 से अधिक	16.0	12.0	12.0	तदैव	50

**(ज) पार्किंग स्थान**

क्र०सं०	भवन/भू-खण्ड	पार्किंग स्थान ECU (Equivalent Car Unit)
1	ग्रुप हाउसिंग योजना	एक ECU प्रति 80 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
2	संस्थागत एवं शैक्षणिक भवन	एक ECU प्रति 100 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
3	औद्योगिक भवन	एक ECU प्रति 100 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
4	व्यावसायिक भवन	एक ECU प्रति 30 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
5	सामाजिक एवं सांस्कृतिक केंद्र	एक ECU प्रति 50 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
6	लॉज, अतिथि गृह, हॉस्टल	एक ECU प्रति 2 अतिथि रुम के लिए
7	हॉस्पिटल, नर्सिंग होम	एक ECU प्रति 65 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
8	सिनेमा, मल्टीप्लेक्स	एक ECU प्रति 15 सीट्स
9	आवासीय भवन	एक ECU प्रति 150 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का

**(झ) अग्निशमन पद्धति, अग्नि सुरक्षा एवं सर्विसेस**

1-तीन मंजिल अथवा 15.0 मीटर से अधिक ऊँचे भवनों और विशिष्ट भवन यथा-संस्थागत एवं शैक्षणिक भवन, व्यावसायिक भवन, हॉस्पिटल, नर्सिंग होम, सिनेमा, मल्टीप्लेक्स 400 वर्गमीटर से अधिक भू-आच्छादन के भवन में अग्नि निकास हेतु एक जीना बाहर की दीवार पर एवं अग्नि सुरक्षा के अन्य सभी प्रावधान करने होंगे। भवन के चारों तरफ बाउन्ड्री दीवार के साथ-साथ 6.0 मीटर चौड़ा मार्ग का प्रावधान करना होगा। जिसमें दमकलों के चालन हेतु कम से कम 4.0 मीटर चौड़ाई का परिवहन मार्ग (Carriage Way) होगा।

2—अग्नि निकास जीने की न्यूनतम चौड़ाई 1.20 मीटर, ट्रेड की न्यूनतम चौड़ाई 28 सेमी0, राईजर अधिकतम 19 सेमी0, एक फ्लाइंट में अधिकतम राईजरों की संख्या 16 तक सीमित होगी।

3—अग्नि निकास जीने तक पहुँच दूरी 15.0 मीटर से अधिक न होनी चाहिए।

4—घुमावदार अग्नि निकास जीने का प्रावधान 10.0 मीटर से अधिक ऊँचे भवनों में नहीं किया जायेगा।

5—उपरोक्त भवनों हेतु अग्नि शमन विभाग के सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की जिम्मेदारी भवन स्वामी की होगी।

6—उपरोक्त भवनों में उत्तर प्रदेश अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम, (6) 2005 एवं राष्ट्रीय भवन संहिता (National Building code) 2005 भाग-4 के अनुसार प्रावधान किया जायेगा जैसे— स्वचालित स्प्रिंकलर पद्धति, फर्स्ट एड, होज रील्स, स्वचालित अग्नि संसूचन और चेतावनी पद्धति, सार्वजनिक संबोधन व्यवस्था, निकास मार्ग के संकेत चिन्ह, फायर मैन स्विच युक्त फायर लिफ्ट, वेट राइजर डाउन कॉर्नर सिस्टम आदि।

### (ज) इलेक्ट्रिक लाईन से दूरी

क्रमांक	विवरण	उर्ध्वाकार दूरी	क्षैतिज दूरी
		मीटर	मीटर
1	लो एण्ड मीडियम वोल्टेज लाईन तथा सर्विस लाईन	2.4	1.2
2	हाई वोल्टेज लाईन 33000 वोल्टेज तक	3.7	1.8
3	एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाईन	3.7+(0.305m) प्रत्येक अतिरिक्त 33000 वोल्टेज पर	1.8+(0.305m) प्रत्येक अतिरिक्त 33000 वोल्टेज पर

### (ट) मोबाईल टावर की स्थापना

1—अनाधिकृत रूप से निर्मित भवन पर टावर का निर्माण अनुमत्य नहीं होगा।

2—शैक्षणिक संस्थान, हास्पिटल, अधिक घनत्व वाली आवासीय बस्ती, अथवा धार्मिक भवन/स्थल आदि पर या इनके 100 मीटर के दायरे में मोबाइल टावर की स्थापना नहीं की जायेगी।

3—मोबाइल टावर की स्थापना हेतु भवन स्वामी एवं आवासीय कल्याण समिति (RWA) की अनापत्ति प्रस्तुत करनी होगी।

4—सेवा आपरेटर द्वारा टावर का निर्माण कार्य किये जाने से पूर्व काउंसिल आफ आर्कटेक्चर में पंजीकृत एवं अधिकृत स्ट्रक्चरल इंजीनियर द्वारा प्रस्तावित निर्माण का मानचित्र इस प्रमाण-पत्र के साथ प्रस्तुत करना होगा कि प्रस्तावित टावर प्रत्येक दृष्टि से सुरक्षित है, भवन जिस पर टावर निर्मित किया जाना है, (यदि ऐसा हो तो) भी टावर के साथ सुरक्षित है तथा प्रस्तावित कक्ष जिसका कुल क्षेत्रफल 60 वर्गमीटर से अनाधिक होगा, भवन निर्माण उपविधियों के अन्तर्गत है। स्ट्रक्चरल सेपटी मानकों के आधार पर भवन की सुदृढ़ता के संबंध में अधिकृत स्ट्रक्चरल इंजीनियर के स्थान पर आई0आई0टी0 तथा इसके समकक्ष संस्थान, लोक निर्माण विभाग, केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग आदि सरकारी संस्थाओं से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत किया जा सकता है।

5—टावर हेतु अनुज्ञा, भारत सरकार के दूरसंचार विभाग द्वारा लाईसेंस प्राप्त सेलुलर मोबाईल/बेसिक टेलीफोन सेवा आपरेटरों को ही प्रदान की जायेगी।

6—जनरेटर केवल "साईलेंट" प्रकृति के होंगे तथा भू-तल पर ही लगाये जायेंगे।

7—यदि टावर का निर्माण भवन की छत पर किया जाता है तो टावर का निचला भाग भवन की छत से न्यूनतम 3.0 मीटर ऊपर होना चाहिए।

8—जहाँ अपेक्षित हो, वहाँ टावर के निर्माण से पूर्व एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इण्डिया/वायुसेना का अनापत्ति प्रमाण-पत्र अनिवार्य रूप से प्रस्तुत करना होगा।

9—सेवा ऑपरेटर कम्पनी और भवन स्वामी को संयुक्त हस्ताक्षर से इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि यदि टावर निर्माण के फलस्वरूप आस-पास के भवनों को एवं जान-माल को किसी भी प्रकार की क्षति पहुँचती है तो उसकी क्षतिपूर्ति का समस्त दायित्व सम्बन्धित कम्पनी और भवन स्वामी का होगा।

10—सेवा प्रदाता द्वारा टावर में जनसामान्य का प्रवेश वर्जित करने के लिए समुचित उपाय यथा वायर फेंसिंग, भवनों की छतों पर जाने वाले दरवाजों पर ताला आदि के प्रावधानों के साथ टावर परिसर के प्रवेश द्वार पर, उचित स्थान पर चेतावनी सूचक साइन बोर्ड लगाना होगा जिसमें 'खतरा', 'आर0 एफ0 विकिरण', 'कृपया प्रवेश न करें' लिखा होगा।

11—इलैक्ट्रोमैग्नेट वेव्स, रेडियो विकिरण, वायब्रेशन (कम्पन) आदि के रूप में होने वाले दुष्परिणामों के नियन्त्रण हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार अथवा अन्य शासकीय अभिकरण द्वारा जारी दिशा निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा।

12—अनुज्ञा-पत्र प्राप्त करने के लिए प्रथम बार शुल्क के रूप में रु0 50,000.00 (पचास हजार मात्र) यह शुल्क एक वर्ष की अवधि के लिए होगा।

13—अनुज्ञा-पत्र के नवीनीकरण के लिए प्रथम बार लिए गये शुल्क का 10% प्रति वर्ष जमा कराना होगा। उक्त के अतिरिक्त अन्य कोई विकास शुल्क आदि नहीं लिया जायेगा।

### नक्शा स्वीकृति की दरें (कृपया देखें भाग-छ)

1—आवासीय भवन एवं शैक्षणिक भवन—सभी तलों पर फर्श से ढके भाग पर रु0 100.00 (एक सौ मात्र) प्रति वर्ग मीटर होगी।

2—व्यावसायिक एवं व्यापारिक भवन—सभी तलों पर फर्श से ढके भाग पर रु0 200.00 (दो सौ मात्र) प्रति वर्ग मीटर होगी।

3—(क) भूमि की प्लानिंग—भूमि को योजनाबद्ध तरीके से विभिन्न आकार के प्लानों में बाँटना।

(ख) भूमि विकास—भूमि पर योजनाबद्ध तरीके से पार्क, उद्यान बनाना, फार्म हाउस विकसित करना, नर्सरी लगाना, बारातघर/बैंकट हाल आदि।

(ग) भूमि का उपभोग—भूमि का विभिन्न प्रकार के सामानों के भण्डारण हेतु प्रयोग करना, जैसे— निर्माण सामग्री, कंटेनर, ईंधन, आर0सी0सी0 पाईप आदि।

(घ) किसी परियोजना का ले-आउट प्लान (तलपट मानचित्र)।

रु0 40.00 (चालीस मात्र) प्रति वर्ग मीटर होगी।

4—पुराने भवन को ध्वस्त करने के पश्चात् पुनः निर्माण करने की दशा में अनुज्ञा शुल्क की दरें नये भवन की दरों के समान होगी।

5—स्वीकृत भवन के नक्शे में संशोधन होने की दशा में अनुज्ञा शुल्क की दरें नये भवन की दरों की एक चौथाई होगी।

6—बेसमेंट, स्टिल्ट, पोडियम, सेवा क्षेत्र व अन्य आच्छादित क्षेत्र की, अनुज्ञा शुल्क में गणना की जाएगी।

7—यदि स्वीकृति के नवीनीकरण का आवेदन, अनुज्ञा अवधि समाप्ति से पूर्व किया जाता है तो स्वीकृति के नवीनीकरण की दरें मूल दरों की 20% होगी। एक बार में अनुज्ञा की अवधि एक वर्ष व अधिकतम दो वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है। अनुज्ञा अवधि समाप्ति के पश्चात् नवीनीकरण की दरें मूल दरों की 50% होगी।

8—उपविधियों के अनुसार, जिला पंचायत से नक्शों की स्वीकृति के बिना निर्माण करने, किसी भूमि पर व्यवसाय करने, स्वीकृत नक्शे से इतर निर्माण करने अथवा भू-खण्ड विकसित करने पर या इन उपविधियों की किसी उपविधि/उपविधियों का उल्लंघन करने पर अर्थदण्ड के रूप में समझौता शुल्क (Compounding Fees) रोपित किया



जाएगा। समझौता शुल्क (Compounding Fees) प्रस्तावित भवन अथवा ले-आउट प्लान (तलपट मानचित्र) पर परिस्थिति अनुसार, कुल शुल्क की गणना का कम से कम 20% से अधिकतम 50% अतिरिक्त होगा। समझौता शुल्क (Compounding Fees) विभाग में जमा होने के उपरान्त पूर्व में निर्मित भवन के नक्शों की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है। समझौते की कार्यवाही उ0प्र0 क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित) की धारा-248 में दी गयी व्यवस्था से नियन्त्रित होगी।

9-पूर्णता प्रमाण-पत्र (Completion Certificate) जारी करने हेतु (सभी तलों के कुल आच्छादित क्षेत्रफल पर) दरें रु0 40.00 (रु0 चालीस मात्र) प्रति वर्ग मीटर होगी।

10-चार दिवारी/बाउन्ड्री वाल स्वीकृति की दरें रु0 20.00 (रु0 बीस मात्र) प्रति वर्ग मीटर होगी।

**नोट**—(शुल्क निर्धारण हेतु भवन के सभी तलों पर फर्श के कुल क्षेत्रफल, कुल आच्छादित क्षेत्रफल सहित गणना करनी होगी)।

### (ठ) अनुज्ञा-पत्र जारी करने की प्रक्रिया

1-स्वामी द्वारा आवेदन-पत्र के साथ प्रस्तावित भवन/परियोजना के नक्शे एवं स्वामित्व के भू-अभिलेख अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत के कार्यालय में जमा किये जायेंगे। एवं आवेदक को इस प्रस्तुतिकरण की दिनांकित पावती दी जायेगी।

2-ऐसे आवेदन-पत्र एवं उसके साथ संलग्नकों को अपर मुख्य अधिकारी तत्काल कार्य अधिकारी/कर अधिकारी को भू-अभिलेखों के परीक्षण हेतु पृष्ठांकित कर देगा।

3-कार्य अधिकारी/कर अधिकारी ऐसे प्राप्त आवेदन पर उपरोक्त कार्यवाही पूर्ण करके अधिकतम एक सप्ताह में सम्बन्धित अभिलेख अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत को प्रस्तुत कर देगा। कार्य अधिकारी की तैनाती न होने की दशा में उपरोक्त कार्यवाही अपर मुख्य अधिकारी द्वारा स्वयं की जायेगी।

4-कार्य अधिकारी से प्राप्त आख्या को अपर मुख्य अधिकारी तत्काल अभियंता, जिला पंचायत को पृष्ठांकित कर देगा।

5-अभियंता द्वारा प्रस्तावित परियोजना के स्थलीय सर्वेक्षण हेतु निदेशित (Designated) अवर अभियंता को स्थल के सर्वेक्षण हेतु आदेशित किया जायेगा।

6-अवर अभियंता द्वारा स्थल सर्वेक्षण की आख्या अधिकतम एक सप्ताह में अभियंता, जिला पंचायत को प्रस्तुत की जायेगी।

7-अवर अभियंता से सर्वेक्षण आख्या प्राप्त होने के उपरान्त बहुमंजिली भवन, व्यवसायिक भवन, संकटमय भवन एवं शैक्षणिक भवन अथवा अन्य महत्वपूर्ण परियोजना के नक्शा पारित करने से पहले अभियन्ता जिला पंचायत द्वारा प्रस्तावित परियोजना के स्थल का सर्वेक्षण अनिवार्य होगा।

8-अभियन्ता द्वारा स्थल की सर्वेक्षण आख्या प्रस्तुत करने के उपरान्त सर्वेक्षण आख्या का परीक्षण किया जायेगा। परियोजना के नक्शों की स्वीकृति हेतु अवर अभियंता से एक अंतरिम शुल्क की गणना करके अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत को सूचित किया जायेगा। आवेदक द्वारा आंगणित अन्तरिम शुल्क की 20% धनराशि अग्रिम रूप से नोटिस प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर कार्यालय जिला पंचायत में जमा करनी होगी। इसके उपरान्त ही नक्शे के विषय में अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। प्रतिबंध यह है, कि नक्शा पारित होने के स्तर पर आवेदक मांग-पत्र के अनुसार निर्धारित अवधि में यदि शुल्क जमा करता है, तो उक्त धनराशि समायोजित (Adjust) हो जायेगी। अन्यथा की दशा में जमा धनराशि जब्त हो जायेगी।

9-जिला पंचायत के अभियंता द्वारा परियोजना की संभाव्यता (Possibility), सुगमता (Convenience), साध्यता (Feasibility), तकनीकी जांच व जिला पंचायत भवन उपविधि में तकनीकी प्रावधानों एवं नक्शों का परीक्षण किया जायेगा। आवश्यकता समझने पर नक्शों में संशोधन हेतु आवेदन कर्ता को निर्देशित किया जायेगा।

10—अभियंता द्वारा परियोजना तकनीकी दृष्टि से सुस्थित (Sound) पाये जाने पर अपनी तकनीकी आख्या अपर मुख्य अधिकारी को अधिकतम 15 दिन में प्रस्तुत करनी होगी। अवर अभियंता से आंगणित शुल्क की धनराशि का विवरण प्रतिपरीक्षण (Cross Verification) कराके तकनीकी आख्या के साथ संलग्न करना होगा।

11—अपर मुख्य अधिकारी उक्त आख्या प्राप्त होने पर कार्य अधिकारी एवं अभियंता द्वारा प्राप्त आख्याओं का परीक्षण करके आवेदक को शुल्क जमा करने का मांग-पत्र जारी करेंगे। जिसमें आवेदक को शुल्क जमा करने के लिये एक माह का समय दिया जायेगा।

12—आवेदक द्वारा नक्शा शुल्क निर्धारित समय में जमा कराना होगा। जिला निधि की रोकड़ बही में शुल्क की प्रविष्टि के उपरांत अपर मुख्य अधिकारी द्वारा नक्शे की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

13—उपरोक्त समस्त कार्यवाही पूर्ण होने के पश्चात् अध्यक्ष, जिला पंचायत की स्वीकृति उपरान्त आवेदक को अनुज्ञा-पत्र अभियंता व अपर मुख्य अधिकारी के संयुक्त हस्ताक्षर से आवश्यक शर्तों के साथ जारी किया जायेगा। नक्शों पर अभियंता, अपर मुख्य अधिकारी एवं अध्यक्ष, के संयुक्त हस्ताक्षर से स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

14—यदि जिला पंचायत द्वारा आवेदन प्राप्ति के दो माह के भीतर आवेदक को कोई सूचना अथवा शुल्क का मांग पत्र जारी नहीं किया जाता है, तो आवेदक द्वारा निर्धारित दो माह की अवधि के समाप्ति के दिनांक से 20 दिन के भीतर प्रकरण अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत के संज्ञान में लिखित रूप से लाया जायेगा। यदि इस पर भी अपर मुख्य अधिकारी 10 दिन में कोई कार्यवाही नहीं करता है, तो पूर्व में प्रस्तुत नक्शा एवं निर्माण की स्वीकृति मानित स्वीकृति (Deemed Sanction) मानी जायेगी।

**विवाद**—उक्त कार्यवाही में किसी विवाद होने की दशा में या स्वीकृत नक्शा किन्हीं कारणों से निरस्त होने की दशा में या ऐसी कार्यवाही उत्पन्न होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर प्रकरण अध्यक्ष, जिला पंचायत को संदर्भित किया जायेगा। जिसमें उनको अपना अनुदेश ऐसे प्रकरण की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर देना होगा एवं उनका ये आदेश अभयपक्षों पर बन्धनकारी होगा।

### (ण) सामान्य अनुदेश (General Instructions)

1—भारत सरकार अथवा उत्तर प्रदेश सरकार या पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित ऐतिहासिक स्मारक, इमारत या स्थल के 200 मीटर के दायरे में निर्माण की अनुमति नहीं दी जायेगी। 200 मीटर से 1.50 किलोमीटर के दायरे में उपविधियोंनुसार निर्माण हेतु मंजिलों एवं ऊँचाई की अनुमति, तत्समय आवश्यक और उचित कारण सहित दी जा सकेगी।

2—प्रस्तावित भू-खण्ड की सीमा से बाहर किसी भी प्रकार के निर्माण की अनुमति नहीं दी जायेगी।

3—भवन के भू-तल पर स्टिल्ट पार्किंग (Stilt Parking), वाहन पार्किंग, बेसमेंट वाहन पार्किंग, भण्डारण व सुविधाओं के रखरखाव व सेवा तल भण्डारण व सुविधाओं के रखरखाव इत्यादि हेतु उपयोग किया जाए, तो इनका क्षेत्रफल फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) में शामिल नहीं होगा।

4—निकटतम हवाई अड्डा, चाहें विमानापत्तन प्राधिकरण (Airport Authority) द्वारा नियन्त्रित हो या रक्षा विभाग अथवा अन्य शासकीय विभाग द्वारा नियन्त्रित हो, के 05 किलोमीटर की परिधि में 30 मीटर से ऊँचे भवन के आवेदनकर्ता को उक्त वर्णित प्रतिष्ठानों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेना होगा।

5—उपरोक्त उपविधि में सभी बातों के होते हुए भी जिला पंचायत यदि उचित व आवश्यक समझे तो, कारणों का उल्लेख करते हुए किसी भवन में भू-आच्छादन, फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) अथवा अधिकतम ऊँचाई में परिवर्तन कर स्वीकृति प्रदान कर सकती है।

6—उपविधियों में दी गयी सूची में उल्लिखित भवनों के अतिरिक्त भवनों एवं गतिविधियों के लिए नियमों व विनियमों का निर्धारण जिला पंचायत द्वारा, इस प्रकार के समकक्ष (Similar) भवनों एवं गतिविधियों के लिए निर्धारित उपविधियों के अनुसार किया जायेगा।

7—मल्टी लेवल पार्किंग में संरचनात्मक एवं सुरक्षा की शर्तों के अधीन अधिकतम दो बेसमेंट अनुमन्य होंगे।

8—इन उपविधियों के अधीन जारी अनुज्ञा, जारी होने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिए वैध एवं मान्य होगी।

9—इन उपविधियों का पालन न करने की दशा में जिला पंचायत द्वारा सम्बन्धित उल्लंघनकर्ता के विरुद्ध सी. आर0पी0सी0 की धारा-133 के अन्तर्गत कार्यवाही की जायेगी।

**(त) अनुज्ञा की शर्तें**

(क) अनुज्ञा-पत्र जारी होने के उपरान्त यदि यह संज्ञान में आए कि भवन निर्माण नक्शे की स्वीकृति हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख फर्जी हैं अथवा उसके द्वारा गलत विवरण दिया गया है, तो जिला पंचायत द्वारा दी गयी नक्शे की स्वीकृति निरस्त की जा सकती है, किया गया निर्माण ध्वस्त किया जा सकता है अथवा सील (Seal) किया जा सकता है।

(ख) अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत को अधिकार होगा कि वह अभियन्ता की संस्तुति पर, पंजीकृत वास्तुविद् द्वारा प्रस्तुत नक्शे में संशोधन अथवा परिवर्तन कर दे अथवा यथारूप स्वीकार कर दें।

(ग) पंजीकृत वास्तुविद् द्वारा तैयार एवं हस्तारित नक्शे ही मान्य होंगे। परियोजना का डिजाईन वास्तुविद् के अधीन कार्य करने वाले योग्य अभियन्ता द्वारा कराया जायेगा।

(घ) कोई भी व्यक्ति, कम्पनी, फर्म या संस्था, राजकीय विभाग अथवा ठेकेदार आदि द्वारा प्रस्तावित मानचित्र जिला पंचायत से स्वीकृत होने के बावजूद अन्य उन सभी विभागों से जिनसे लाईसेंस या अनापत्ति प्रमाण-पत्र लिया जाना आवश्यक है, उनसे लाईसेंस/अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने का उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

(ङ) शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत आदेशों का पालन आवेदनकर्ता/मालिक को करना होगा।

(च) निर्माण के दौरान अथवा स्वीकृति के समय अपर मुख्य अधिकारी को यदि किसी प्रमाण पत्र (तकनीकी एवं प्रशासनिक) की आवश्यकता पड़ने पर आवेदनकर्ता को प्रस्तुत करना होगा।

**दण्ड**

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित) की धारा-240 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, लखनऊ यह निर्देश देती है, कि जो भी स्वामी इन उपविधियों का उल्लंघन करेगा, वह अर्थ-दण्ड से दण्डनीय होगा। जो अंकन रु0 1,000.00 तक होगा, जो प्रथम दोष सिद्ध होने के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए, जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता रहा है, रुपये 50.00 प्रतिदिन हो सकेगा, अथवा अर्थ-दण्ड का भुगतान न किया जाए तो कारावास से दण्डित किया जायेगा, जोकि तीन माह तक हो सकेगा।

**निरसन**

भवन निर्माण उपविधियों के जिला पंचायत, लखनऊ के क्षेत्र में प्रभावी होने के दिनांक से पूर्व प्रचलित उपविधियाँ निरस्त हो जायेगी।

20 दिसम्बर, 2022 ई0

सं0 3315/21ए-06/2021-22—उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 जो उ0प्र0 पंचायत विधि (संशोधन) अधिनियम, 1994 द्वारा संशोधित है, की धारा 239 (2) के अन्तर्गत प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, लखनऊ द्वारा जनपद लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्र में पशु मेलों, पशु बाजार, पशु पेंठों अथवा प्रदर्शनियों को नियंत्रित एवं विनियमित करने के संबंध में प्रचलित उपविधि में संशोधन सम्बन्धी उपविधि बनायी गयी है। मेरे द्वारा उपविधि की पुष्टि कर दी गयी है एवं उक्त अधिनियम की धारा 242(2) के अन्तर्गत प्रकाशित की जाती है। यह उपविधि गजट में प्रकाशित होने की तिथि से लागू होगी।

**पशु मेला, पशु बाजार, पशु पेंठ अथवा पशु प्रदर्शनी****उपविधियाँ**

1—ग्रामीण क्षेत्र का तात्पर्य उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम, 1961 में दी गई परिभाषा से है।

2—पशु मेला, पशु बाजार, पशु पेंठ अथवा पशु प्रदर्शनी का तात्पर्य उस स्थल से है, जहां जिला पंचायत किसी व्यक्ति अथवा किसी संस्था (जिसमें धार्मिक संस्था भी सम्मिलित है) शामिल है, द्वारा जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में कय-विक्रय अथवा प्रदर्शनी हेतु पशु लाये जाते हैं।

3-पशु का तात्पर्य सभी जाति एवं श्रेणी के पशुओं से है।

4-रजिस्ट्रेशन अधिकारी का तात्पर्य उस वयस्क व्यक्ति से है, जिसे लाईसेंस अधिकारी ने जिला पंचायत द्वारा स्थापित पशु पैठों अथवा पशु प्रदर्शनियों, पशु मेलों, पशु बाजारों में पशुओं की बिक्री लिखने एवं शुल्क उगाही हेतु रसीद जारी करने हेतु नियुक्त किया है। निजी पशु मेलों पशु बाजारों, पशु पैठों एवं पशु प्रदर्शनियों में उनके संचालक अथवा प्रबन्धक की संस्तुति कर उपरोक्त प्रयोजन हेतु लाईसेंस अधिकारी द्वारा नियुक्त किया गया व्यक्ति रजिस्ट्रेशन अधिकारी माना जायेगा।

5-ठेकेदार का तात्पर्य भी उस वयस्क व्यक्ति से है जिसे जिला पंचायत ने किसी पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी हेतु ठेके की शर्तों के अनुरूप नियत अवधि के लिए प्रबन्ध के निमित्त अधिकृत किया हो।

### उपविधि भाग-1

1-प्रत्येक व्यक्ति जो जिला पंचायत, लखनऊ के ग्रामीण क्षेत्र में कोई पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी आयोजित करना चाहता है, को इन उपविधियों का पालन करना अनिवार्य होगा।

2-पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी के संचालक अथवा उसके द्वारा नियुक्त मैनेजर या अधिकृत एजेंट के लिये, बाजार में आये हुए व्यक्तियों के ठहरने, जानवरों हेतु चारा-पानी, साफ-सफाई, शौचालय तथा रोशनी का प्रबन्ध व रख-रखाव स्वयं कराना होगा।

3-जिला पंचायत के अध्यक्ष, अपर मुख्य अधिकारी, कार्य अधिकारी, कर अधिकारी या उनके द्वारा अधिकृत कर्मचारी किसी भी समय निरीक्षण कर सकता है।

4-नवीन पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी आयोजित करने के लिए शान्ति व्यवस्था सम्बन्धी पुलिस विभाग राजस्व विभाग तथा चिकित्सा विभाग की आख्या प्राप्त होने के उपरान्त जिला पंचायत के लाईसेंस अधिकारी द्वारा लाईसेंस प्रार्थना-पत्र पर विचार किया जायेगा।

5-नये पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी आयोजित करने के लिए यह अनिवार्य होगा कि प्रारम्भ करने के तिथि से एक माह (तीस दिन) के पूर्व जिला पंचायत से लाईसेंस प्राप्त कर लेंगे। लाईसेंस की अवधि 01 अप्रैल से 31 मार्च होगी।

6-किसी पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी के स्थल से 8 किमी० के अन्दर किसी दूसरे पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी लगाने हेतु लाईसेंस नहीं दिया जायेगा। प्रतिबन्ध यह है, कि यह नियम उपविधि के लागू होने से पूर्व से आयोजित हो रहे पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनियों पर प्रभावी नहीं होगा।

7-1 अप्रैल से 30 अप्रैल तक लाइसेंस शुल्क जमा कर लाइसेंस नवीनीकरण कराना होगा उसके उपरान्त रु० 1,000.00 प्रति माह विलम्ब शुल्क जमा कर ही लाइसेंस प्राप्त किया जा सकेगा।

8-किसी पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी पूर्व से लग रही है, उसके संचालक को इन उपविधियों के प्रकाशन के एक माह के अन्दर लाईसेंस बनवा लेना होगा अन्यथा उपनियम संख्या-09 के अनुसार विलम्ब शुल्क जमा करने पर ही लाईसेंस जारी किया जायेगा। प्रतिबन्ध यह है कि ग्राम पंचायतों द्वारा आयोजित पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी पर लगाये गये विलम्ब शुल्क को किसी स्थिति तक कम करने अथवा समाप्त करने का विशेषाधिकार अध्यक्ष, जिला पंचायत को होगा।

9-अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, लखनऊ इन उपविधियों के अन्तर्गत लाईसेंस अधिकारी होगा।

10-पशुओं के पंजीकरण/रजिस्ट्रेशन की रसीद बुक जिला पंचायत में पशु बाजार स्वामी द्वारा निर्धारित शुल्क जमा कराकर प्राप्त की जायेगी तथा पशु बाजार स्वामी द्वारा पंजीकरण/रजिस्ट्रेशन रसीद बुक प्रयुक्त होने के उपरान्त जिला पंचायत में जमा करना अनिवार्य होगा।

11—पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी के लिए निम्नलिखित लाईसेन्स शुल्क देय होगा:—

(1) वर्ष में एक बार 01 से 15 दिन तक लगातार लगने वाले पशु मेले के लिए लाईसेन्स शुल्क।	—	रु0 25,000 वार्षिक
(2) वर्ष में एक बार 15 दिन से अधिक किन्तु 30 दिन तक लगातार लगने वाले पशु मेले के लिए लाईसेन्स शुल्क।	—	रु0 40,000 वार्षिक
(3) वर्ष में बार 30 दिन से अधिक अवधि के लिए लगातार लगने वाले पशु मेले के लिए लाईसेन्स शुल्क।	—	रु0 50,000 वार्षिक
(4) सप्ताह में एक बार लगने वाले पशु बाजार, पशु पैठ का लाईसेन्स शुल्क।	—	रु0 20,000 वार्षिक
(5) सप्ताह में 2 दिन लगने वाले पशु बाजार, पशु पैठ का लाईसेन्स शुल्क।	—	रु0 40,000 वार्षिक
(6) सप्ताह में 2 दिन से अधिक बार लगने वाले पशु बाजार पशु पैठ का लाईसेन्स शुल्क।	—	रु0 60,000 वार्षिक

### उपविधि भाग-2

1—जिला पंचायत, लखनऊ द्वारा संचालित पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी में सार्वजनिक मार्ग के किनारे पशुओं के लदान व उतारने के लिए अड्डों की व्यवस्था करेगी।

2—निजी स्वामित्व में लगने वाले पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी के निकट सार्वजनिक मार्ग के किनारे पशुओं के लदान एवं उतरान हेतु अड्डे की व्यवस्था जिला पंचायत द्वारा ही किया जायेगा।

3—यातायात की सुरक्षा तथा मेले में ट्रैफिक की व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिए अड्डों के पास वाहनों का पार्किंग स्थल निर्धारित किया जायेगा। पशुओं के लदान व उतरान के लिए अड्डा बनायी जायेगी।

4—जिला पंचायत अड्डों की स्थापना एवं संचालन का कार्य स्वयं, किसी एजेन्सी अथवा ठेकेदार के माध्यम से करेगी। निजी क्षेत्र के पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी में अड्डों की स्थापना ट्रैफिक व्यवस्था संचालन के कार्य हेतु पशु मेला, पशु बाजार, पशु पैठ एवं पशु प्रदर्शनी के स्वामी से कोई सम्बन्ध नहीं रहेगा।

5—ढुलान, उतरान एवं पार्किंग शुल्क निम्न प्रकार देय होगा—

वाहन की किस्म	शुल्क रु0
(1) मेटाडोर या छोटा ट्रक, ट्राली	75.00
(2) बड़ा ट्रक, ट्राली	100.00
(3) छोटा ट्रक या मेटाडोर जिसमें पशु लदे हो	150.00
(4) बड़ा ट्रक जिसमें पशु लदे हो	200.00
(5) सामान भरा बैलगाड़ी या खड़-खड़ा	30.00
(6) खाली बैलगाड़ी या खड़-खड़ा	20.00
(7) सामान भरा ट्रैक्टर, ट्राली, मेटाडोर तथा छोटा ट्रक	200.00
(8) सामान भरा हुआ बड़ा ट्रक	300.00

**दण्ड**

उ० प्र० क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत, अधिनियम, 1961 की धारा 240 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत, लखनऊ यह निर्देश देती है, कि जो व्यक्ति इन उपविधियों का उल्लंघन करेगा, वह अर्थदण्ड से दण्डनीय होगा, जो रु० 1,000.00 तक होगा और यदि ऐसा उल्लंघन जारी रहे तो अतिरिक्त अर्थदण्ड से दण्डित होगा जो प्रथम दोष सिद्ध होने के बाद ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिनके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि उसमें अपराधी अपराध करता रहा है रु० 50 प्रतिदिन हो सकेगा, अथवा अर्थ-दण्ड का भुगतान न किया जाए तो कारावास से दण्डित किया जायेगा, जोकि तीन मास तक हो सकेगा।

डा० रोशन जैकब,  
आयुक्त,  
लखनऊ मण्डल, लखनऊ।

**कार्यालय, जिला पंचायत, चित्रकूट****संशोधन**

22 दिसम्बर, 2022 ई०

सं० 930/ख० परि० शु०-उपविधि/जि०पं०चि०/2022-23-सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि संख्या-2376/23-एल०बी०ए०/उपविधि गजट दिनांक 5 अक्टूबर 2013 ई० प्रकाशन उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित) की धारा 142-143 के साथ पठित धारा 239 के अधीन दी गयी शक्ति का प्रयोग कर जिला पंचायत, चित्रकूट द्वारा जनपद चित्रकूट अथवा अन्य जनपदों के ग्रामीण क्षेत्र की नदियों या उनके तट से बालू, मोरम, रेत या अन्य खनिजों गिट्टी, कोयला, बजरी, भस्सी, खारों से निकलने वाली मिट्टी को लेने, एकत्रित करने तथा उसे जिले में जिले के बाहर व्यवसायिक उद्देश्य से परिवहन करने वाले शक्ति चालित वाहन या पशु चालित वाहन यथा ट्रैक्टर ट्राली, ट्रक, मिनी ट्रक, डम्पर, पशुगाड़ी, या मानव चालित नौका को नियन्त्रित एवं विनियमित करने हेतु उपविधि बनायी गई है। इस प्रभावी खनिज परिवहन शुल्क/तहबाजारी उपविधि की धारा 2.10 प्रस्तर 6 एवं धारा 2.9 प्रस्तर 21 में नियमानुसार आवश्यक संशोधन करने की उपविधि जो जिला पंचायत, चित्रकूट के अन्य प्रस्ताव संख्या-3 दिनांक 17 सितम्बर, 2022 द्वारा सर्वसम्मति से पारित है और उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम की धारा 242(2) के प्रयोजनार्थ प्रकाशित है। यदि इस पर किसी को कोई आपत्ति/सुझाव हों तो प्रकाशन तिथि से 30 दिन के अन्दर लिखित रूप से कार्यालय में दे सकते हैं। निर्धारित अवधि के उपरान्त प्राप्त सुझाव/आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

इलाहाबाद शनिवार 5 अक्टूबर 2013 ई० (आश्विन 13, 1935 शक संवत्) 23 सितम्बर, 2013 ई० द्वारा प्रकाशित उपविधि में प्राविधानित दरों के सापेक्ष प्रस्तावित/संशोधित दरें निम्नवत् हैं—

**संशोधन**

क्र० सं०	उपविधि में प्राविधानित दरें	प्रस्तावित संशोधित दरें
1	6—जिला पंचायत चित्रकूट द्वारा लिये जाने वाले शुल्क की दरें निम्न प्रकार होंगी— 1. पशुओं के द्वारा खींचे जाने वाली गाड़ी 10 रु० प्रति फेरी 2. मानव चालित नाव 20 रु० प्रति फेरी 3. ट्रैक्टर ट्राली 50 रु० प्रति फेरी 4. ट्रक:— (क) मिनी ट्रक (लाइट गुड्स 100 रु० प्रति फेरी विहिकिल्स) (ख) ट्रक (लाइट गुड्स 150 रु० प्रति फेरी विहिकिल्स 6 चक्का) (ग) भारी ट्रक (हैवी गुड्स 200 रु० प्रति फेरी विहिकिल्स 10 चक्का या अधिक)	6—जिला पंचायत चित्रकूट द्वारा लिये जाने वाले शुल्क की दरें निम्न प्रकार होंगी— 1. पशुओं के द्वारा खींचे जाने वाली गाड़ी 20 रु० प्रति फेरी 2. मानव चालित नाव 40 रु० प्रति फेरी 3. ट्रैक्टर ट्राली 100 रु० प्रति फेरी 4. ट्रक:— (क) मिनी ट्रक (लाइट गुड्स 200 रु० प्रति फेरी विहिकिल्स) (ख) ट्रक (लाइट गुड्स 300 रु० प्रति फेरी विहिकिल्स 6 चक्का) (ग) भारी ट्रक (हैवी गुड्स 400 रु० प्रति फेरी विहिकिल्स 10 चक्का या अधिक)

क्र० सं०	उपविधि में प्राविधानित दरें	प्रस्तावित संशोधित दरें
2	21-वसूली स्थल पर अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, चित्रकूट के द्वारा सार्वजनिक मार्ग /नदी मार्ग पर ऐसे स्थान पर नियत किये जायेगे, जहां पर कि यातायात अवरुद्ध न हो। वसूली स्थल पर गाड़ियों को रोकने हेतु किसी प्रकार का बैरियर या रस्सी का प्रयोग नहीं किया जायेगा।	21-वसूली स्थल पर अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, चित्रकूट के द्वारा खनिज के उद्गम स्थल/नदी मार्ग पर ऐसे स्थान पर नियत किये जायेगे, जहां पर कि यातायात अवरुद्ध न हो। खनिज उद्गम स्थल का अर्थ बालू/मोरम/ सिलकासेण्ड-समस्त स्वीकृत पट्टे जनपद-चित्रकूट एवं गिट्टी/भस्सी उद्गम स्थल समस्त स्टोन क्रेशर जनपद चित्रकूट से है। वसूली स्थल पर गाड़ियों को रोकने हेतु किसी प्रकार का बैरियर या रस्सी का प्रयोग नहीं किया जायेगा।

ह० (अस्पष्ट),  
आयुक्त,  
चित्रकूटधाम मण्डल, बांदा।

### कार्यालय जिला पंचायत, बांदा

24 दिसम्बर, 2022 ई०

सं० 325/21-एल०बी०ए०/उपविधि-प्रकाशन-उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 (यथा संशोधित) की धारा 239 (1) एवं धारा 239 (2) के साथ पठित अधिनियम की धारा 143 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग कर के जिला पंचायत बांदा ने ग्राम्य क्षेत्र, जो कि उक्त अधिनियम की धारा 2 (10) में परिभाषित है, में से इस क्षेत्र में स्थापित किसी विकास प्राधिकरण एवं उ०प्र० औद्योगिक क्षेत्र विकास अधिनियम 1976 की धारा 2 (डी) में घोषित औद्योगिक विकास क्षेत्र को हटाते हुए शेष ग्राम्य क्षेत्र के अन्तर्गत बनने वाले सभी प्रकार के भवनों के नक्शों एवं निर्माण को नियंत्रित एवं विनियमित करने के उद्देश्य से निम्न उपविधि बनायी है। यह उपविधि उ०प्र० गजट में प्रकाशित होने की तिथि से प्रभावी होगी।

1-अधिनियम का तात्पर्य उ०प्र० क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 से है।

2-ग्राम्य क्षेत्र से तात्पर्य जिले में स्थित प्रत्येक नगर पंचायत, नगर पालिका परिषद, छावनी तथा नगर निगम क्षेत्र के अतिरिक्त उस क्षेत्र को हटाते हुए जोकि किसी विकास प्राधिकरण, विनियमित क्षेत्र या यू०पी०एस०आई०डी०सी० के द्वारा अधिग्रहीत किया गया हो, जिसके अधिग्रहण की सूचना पूर्ण विवरण सहित यथा ग्राम का नाम, गाटा/खसरा संख्या, अधिग्रहीत क्षेत्रफल आदि गजट में प्रकाशित की जा चुकी हो।

3-विनियमन का मतलब भवन के मूल निर्माण एवं बने हुए भवन में अतिरिक्त निर्माण एवं फेरबदल की कार्यवाही को विनियमित करने से है।

4-मानचित्र से तात्पर्य भवन के ड्राइंग, डिजाइन एवं विशिष्टियों के अनुसार कागज/इलेक्ट्रानिक्स डिवाइस पर बने उस नक्शे से है, जोकि पंजीकृत वास्तुविद के द्वारा बनाकर प्रस्तुत किया गया हो एवं डिजाइन योग्य (Eligible) अभियन्ता द्वारा तैयार किया गया हो।

5-निर्माण कार्य का तात्पर्य किसी भवन का निर्माण करना, पुनः निर्माण करना या उसमें सारवान विचलन करना या उसको ध्वस्त करने से है।

6-भवन की ऊंचाई का तात्पर्य संलग्न किसी नाली के टाप से लेकर उस भवन के सबसे ऊंचे बिन्दु तक नापी गयी लम्बवत (Vertical) ऊंचाई से एवं ढलान वाली छत के लिए दो गहराईयों के बीच से है। भवन की ऊंचाई में मन्टी, मशीनरूम, पानी की टंकी, एन्टीना आदि की ऊंचाई सम्मिलित नहीं होगी।

7-छज्जा का तात्पर्य ऐसे ढलाननुमा या भूमि के क्षितिज के अनुसार बाहर निकला हुआ भाग जोकि सामान्यतया सूरज या बारिश से बचाव के लिए बनाया जाता है।

8-ड्रेनेज का तात्पर्य उस व्यवस्था से है, जिसका निर्माण किसी तरल पदार्थ जैसे रसोई, स्नानगृह से विसर्जित पानी आदि को हटाने के लिए किया जाता है, इसके अन्तर्गत नाली व पाइप भी सम्मिलित है।

9-निर्मित भवन का तात्पर्य ऐसे भवन से है, जोकि परिभाषित ग्रामीण क्षेत्र में इन उपविधियों के लागू होने से पहले अस्तित्व में आ चुका है अथवा जिला पंचायत की स्वीकृति के बिना निर्मित किया गया हो।

10-तल (Floor Level) का तात्पर्य किसी मंजिल के उस निचले खंड से है, जहां पर सामान्यतः किसी भवन में चला फिरा जाता हो।

11-फ्लोर एरिया रेशियो (FAR-Floor Area Ratio) का तात्पर्य उस भागफल से है, जो सभी तलों के आच्छादित कुल क्षेत्रफल को भू-खण्ड के क्षेत्रफल से भाग देने से प्राप्त होता है।

12-भू-आच्छादन (Ground Coverage) का तात्पर्य भू-तल पर बने सभी निर्माण द्वारा घेरे गये क्षेत्रफल से है।

13-ग्रुप हाउसिंग का तात्पर्य उस परिसर से है, जिसके अन्दर आवासीय प्लैट अथवा स्वतंत्र आवासीय (Independent Apartment Unit) इकाई बनी हों तथा मूल सुविधाओं जैसे पार्किंग, पार्क, बाजार, जनसुविधाएँ आदि का प्रावधान हो।

14-ले-आउट प्लान का तात्पर्य उस नक्शे से है, जोकि किसी स्थल के समस्त भू-खण्ड, भवन खण्ड, मार्ग, खुली जगह, आने-जाने के बिन्दु, पार्किंग व्यवस्था, भू-निर्माण (Landscaping) अथवा विभिन्न आकार की प्लाटिंग की समस्त जानकारी व अन्य विवरण को इंगित करने वाला प्लान से है।

15-प्राविधिक (Technical) व्यक्ति का तात्पर्य निम्नलिखित से है:-

(अ) अभियंता-अभियंता, जिला पंचायत

(ब) अवर अभियंता-इस उपविधि में अवर अभियंता का तात्पर्य उस अवर अभियंता से है जिसको अभियंता, जिला पंचायत द्वारा भवन के नक्शों की स्वीकृति की कार्यवाही के लिए निदेशित (Designated) किया गया हो।

16-कार्य अधिकारी का तात्पर्य कार्य अधिकारी, जिला पंचायत से है।

17-अधिभोग (Occupancy) का तात्पर्य उस प्रयोजन से है, जिसके लिए भवन या उसका भाग प्रयोग में लाया जाना है, जिसके अन्तर्गत सहायक अधिभोग भी सम्मिलित है।

18-स्वामी का तात्पर्य व्यक्ति, व्यक्तियों का समूह, कम्पनी, ट्रस्ट, पंजीकृत संस्था राज्य सरकार एवं केन्द्र सरकार के विभाग एवं अन्य प्राधिकरण जिसके/जिनके नाम में भूमि का स्वामित्व सम्बन्धित अभिलेखों में दर्ज है।

19-रेन वाटर हार्वेस्टिंग का तात्पर्य बरसात के पानी को उपयोग करके विभिन्न तकनीकों से भू-गर्भ जल के स्तर को ऊंचा उठाने से है।

20-सेटबैक का तात्पर्य किसी भवन के चारों तरफ यथा स्थिति या मानक के अनुसार एवं बाउन्ड्री दीवार के बीच छोड़ी गयी खाली जगह अथवा रास्ते से है।

21-अपर मुख्य अधिकारी का तात्पर्य अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, बॉदा से है।

22-जिला पंचायत का तात्पर्य अधिनियम की धारा 17(1) में संघटित जिला पंचायत बॉदा से है।

23-अध्यक्ष का तात्पर्य-अध्यक्ष, जिला पंचायत बॉदा से है।

24-बहु मंजिली भवन (Multy Storey) चार मंजिल अथवा 15 मीटर से अधिक ऊंचाई का भवन बहु मंजिल कहलायेगा।

25-मंजिल का तात्पर्य भवन के उस भाग से है, जो किसी तल की सतह और इसके ऊपर के अनुवर्ती तल के बीच हो और यदि इसके ऊपर कोई तल न हों, तो वह स्थान जो तल और इसके ऊपर की छत के मध्य हों।

26-भवन का तात्पर्य ऐसी स्थायी प्रकृति के निर्माण अथवा संरचना से है, जोकि किसी भी प्रकार की सामग्री से निर्माण किया जायें, एवं उसका प्रत्येक भाग चाहें मानव प्रयोग या अन्यथा किसी प्रयोग में लाया जा रहा हो एवं उसके अन्तर्गत बुनियाद, कुर्सी क्षेत्र, दीवार, फर्श, छत, चिमनी, पानी की व्यवस्था, स्थायी प्लैटफार्म, बरान्डा, बालकनी, कानर्स या छज्जा या भवन का अन्य भाग जो किसी खुले भू-भाग को ढकने के उद्देश्य से बनाया जायेगा। इसके अन्तर्गत टैन्ट, शामियाना, तिरपाल आदि जोकि पूर्णतः अस्थायी रूप से किसी समारोह के लिये लगाये जाते हैं, वह भवन की परिभाषा में सम्मिलित नहीं होंगे।

27-आवासीय भवन के अन्तर्गत वे भवन सम्मिलित होंगे जिनमें सामान्यतः आवासीय प्रयोजन के प्राविधान सहित शयन सुविधा के साथ खाना बनाने तथा शौचालय की सुविधा हो। इसमें एक अथवा एक से अधिक आवासीय इकाई शामिल है।



28—व्यवसायिक/वाणिज्यिक भवन के अन्तर्गत वे भवन या भवन का वह भाग जो दुकानों, भण्डारण बाजार व्यवसायिक वस्तुओं के प्रदर्शन, थोक या फुटकर बिक्री, व्यवसाय से सम्बन्धित कार्यकलाप होटल, पेट्रोल पम्प, कन्वीनिएन्स स्टोर्स एवं सुविधाएं जो माल व्यवसायिक माल की बिक्री से अनुशांगिक हों और उसी भवन में स्थित हों सम्मिलित होंगे अथवा ऐसे भवन/स्थल जिनका प्रयोग धनोपार्जन हेतु किया जाना हो ।

29—संकटमय भवन के अन्तर्गत भवन या भवन के वह भाग सम्मिलित होंगे जिनमें अत्यधिक ज्वलनशील या विस्फोटक सामग्री या उत्पाद का संग्रहण, वितरण, उत्पादन या प्रक्रम (प्रोसेसिंग) का कार्य होता हो या जो अत्यधिक ज्वलनशील हो या जो ज्वलनशील भाप या विस्फोटक पैदा करता हो या जो अत्यधिक कारोसिव, जहरीली या खतरनाक क्षार, तेजाब हो या अन्य द्रव्य पदार्थ, रासायनिक पदार्थ जिनमें ज्वाला, भाप पैदा होती हो, विस्फोटक जहरीले इरीटेन्ट या कारोसिव गैसे पैदा होती हो या जिनमें धूल के विस्फोटक मिश्रण पैदा करने वाली सामग्री या जिनके परिणामस्वरूप ठोस पदार्थ छोटे-2 कणों में विभाजित हो जाता हो और जिनमें तत्काल ज्वलन प्रक्रिया प्रारम्भ हो जाती हो, के संग्रहण वितरण या प्रक्रम (प्रोसेसिंग) के लिए प्रयुक्त किया जाता हो ।

30—भवन गतिविधि/भवन निर्माण का तात्पर्य किसी भवन के बनाने या पुनः बनाने या उसमें सारवान विचलन या ध्वस्त करने की कार्यवाही मानी जायेगी ।

31—पार्किंग स्थल का तात्पर्य ऐसे चहारदीवारी में बंद या खुले स्थान से है, जहां पर वाहन इकट्ठे रूप में खड़े हो सकते हैं, परन्तु इसके लिए आवश्यक है, कि उक्त स्थान पर आने-जाने के लिए एक सुगम एवं स्वतंत्र जोड़ने वाला मार्ग बना हो ।

इन उपविधियों में जिन शब्दों का प्रयोग किया गया है, परन्तु वे उक्त परिभाषाओं में सम्मिलित नहीं हैं, का तात्पर्य वही होगा, जोकि ऐसे शब्दों का National building Code एवं Bureau of Indian standards के यथा संशोधित में माना जाता है । किसी विरोधाभास की स्थिति में अधिनियम के प्रावधान प्रभावी माने जायेंगे ।

### उपविधि

ये उपविधियां जिला पंचायत बॉदा के उक्त परिभाषित ग्रामीण क्षेत्र में जोकि इन उपविधियों के लिए परिभाषित किया गया है, में किसी भी व्यक्ति, ठेकेदार कंपनी, फर्म या संस्था, सहकारी समिति, सोसाईटी, राजकीय विभाग द्वारा निर्माण कराये जाने वाले आवासीय, व्यावसायिक, औद्योगिक भवन, शिक्षण संस्थान, फार्म हाउस, गुप हाऊसिंग, दुकानों, मार्केट, धर्मार्थ अथवा जनहितार्थ भवन इत्यादि का ले-आउट प्लान एवं/या भवन प्लान एवं निर्मित भवनों में परिवर्तन, परिवर्धन, विस्तार को नियन्त्रित एवं विनियमित करने की उपविधियां कहलायेंगी ।

### (क) नक्शा स्वीकृत न कराने की परिस्थितियां

ऐसे प्रकरण/निर्माण कार्य जिनमें उपविधियों के अन्तर्गत नक्शा स्वीकार कराना आवश्यक नहीं होगा ।

1—उक्त परिभाषित ग्राम्य क्षेत्र में निम्नलिखित परिस्थितियों में भवन निर्माण, परिवर्तन, विस्तार की स्वीकृति हेतु प्रार्थना-पत्र की आवश्यकता नहीं होगी ।

(अ) ये उपविधियां कच्चे मकानों एवं गांव के मूल निवासी के शुद्धतया निजी आवास/कृषि कार्य हेतु बनाये जाने वाले 300 वर्गमी0 क्षेत्रफल एवं दो मंजिल तक ऊँचे आवासीय भवनों पर लागू नहीं होंगी परन्तु सुरक्षित डिजाईन व निर्माण की जिम्मेदारी मालिक की होगी एवं उक्त निर्माण/कार्यवाही करने से पूर्व जिला पंचायत को एक लिखित सूचना देनी होगी ।

(ब) सफेदी व रंग-रोगन के लिए ।

(स) प्लास्टर व फर्श मरम्मत के लिए ।

(द) पूर्व स्थान पर छत पुनर्निर्माण के लिए ।

(य) प्राकृतिक आपदा से क्षतिग्रस्त भवन के हिस्से का पुनर्निर्माण ।

(र) मिट्टी खोदने या मिट्टी से गड़ढा भरना ।

### (ख) प्रार्थना-पत्र, भू-अभिलेख व नक्शें

उक्त ग्राम्य क्षेत्र में कोई भी नया निर्माण, पुराने भवन में परिवर्तन या परिवर्धन विस्तार या भू-खण्ड के ले-आउट की स्वीकृति का आशय रखने वाला स्वामी, इन उपविधियों के अनुसार ऐसा करने से एक माह पहले अपर

मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत को एक आवेदन-पत्र के साथ निम्नलिखित अभिलेख तथा सूचनायें प्रस्तुत करेगा एवं पावती रसीद प्राप्त करेगा।

1—स्थल का नक्शा निम्नवत् दिया जायेगा—

ले-आउट प्लान का पैमाना 1 : 500 होगा ।

की-प्लान का पैमाना 1 : 1000 होगा ।

बिल्डिंग प्लान का पैमाना 1 : 100 होगा ।

स्थल के चारों तरफ की सीमायें उनके नाम तथा समीपवर्ती भूमि का संक्षिप्त विवरण तथा भूमि मालिक का नाम।

समीपवर्ती मार्ग अथवा मार्गों का विवरण तथा निर्माणाधीन भवन से मार्ग की दूरी ।

स्थल के नक्शे के साथ भूमि के स्वामित्व का प्रमाण-पत्र जैसे विक्रय आलेख, दाखिल खारिज, खतौनी आलेख।

2—प्रस्तावित भवन/परियोजना का नक्शा उपरोक्त वर्णित पैमाने के अनुसार होगा ।

(अ) प्रत्येक मंजिल के ढके हुए भाग का नक्शा विवरण सहित ।

(ब) नक्शे पर पंजीकृत वास्तुविद का पंजीकरण नंबर, नाम व पता सहित हस्ताक्षर ।

(स) नक्शे पर भू-स्वामी अथवा स्वामियों के नाम व पता सहित हस्ताक्षर ।

(य) भू-स्वामी अथवा स्वामियों द्वारा नक्शा स्वीकृति के लिये प्रार्थना-पत्र ।

(र) भवन/परियोजना के बनाने व उपयोग का उद्देश्य जैसे आवासीय, व्यवसायिक, शिक्षण, धर्मार्थ अथवा जनहितार्थ भवन ।

(ल) स्थल का की-प्लान, ले-आउट प्लान, फ्लोर-प्लान, एलिवेशन, भवन की ऊँचाई, सेक्सन, स्ट्रक्चर विवरण, रैन हार्वेस्टिंग प्रणाली, बेसमेंट, लैंडस्केप प्लान, वातानुकूलित प्लांट, सीवेज-जल निस्तारण व्यवस्था अग्नि निकास जीने की स्थिति व अन्य विवरण ।

(व) नक्शे पर परियोजना का नाम, शीर्षक, भू-खण्ड का खसरा, ग्राम, तहसील सहित पूरा पता ।

(श) नक्शे पर भू-खण्ड का क्षेत्रफल, ग्राउंड कवरेज, हर तल का क्षेत्रफल, बेसमेंट का क्षेत्रफल आदि का विवरण ।

3—बहु मंजिली भवन (मल्टी स्टोरी ) चार मंजिल अथवा 15 मीटर से अधिक ऊँचाई के भवन में नक्शे पर निम्नलिखित अतिरिक्त सूचना भी देनी होगी—

अग्निशमन प्रणाली की व्यवस्था आपात सीढ़ी व निकासी, अग्निसुरक्षा लिफ्ट अग्निअलार्म आदि का विवरण व ठिकाने (Location) ।

निर्माण कार्य एवं निर्माण में उपयोग की जाने वाली सामग्री की विशिष्टियाँ आदि ।

### (ग) नक्शा स्वीकृति प्रदान न करने की परिस्थितियाँ

निम्नलिखित परिस्थितियों में भवन निर्माण, परिवर्तन, विस्तार की किसी भू-खंड पर स्वीकृति प्रदान नहीं की जायेगी यदि

अ—प्रस्तावित भवन—उपयोग अनुमन्य भू-उपयोग से भिन्न है।

ब—प्रस्तावित निर्माण धार्मिक प्रकृति का है और उससे किसी समाज की धार्मिक भावनाएं आहत होती हो ।

स—प्रस्तावित निर्माण का उपयोग लोगों की भावनाएं भड़काने का स्रोत (Source Of Annoyance) अथवा आस-पास रहने वालों के स्वास्थ्य पर दुष्प्रभाव डालता हो ।

### (घ) तकनीकी अनुदेश (Technical Instructions)

1—(क) एक आवास गृह में 4.5 व्यक्ति प्रति गृह माना (Consider) गया है ।

(ख) भवन के भू-तल पर स्टिल्ट पार्किंग (Stilt Parking) अधिकतम 2.4 मीटर ऊँचाई तक अनुमन्य होगी ।

(ग) लिंटल (Lintel) अथवा छत स्तर पर छज्जा अधिकतम क्रमशः 0.45 मीटर एवं 0.75 मीटर चौड़ा होगा ।

(घ) बेसमेंट का निर्माण भवन की सीमा से बाहर नहीं किया जायेगा। बेसमेंट की फर्श से सीलिंग तक की अधिकतम ऊँचाई 4.5 मीटर तथा बाहर की नाली से बेसमेंट की अधिकतम ऊँचाई 1.5 मीटर होगी। स्ट्रेक्चर स्थिरता के आधार पर बेसमेंट सन्निकट (Adjacent) प्लॉट से 2.0 मीटर दूरी तक निर्मित किया जा सकता है।

(ङ) बहु मंजिली भवन में कम से कम एक सामान (Good)/मालवाहक लिफ्ट का प्रावधान करना होगा।

(च) राष्ट्रीय भवन संहिता (National Building Code) 2005 के प्राविधान के अनुसार ग्रुप हाउसिंग के दो ब्लॉक में न्यूनतम 6.0 मीटर से 16.0 मीटर की दूरी होगी। भवन की 18.0 मीटर ऊँचाई तक 6.0 मीटर इसके पश्चात् प्रत्येक 3.0 मीटर अतिरिक्त ऊँचाई के लिए ब्लॉक की दूरी 1.0 मीटर बढ़ाई जाएगी। भूखंड के डैड एन्ड (Dead End) पर ब्लॉक की अधिकतम दूरी 9.0 मीटर होगी।

(छ) बहु मंजिली भवन में चार तलों के बाद एक सेवा तल अनुमन्य होगा। किसी भवन में अधिकतम 3 सेवा तल का प्रावधान किया जा सकता है, सेवा तल की अधिकतम ऊँचाई 2.4 मीटर होगी।

2-निम्नलिखित निर्माण/सुविधाओं के लिये भूखंड का 10: क्षेत्रफल, भू-आच्छादन (Ground Coverage) में अतिरिक्त जोड़ा जा सकता है—

(क) जेनरेटर कक्ष, सुरक्षा मचान, सुरक्षा केबिन, गार्ड रूम, टॉयलेट ब्लॉक, ड्राईवर रूम, विद्युत उप केन्द्र आदि।

(ख) मम्टी, मशीन रूम, पम्प हाउस, जल-मल प्लांट।

(ग) ढके हुए पैदल पथ आदि।

3-(क) आवासीय भवन में कमरे का आकार 2.4 मीटर एवं 9.5 वर्ग मीटर से कम न होना चाहिए।

(ख) छत की सीलिंग की ऊँचाई 2.75 मीटर से कम न होनी चाहिए।

(ग) ए०सी० कमरे की ऊँचाई 2.40 मीटर से कम न होनी चाहिए।

(घ) रसोईघर की ऊँचाई 2.75 मीटर, आकार 1.80 मीटर एवं 5.00 वर्ग मीटर से कम न होना चाहिए।

(ङ) संयुक्त संडास (जम्सज) का आकार 1.20 मीटर एवं 2.20 वर्ग मीटर से कम न होना चाहिए।

(च) खिड़की व रोशनदान का क्षेत्रफल फर्श के क्षेत्रफल का 10: से कम न होना चाहिए।

(छ) तीन मंजिल तक के भवन में सीढ़ी की चौड़ाई 1.00 मीटर एवं इससे अधिक ऊँचे भवन में 1.50 मीटर से कम न होनी चाहिए।

4-(क) पार्क, टोट-लोट्स (ज्वज.स्वजे), लैंड स्केप (संदकेबंचम) आदि का क्षेत्रफल भूखंड के क्षेत्रफल का 15: होगा।

(ख) 30 मीटर तक के मार्ग पर स्थित समस्त प्रकार के भवनों की अधिकतम ऊँचाई सड़क की विद्यमान चौड़ाई तथा अनुमन्य फ्रंट सेट-बैक के योग का डेढ़ गुना होगी।

(ग) भूकम्प रोधी व सुरक्षित डिजाईन की जिम्मेदारी वास्तुविद एवं उसके अन्तर्गत कार्यरत डिजाईनर की होगी।

5-स्वीकृत किये गये भवन में जल आपूर्ति एवं मल-मूत्र एवं बेकार पानी के निस्तारण (क्वेचवेंस) की व्यवस्था स्वामी द्वारा स्वयं की जायेगी जिला पंचायत का इसके लिए कोई उत्तरदायित्व व्यय अधिभार नहीं होगा।

6-बेसमेंट में इलेक्ट्रिक ट्रान्सफार्मर की स्थापना, ज्वलनशील, विस्फोटक सामग्री आदि का भण्डारण नहीं किया जा सकेगा।

### (ङ) रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम

भवन एवं पक्की सड़कों के द्वारा भूखंड के प्रत्येक 300 वर्ग मीटर के भू-आच्छादन (Ground Coverage) पर एक रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम होगा। प्रत्येक 1000 वर्ग मीटर के भू-आच्छादन (Ground Coverage) पर एक अतिरिक्त रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करना होगा।

### (च) विकसित जनपदों की सूची (1)

लखनऊ, गौतमबुद्ध नगर, गाजियाबाद, मेरठ, आगरा, कानपुर नगर, वाराणसी, मथुरा, इलाहाबाद, बरेली, सहारनपुर, अलीगढ़, गोरखपुर, मुरादाबाद, हापुड, भामली, मुजफ्फरनगर एवं झांसी।

## (छ) भू-आच्छादन एवं फ्लोर एरिया रेशियो (FAR)

विभिन्न भवनों हेतु भू-आच्छादन एवं फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) के मानक निम्नवत होंगे—

क्र० सं०	भवन एवं भू-उपयोग	भू-आच्छादन	फ्लोर एरिया रेशियो (FAR)	भवन की अधिकतम ऊँचाई सूची (1) के अनुसार जनपदों में	भवन की अधिकतम ऊँचाई अन्य जनपदों में
1	2	3	4	5	6
		प्रतिशत		मीटर	मीटर
1	(i) आवासीय भवन भू-खण्ड 500 वर्ग मीटर तक	80	3.00	15	15
	(ii) आवासीय भवन भू-खण्ड 500-2000 वर्ग मीटर तक	65	4.00	15	15
2	ग्रुप हाउसिंग योजना, रैन बसेरा (Night Shelter)	50	3.00	30	21
3	औद्योगिक भवन	60	1.00	18	12
4	व्यवसायिक भवन				
	(i) सुविधा (Convenient) शॉपिंग केंद्र, शॉपिंग माल्स, व्यवसायिक केंद्र, होटल	40	2.50	30	21
	(ii) बैंक, सिनेमा, मल्टीप्लेक्स,	40	1.50	24	18
	(iii) वेयरहाउस, गोदाम	60	1.50	18	15
	(iv) दुकाने व मार्केट	60	1.50	15	10
5	संस्थागत एवं शैक्षणिक भवन				
	(i) सभी उच्च शिक्षण संस्थान, विश्वविद्यालय, अनुसंधान एवं प्रशिक्षण संस्थान, डिग्री कॉलेज आदि	50	1.50	24	15
	(ii) हायर सेकंडरी, प्राइमरी, नर्सरी स्कूल, क्रेच सेंटर आदि	50	1.50	24	15
	(iii) हॉस्पिटल, डिस्पेंसरी, चिकित्सालय, लैब, नर्सिंग होम आदि	75	2.50	24	15
6	धर्मार्थ अथवा जनहितार्थ भवन	50	1.20	15	10
(i)	सामुदायिक केंद्र क्लब, बारात घर, जिमखाना, अग्निशमन केंद्र, डाकघर, पुलिस स्टेशन	30	1.50	15	10
(ii)	धर्मशाला, लॉज, अतिथिगृह, हॉस्टल	40	2.50	15	10
(iii)	धर्मकांटा, पेट्रोल पम्प, गैस गोदाम, शीत गृह	40	0.50	10	6
7	कार्यालय भवन				
	सरकारी, अर्धसरकारी, कारपोरेट एवं अन्य कार्यालय भवन	40	2.00	30	15
8	क्रीडा एवं मनोरंजन कॉम्प्लेक्स, शूटिंग रेंज, सामाजिक एवं सांस्कृतिक केंद्र	20	0.40	15	10
9	नर्सरी	10	0.50	6	6
10	बस स्टेशन, बसडिपो, कार्यशाला	30	2.00	15	12
11	फार्म हाउस	10	0.15	10	6
12	डेयरी फार्म	10	0.15	10	6
13	मुर्गा, सूअर, बकरी फार्म	20	0.30	6	6
14	ए० टी० एम०	100	1.00	6	6

## (ज) सेट बेक (set back)

क्रमांक	भू-खण्ड का क्षेत्रफल	सामने (Front)	साईड (side)	पीछे (Rear)	लैंड स्केपिंग (landscaping)	खुला स्थान % तक
1	2	3	4	5	6	7
	वर्ग मीटर	मीटर	मीटर	मीटर		
1	150 तक	3.0	0.0	1.5	एक वृक्ष प्रति 100 वर्ग मीटर	25
2	151-300	3.0	0.0	3.0	तदैव	25
3	301-500	4.5	3.0	3.0	तदैव	25
4	501-2000	6.0	3.0	3.0	तदैव	25
5	2001-6000	7.5	4.5	6.0	तदैव	25
6	6001-12000	9.0	6.0	6.0	तदैव	25
7	12001-20000	12.0	7.5	7.5	तदैव	50
8	20001-40000	15.0	9.0	9.0	तदैव	50
9	40001 से अधिक	16.0	12.0	12.0	तदैव	50

## (झ) पार्किंग स्थान

क्रमांक	भवन/भू-वर्ग मीटर भू-खण्ड	पार्किंग स्थान ECU (Equivalent Car Unit)
1	ग्रुप हाउसिंग योजना	एक ECU प्रति 80 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
2	संस्थागत एवं शैक्षणिक भवन	एक ECU प्रति 100 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
3	औद्योगिक भवन	एक ECU प्रति 100 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
4	व्यवसायिक भवन	एक ECU प्रति 30 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
5	समाजिक एवं सांस्कृतिक केन्द्र	एक ECU प्रति 50 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
6	लाज, अतिथिगृह, हास्टल	एक ECU प्रति 2 अतिथि रुम के लिये
7	हॉस्पिटल, नर्सिंग होम	एक ECU प्रति 65 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का
8	सिनेमा, मल्टीप्लेक्स	एक ECU प्रति 15 सीट्स
9	आवासीय भवन	एक ECU प्रति 150 वर्ग मीटर स्वीकृत (FAR) का

## (अ) अग्नि शमन पद्धति, अग्नि सुरक्षा एवं सर्विसिंग

(i)--तीन मंजिल अथवा 15 मीटर से अधिक ऊँचे भवनों और विशिष्ट भवन यथा--संस्थागत एवं शैक्षणिक भवन व्यावसायिक भवन हॉस्पिटल, नर्सिंग होम सिनेमा, मल्टीप्लेक्स 400 वर्ग मीटर से अधिक भू-आच्छादन के भवन में अग्नि निकास हेतु एक जीना बाहर की दीवार पर एवं अग्नि सुरक्षा के अन्य सभी प्रावधान करने होंगे। भवन के चारो तरफ बाउन्ड्री दीवार के साथ-साथ 6 मीटर चौड़े मार्ग का प्रावधान करना होगा। जिसमें दमकलों के चालन हेतु कम से कम 4 मीटर चौड़ाई का परिवहन मार्ग (Carriage Way) होगा।

(ii)--अग्नि निकास जीने की न्यूनतम चौड़ाई 1.2 मीटर, ट्रेड की न्यूनतम चौड़ाई 28 से०मी०, राईजर अधिकतम 19 से०मी०, एक फ्लाइंट में अधिकतम राईजरों की संख्या 16 तक सीमित होगी।

(iii)--अग्नि निकास जीने तक पहुँच दूरी 15 मीटर से अधिक न होनी चाहिए !

(iv)--घुमावदार अग्नि निकास जीने का प्रावधान 10 मीटर से अधिक ऊँचे भवनों में नहीं किया जायेगा।

(v)—उपरोक्त भवनों हेतु अग्नि शमन विभाग के सक्षम प्राधिकारी से अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्राप्त करने की जिम्मेदारी भवन स्वामी की होगी ।

(vi)—उपरोक्त भवनों में उत्तर प्रदेश अग्नि निवारण और अग्नि सुरक्षा अधिनियम (6) 2005 एवं राष्ट्रीय भवन संहिता (National Building Code) 2005 भाग-4 के अनुसार प्रावधान किया जायेगा जैसे स्वचालित स्प्रिंकलर पद्धति, फर्स्ट एंड होज रील्स, स्वचालित अग्नि संसूचन और चेतावनी पद्धति, सार्वजनिक संबोधन व्यवस्था, निकास मार्ग के संकेत चिन्ह, फायर मैन स्विच युक्त फायर लिफ्ट, वैट राइजर डाउन कॉर्नर सिस्टम आदि ।

#### (ट) इलेक्ट्रिक लाईन से दूरी

क्रमांक	विवरण	उर्ध्वाकार दूरी मीटर	क्षैतिज दूरी मीटर
1	लो एंड मीडियम वोल्टेज लाईन तथा सर्विस लाईन	2.4	1.2
2	हाई वोल्टेज लाईन 33000 वोल्टेज तक	3.7	1.8
3	एक्स्ट्रा हाई वोल्टेज लाईन	3.7+(0.305 m ) प्रत्येक अतिरिक्त 33000 वोल्टेज पर	1.8+(0.305 m ) प्रत्येक अतिरिक्त 33000 वोल्टेज पर

#### (ठ) मोबाइल टावर की स्थापना

क—मोबाइल टावर की स्थापना हेतु भवन स्वामी/भू-स्वामी एवं आवासीय कल्याण समिति (RWA) की अनापत्ति प्रस्तुत करनी होगी ।

ख—जनरेटर केवल 'साइलेंट' प्रकृति के होंगे तथा भू-तल पर ही लगाये जायेंगे ।

ग—यदि टावर का निर्माण भवन की छत पर किया जाता है तो टावर का निचला भाग भवन की छत से न्यूनतम 3 मीटर ऊपर होना चाहिए ।

घ—जहाँ अपेक्षित हो, वहाँ टावर के निर्माण से पूर्व एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इण्डिया/वायुसेना का अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा ।

ङ—सेवा ऑपरेटर कंपनी और भवन स्वामी को संयुक्त हस्ताक्षर से इस आशय का शपथ-पत्र प्रस्तुत करना होगा कि यदि टावर निर्माण के फलस्वरूप आस-पास के भवन एवं जान-माल को किसी भी प्रकार की क्षति पहुँचती है तो उसकी क्षतिपूर्ति का समस्त दायित्व सम्बंधित कंपनी और भवन स्वामी/भू-स्वामी का होगा ।

च—इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, रेडियो विकिरण, वायुब्रेसन (कम्पन) आदि के रूप में होने वाले दुष्परिणामों के नियंत्रण हेतु भारत सरकार/राज्य सरकार अथवा अन्य शासकीय अभिकरण द्वारा जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन करना अनिवार्य होगा ।

छ—अनुज्ञा पत्र जारी करने के लिये सूची (1) के अनुसार जनपदों में प्रथम बार शुल्क के रूप में एक लाख रुपये व अन्य जनपदों में पचास हजार रुपये जिला पंचायत में जमा कराने होंगे। यह शुल्क एक वर्ष की अवधि के लिए होगा तथा अप्रत्यापणीय (Non- Refundable) होगा । अनुज्ञा के नवीनीकरण के लिए प्रथम बार की शुल्क का 10: प्रति वर्ष जमा कराने होंगे।

ज—शैक्षणिक संस्था, हास्पिटल, अधिक घनत्व वाली आवासीय बस्ती, अथवा धार्मिक भवन/स्थल आदि पर या इनके 100 मीटर के दायरे में मोबाइल टावर की स्थापना नहीं की जायेगी ।

#### (ड) नक्शे स्वीकृति की दरें

क—आवासीय भवन एवं शैक्षणिक भवन

सूची (1) के अनुसार जनपदों में—सभी तलों पर फर्श से ढके भाग पर रुपये 50 प्रति वर्ग मीटर, अन्य जनपदों में यह दर 25 रुपये प्रति वर्ग मीटर होगी।

ख—व्यवसायिक एवं व्यापारिक भवन

सूची (1) के अनुसार जनपदों में—सभी तलों पर फर्श से ढके भाग पर 100 रुपये प्रति वर्ग मीटर, अन्य जनपदों में यह दर 50 रुपये प्रति वर्ग मीटर होगी ।

ग—(i) भूमि की प्लानिंग—भूमि को योजनाबद्ध तरीके से विभिन्न आकार के प्लानों में बाँटना ।

(ii) भूमि विकास—भूमि पर योजनाबद्ध तरीके से पार्क, उद्यान बनाना, फार्म हाउस विकसित करना, नर्सरी लगाना, शादी बैंकट हाल आदि ।

(iii) भूमि का उपभोग—भूमि का विभिन्न प्रकार के सामानों के भण्डारण हेतु प्रयोग करना जैसे निर्माण सामग्री, कंटेनर, ईंधन आर०सी०सी०पाईप आदि ।

(iv) किसी परियोजना का ले आउट प्लान (तलपट मानचित्र)

उपरोक्त ग—(i) से (iv) तक, सूची (1) के अनुसार जनपदों में 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर, अन्य जनपदों में यह दर 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर होगी ।

घ—पुराने भवन को ध्वस्त करने के पश्चात् पुनः निर्माण करने की दशा में अनुज्ञा शुल्क की दरें नये भवन की दरों के समान होंगी ।

ङ—स्वीकृत भवन के नक्शे में संशोधन होने की दशा में अनुज्ञा शुल्क की दरें नये भवन की दरों की एक चौथाई होंगी ।

च—बेसमेंट, स्टिल्ट, पोडियम, सेवा क्षेत्र व अन्य आच्छादित क्षेत्र की, अनुज्ञा शुल्क में गणना की जाएगी ।

छ—यदि स्वीकृति के नवीनीकरण का आवेदन, अनुज्ञा अवधि समाप्ति से पूर्व किया जाता है तो स्वीकृति के नवीनीकरण की दरें मूल दरों की 10% होंगी । एक बार में अनुज्ञा की अवधि एक वर्ष व अधिकतम दो वर्ष तक बढ़ाई जा सकती है । अनुज्ञा अवधि समाप्ति के पश्चात् नवीनीकरण की दरें मूल दरों की 50% होंगी ।

ज—उपविधियों के अनुसार, जिला पंचायत से नक्शों की स्वीकृति के बिना निर्माण करने, किसी भूमि पर व्यवसाय करने, स्वीकृत नक्शे से इतर निर्माण करने, अथवा जिला पंचायत भवन उपविधि की किसी धारा या उपधारा का उल्लंघन करने पर अर्थ—दण्ड के रूप में समझौता शुल्क (Compounding Fees) रोपित किया जायेगा । समझौता शुल्क (Compounding Fees) प्रस्तावित भवन अथवा ले आउट प्लान (तलपट मानचित्र) पर परिस्थिति अनुसार, कुल शुल्क की गणना का कम से कम 20% से अधिकतम 50% अतिरिक्त होगा । समझौता शुल्क (Compounding Fees) विभाग में जमा होने के उपरांत पूर्व में निर्मित भवन के नक्शे की स्वीकृति प्रदान की जा सकती है । समझौते की कार्यवाही अधिनियम की धारा 248 में दी गयी व्यवस्था से नियन्त्रित होगी ।

झ—सूची (1) के अनुसार जनपदों में पूर्णता प्रमाण पत्र (Completion Certificate) जारी करने की दरें 20 रुपये प्रति वर्ग मीटर व अन्य जनपदों में 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर होगी । ये दरें सभी तलों के कुल आच्छादित क्षेत्रफल पर लागू होंगी ।

ञ—सूची (1) के अनुसार जनपदों में बाउन्ड्री वाल स्वीकृति की दरें 10 रुपये प्रति मीटर व्यय अन्य जनपदों में 5 रुपये प्रति मीटर होगी ।

नोट—(शुल्क निर्धारण हेतु, भवन के सभी तलों पर फर्श के कुल क्षेत्रफल की गणना करनी होगी)

### (ण) अनुज्ञा-पत्र जारी करने की प्रक्रिया

1—स्वामी द्वारा आवेदन पत्र के साथ प्रस्तावित भवन/परियोजना के नक्शे एवं स्वामित्व के भू-अभिलेख अपर मुख्य अधिकारी जिला पंचायत के कार्यालय में जमा किये जायेंगे एवं आवेदक को इस प्रस्तुतिकरण की दिनांकित पावती दी जायेगी ।

2—ऐसे आवेदन-पत्र एवं उसके साथ संलग्नकों को अपर मुख्य अधिकारी तत्काल कार्य अधिकारी को भू-अभिलेखों के परीक्षण हेतु पृष्ठांकित कर देगा ।

3—कार्य अधिकारी ऐसे प्राप्त आवेदन पर उपरोक्त कार्यवाही पूर्ण करके अधिकतम एक सप्ताह में सम्बन्धित अभिलेख अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत को प्रस्तुत कर देगा। कार्य अधिकारी की तैनाती न होने की दशा में उपरोक्त कार्यवाही अपर मुख्य अधिकारी द्वारा स्वयं की जायेगी।

4—कार्य अधिकारी से प्राप्त आख्या को अपर मुख्य अधिकारी तत्काल अभियंता, जिला पंचायत को पृष्ठांकित कर देगा।

5—अभियंता द्वारा प्रस्तावित परियोजना के स्थलीय सर्वेक्षण हेतु निदेशित (Designated) अवर अभियंता को स्थल के सर्वेक्षण हेतु आदेशित किया जायेगा।

6—अवर अभियंता द्वारा स्थल सर्वेक्षण की आख्या अधिकतम एक सप्ताह में अभियंता, जिला पंचायत को प्रस्तुत की जायेगी।

7—अवर अभियंता से सर्वेक्षण आख्या प्राप्त होने के उपरान्त बहुमंजिली भवन, व्यवसायिक भवन, संकटमय भवन एवं शैक्षणिक भवन अथवा अन्य महत्वपूर्ण परियोजना के नक्शा पारित करने से पहले अभियंता जिला पंचायत द्वारा प्रस्तावित परियोजना के स्थल का सर्वेक्षण अनिवार्य होगा।

8—अभियंता द्वारा स्थल की सर्वेक्षण आख्या प्रस्तुत करने के उपरांत सर्वेक्षण आख्या का परीक्षण किया जायेगा। परियोजना के नक्शों की स्वीकृति हेतु अवर अभियंता से एक अंतरिम शुल्क की गणना करके अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत को सूचित किया जायेगा। आवेदक द्वारा आंगणित अन्तरिम शुल्क की 20 प्रतिशत धनराशि अग्रिम रूप से नोटिस प्राप्त होने के एक सप्ताह के अन्दर कार्यालय जिला पंचायत में जमा करनी होगी। इसके उपरान्त ही नक्शे के विषय में अग्रिम कार्यवाही की जायेगी। प्रतिबंध यह है कि नक्शा पारित होने के स्तर पर आवेदक मांग-पत्र के अनुसार निर्धारित अवधि में यदि शुल्क जमा करता है, तो उक्त धनराशि समायोजित (Adjust) हो जायेगी। अन्यथा की दशा में जमा धनराशि जब्त हो जायेगी।

9—जिला पंचायत के अभियंता द्वारा परियोजना की संभाव्यता (Possibility), सुगमता (Convenience), साध्यता (Feasibility), तकनीकी जांच व जिला पंचायत भवन उपविधि में तकनीकी प्रावधानों एवं नक्शों का परीक्षण किया जायेगा। आवश्यकता समझने पर नक्शों में संशोधन हेतु आवेदन-कर्ता को निर्देशित किया जायेगा।

10—अभियंता द्वारा परियोजना तकनीकी दृष्टि से सुस्थित (Sound) पाये जाने पर अपनी तकनीकी आख्या अपर मुख्य अधिकारी को अधिकतम 15 दिन में प्रस्तुत करनी होगी। अवर अभियंता से आंगणित शुल्क की धनराशि का विवरण प्रतिपरीक्षण (Cross Verification) कराके तकनीकी आख्या के साथ संलग्न करना होगा।

11—अपर मुख्य अधिकारी उक्त आख्या प्राप्त होने पर कार्य अधिकारी एवं अभियंता द्वारा प्राप्त आख्याओं का परीक्षण करके आवेदक को शुल्क जमा करने का मांग-पत्र जारी करेंगे। जिसमें आवेदक को शुल्क जमा करने के लिये एक माह का समय दिया जायेगा।

12—आवेदक द्वारा नक्शा शुल्क निर्धारित समय में जमा कराना होगा। जिला निधि की रोकड़ बही में शुल्क की प्रविष्टि के उपरांत अपर मुख्य अधिकारी द्वारा नक्शे की स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

13—उपरोक्त समस्त कार्यवाही पूर्ण होने के उपरान्त आवेदक को अनुज्ञा-पत्र अपर मुख्य अधिकारी एवं अभियंता के संयुक्त हस्ताक्षर से आवश्यक शर्तों के साथ जारी किया जायेगा। नक्शों पर अपर मुख्य अधिकारी एवं अभियंता द्वारा संयुक्त हस्ताक्षर से स्वीकृति प्रदान की जायेगी।

14—यदि जिला पंचायत द्वारा आवेदन प्राप्ति के दो माह के भीतर आवेदक को कोई सूचना अथवा शुल्क की मांग पत्र जारी नहीं किया जाता है, तो आवेदक द्वारा निर्धारित दो माह की अवधि के समाप्ति के दिनांक से 20 दिन के भीतर प्रकरण अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत के संज्ञान में लिखित रूप से लाया जायेगा। यदि इस पर भी अपर मुख्य अधिकारी 10 दिन में कोई कार्यवाही नहीं करता है, तो पूर्व में प्रस्तुत नक्शा एवं निर्माण की स्वीकृति मानित स्वीकृति (Deemed Sanction) मानी जायेगी।



विवाद—उक्त कार्यवाही में किसी विवाद होने की दशा में या स्वीकृत नक्शा किन्हीं कारणों से निरस्त होने की दशा में या ऐसी कार्यवाही उत्पन्न होने के दिनांक से 30 दिन के भीतर प्रकरण अध्यक्ष, जिला पंचायत को संदर्भित किया जायेगा। जिसमें उनको अपना अनुदेश ऐसे प्रकरण की प्राप्ति के 30 दिन के भीतर देना होगा एवं उनका ये आदेश उभयपक्षों पर बाध्यकारी होगा।

### (त) सामान्य अनुदेश (General Instructions)

1—भारत सरकार अथवा उत्तर प्रदेश सरकार एवं पुरातत्व विभाग द्वारा संरक्षित ऐतिहासिक स्मारक, इमारत या स्थल के 200 मीटर के दायरे में निर्माण की अनुमति नहीं दी जायेगी। 200 मीटर से 1.5 किलो मीटर के दायरे में निर्माण की मंजिलों एवं ऊँचाई की अनुमति, तत्समय आवश्यक और उचित कारण सहित दी जायेगी।

2—भू-खंड की सीमा से बाहर कोई निर्माण अनुमन्य नहीं होगा।

3—भवन के भू-तल पर स्टिल्ट पार्किंग (Stilt Parking) वाहन पार्किंग, बेसमेंट वाहन पार्किंग, भंडारण व सुविधाओं के रख रखाव व सेवा तल (Service Floor) भंडारण व सुविधाओं के रख-रखाव इत्यादि हेतु उपयोग किया जाये तो इनका क्षेत्रफल एफ०ए०आर० में शामिल नहीं होगा।

4—निकटतम हवाई अड्डा चाहे विमानापत्तम प्राधिकरण (Airport Authority) द्वारा नियन्त्रित हो या रक्षा विभाग अथवा अन्य शासकीय विभाग द्वारा नियंत्रित हो के 5 किमी० की परिधि में 30 मीटर से ऊँचे भवन के आवेदनकर्ता को उक्त वर्णित प्रतिष्ठानों से अनापत्ति प्रमाण-पत्र लेना होगा।

5—उपरोक्त उपविधि में सभी बातों के होते हुए भी जिला पंचायत यदि उचित व आवश्यक समझे तो कारणों का उल्लेख करते हुए किसी भवन में भू-आच्छादन, फ्लोर एरिया रेशियो (FAR) अथवा अधिकतम ऊँचाई में परिवर्तन की स्वीकृति प्रदान कर सकती है।

6—उपरोक्त सूची में उल्लिखित, भवनों के अतिरिक्त भवनों एवं गतिविधियों के नियमों व विनियमों का निर्धारण, जिला पंचायत द्वारा, इस प्रकार के समकक्ष (Similar) भवनों एवं गतिविधियों के लिए निर्धारित उपविधियों के अनुसार किया जायेगा।

7—मल्टी लेवल पार्किंग में संरचनात्मक एवं सुरक्षा की शर्तों के अधीन अधिकतम दो बेसमेंट अनुमन्य होंगे।

8—इन उपविधियों के आधीन जारी अनुज्ञा जारी होने के दिनांक से तीन वर्ष की अवधि के लिये वैध एवं मान्य होगी।

9—इन उपविधियों के पालन न करने की दशा में सम्बंधित उल्लंघनकर्ता के विरुद्ध सी०आर०पी०सी० की धारा 133 के अन्तर्गत जिला पंचायत द्वारा कार्यवाही की जायेगी।

### (थ) अनुज्ञा की शर्तें

अनुज्ञा-पत्र जारी होने के उपरांत यदि यह संज्ञान में आये की नक्शे स्वीकृति हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख फर्जी हैं अथवा गलत विवरण दिया गया है तो जिला पंचायत द्वारा दी गयी नक्शों की स्वीकृति निरस्त की जा सकती है, किया गया निर्माण ध्वस्त किया जा सकता है अथवा सील (Seal) किया जा सकता है।

क—अपर मुख्य अधिकारी को अधिकार होगा की वह अभियंता जिला पंचायत की संस्तुति पर, वास्तुविद द्वारा प्रस्तुत नक्शों में संशोधन अथवा परिवर्तन कर दे अथवा स्वीकार कर ले।

ख—पंजीकृत वास्तुविद द्वारा तैयार एवं हस्ताक्षरित नक्शे ही मान्य होंगे। परियोजना का डिजाईन वास्तुविद के अंतर्गत कार्य करने वाले योग्य अभियंता द्वारा कराया जायेगा।

ग—कोई भी व्यक्ति, कम्पनी, फर्म या संस्था, राजकीय विभाग अथवा ठेकेदार आदि द्वारा प्रस्तावित मानचित्र जिला पंचायत से स्वीकृत होने के बावजूद अन्य उन सभी विभागों से जिनसे लाईसेंस/अनापत्ति प्रमाण-पत्र लिया जाना आवश्यक है, अनुमति/अनापत्ति प्राप्त करने का उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

**(द) दण्ड**

उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत एवं जिला पंचायत अधिनियम 1961 की धारा 240 के अधीन प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए जिला पंचायत बाँदा यह निर्देश देती है कि जो व्यक्ति इन उपविधियों का उल्लंघन करेगा, वह अर्थ-दण्ड से दण्डनीय होगा। जो अंकन रु0 1,000.00 तक होगा, जो प्रथम दोष सिद्ध होने के पश्चात् ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जिसके बारे में यह सिद्ध हो जाये कि अपराधी अपराध करता रहा है, रु0 50.00 प्रतिदिन हो सकेगा, अथवा अर्थ-दण्ड का भुगतान न किया जाये तो कारावास से दण्डित किया जायेगा, जोकि तीन माह तक हो सकेगा।

ह0 (अस्पष्ट),  
आयुक्त,  
चित्रकूटधाम मण्डल,  
बाँदा।



# सरकारी गज़ट, उत्तर प्रदेश

## उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा प्रकाशित

प्रयागराज, शनिवार, 7 जनवरी, 2023 ई० (पौष 17, 1944 शक संवत्)

### भाग 8

सरकारी कागज-पत्र, दवाई हुई रुई की गांठों का विवरण-पत्र, जन्म-मरण के आंकड़े, रोगग्रस्त होने वालों और मरने वालों के आंकड़े, फसल और ऋतु सम्बन्धी रिपोर्ट, बाजार-भाव, सूचना, विज्ञापन इत्यादि।

### कार्यालय, नगर निगम, अयोध्या

27 जुलाई, 2021 ई०

### नगर निगम, अयोध्या सीमान्तर्गत तम्बाकू उत्पादों की बिक्री हेतु लाइसेंस शुल्क का निर्धारण, विनियमन और नियंत्रण एवं अनुज्ञप्ति शुल्क उपविधि, 2020

सं० 1210/न०नि०अयो०फै०/ला०शु०/2021-मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्र सं० 7862/3-18/06 (9-18) दिनांक 12 अक्टूबर, 2018 एवं यूपीवीएचए/टीसीपी/2018 दिनांक 04 नवम्बर, 2018 तथा अधिनियम कोटपा अधिनियम के अनुपालन में उत्तर प्रदेश नगर निगम अधिनियम, 1959 (उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 2 सन् 1959) की धारा-437, 438(1), 438-घ(2), 541, 542 एवं 543 में प्रदत्त अधिकारों के अन्तर्गत नगर निगम, अयोध्या सीमान्तर्गत तम्बाकू उत्पादों की बिक्री हेतु लाइसेंस शुल्क का निर्धारण विनियम और नियंत्रण एवं अनुज्ञप्ति शुल्क हेतु नगर निगम अधिनियम की धारा 541(20) के अन्तर्गत उपविधि, 2020 तैयार की गयी जो मा० सदन की कार्यकारणी समिति की बैठक दिनांक 11 जनवरी, 2021 प्रस्ताव सं० 2 के द्वारा स्वीकृति प्रदान की गयी। उपविधि के सम्बन्ध में 30 दिवस के अन्दर आपत्ति/सुझाव प्राप्त किये जाने हेतु 2 दैनिक समाचार-पत्र "हिन्दुस्तान" व "स्वतंत्र चेतना" में प्रकाशित कराया गया जिसका प्रकाशन दिनांक 27 जुलाई, 2021 को हो गया है। तदोपरान्त कुछ आपत्ति/सुझाव प्राप्त हुये जिनका निराकरण गठित टीम द्वारा किया जा चुका है। उक्त प्रस्ताव उ० प्र० के सरकारी गजट के प्रकाशित होने के दिनांक से लागू होगा।

### 1-संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ-

(1) यह उपविधि अयोध्या नगर निगम (तम्बाकू उत्पादों की बिक्री हेतु लाइसेंस शुल्क का निर्धारण विनियमन और नियंत्रण एवं अनुज्ञप्ति शुल्क) उपविधि, 2020 कही जायेगी।

(2) इसका विस्तार नगर निगम, अयोध्या के सम्पूर्ण क्षेत्र में होगा।

(3) यह उपविधि गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से प्रभावी होगी।

**2—तम्बाकू वेण्डर लाइसेंसिंग के लिये योग्यता—**

- (1) वह भारत का नागरिक हो।
- (2) आवेदनकर्ता की न्यूनतम उम्र 18 वर्ष या अधिक होनी अनिवार्य है।
- (3) दुकानदार के नाम का आधार कार्ड अनिवार्य है, अयोध्या से बाहर का आधार कार्ड होने की स्थिति में स्थानीय पार्षद से सत्यापन आवश्यक है।
- (4) आवेदनकर्ता की तम्बाकू की दुकान किसी भी शैक्षणिक संस्थान से 100 गज की परिधि में नहीं होनी चाहिये।
- (5) आवेदनकर्ता की दुकान स्थायी हो।
- (6) उक्त के अतिरिक्त नगर निगम सीमा के अन्तर्गत स्ट्रीट वेडिंग नीति के अन्तर्गत अस्थायी दुकान हो सकती है।

**3—वार्षिक पंजीकरण एवं नवीनीकरण शुल्क—**

- (1) तम्बाकू विक्रेताओं का पंजीकरण एक वर्ष के लिये ही मान्य होगा, तत्पश्चात् लाइसेंस का नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा। स्ट्रीट वेडिंग नीति के अन्तर्गत अस्थायी दुकानों हेतु वार्षिक पंजीकरण शुल्क रु0 200.00 स्थायी दुकानों हेतु रु0 1,000.00 एवं थोक स्थायी दुकानदारों के लिये रु0 5,000.00 होगा।
- (2) एक वर्ष के उपरान्त नवीनीकरण शुल्क थोक विक्रेता के लिये रु0 5,000.00 फुटकर स्थायी विक्रेताओं के लिये रु0 1,000.00 एवं फुटपाथ पर गुमटी और अस्थायी दुकानों हेतु रु0 200.00 होगा।
- (3) उक्त धनराशि आवेदनकर्ता द्वारा पंजीकरण के समय ही देय होगी।

**4—तम्बाकू नियंत्रण कानून एवं अधिनियम का अनुपालन—**

पंजीकृत तम्बाकू विक्रेताओं को निम्नलिखित का अनुपालन अनिवार्य होगा—

- (1) शैक्षणिक संस्थानों के 100 गज की परिधि में कोई भी तम्बाकू उत्पादन संचालित नहीं की जायेगी।
- (2) तम्बाकू विक्रेता द्वारा कोटपा की धारा-5 के अन्तर्गत साइनेज लगाना अनिवार्य होगा।
- (3) तम्बाकू विक्रेता कोटपा की धारा 6-अ के अनुसार नाबालिग तम्बाकू उत्पाद की न तो बिक्री करेगा और न ही नाबालिक द्वारा बिक्री करायी जायेगी।
- (4) दुकान पर खुली सिगरेट की बिक्री प्रतिबन्धित होगी।

**5—नियम व शर्तें—**

- (1) तम्बाकू विक्रेताओं का पंजीकरण एक वर्ष के लिये मान्य होगा। तत्पश्चात् लाइसेंस का नवीनीकरण कराना अनिवार्य होगा। बिना लाइसेंस के तम्बाकू उत्पाद नहीं बेचे जायेंगे।
- (2) पंजीकृत दुकानदार सिर्फ और सिर्फ तम्बाकू उत्पादों की ही बिक्री करेगा।
- (3) एक व्यक्ति एक लाइसेंस की प्रक्रिया अपनायी जायेगी, दिया गया लाइसेंस अहस्तांतरणीय होगा।
- (4) एक लाइसेंस एक दुकान के लिये मान्य होगा।
- (5) किन्हीं परिस्थितियों में केन्द्र सरकार, राज्य सरकार, माननीय न्यायालय, स्वास्थ्य विभाग, नगर निगम अथवा अन्य विभागों के द्वारा जारी नियम और कानून में कोई परिवर्तन अथवा संशोधन अथवा उसके दिशा निर्देश का अनुपालन पंजीकृत दुकानदारों द्वारा अनिवार्य होगा।
- (6) तम्बाकू उत्पाद की बिक्री हेतु देय लाइसेंस के नियमों के उल्लंघन होने की स्थिति में लाइसेंस धारक को पहले संबंधित अधिकारी द्वारा चेतावनी दे दी जायेगी। लाइसेंस धारक द्वारा उल्लंघन जारी रखने पर नगर निगम,

अयोध्या द्वारा निलंबन की कार्यवाही की जायेगी। फिर भी उल्लंघन जारी रखने की दशा में लाइसेंस रद्द किया जा सकता है। एक बार लाइसेंस रद्द होने पर दोबारा लाइसेंस होने की प्रक्रिया पर विचार नहीं किया जायेगा।

(7) तम्बाकू बिक्री लाइसेंस धारक के अतिरिक्त कोई अन्य कामर्शियल माल, थोक बाजार, बिग बाजार, स्पेन्सर्स, जनरल मर्चेन्ट, किराना दुकान आदि तम्बाकू उत्पादों की बिक्री नहीं कर पायेगा। इसमें वे दुकान भी सम्मिलित होगी जो गुमटी लगाते हैं उक्त के उल्लंघन होने पर प्रथम बार रु0 2,000.00 जुर्माना व सामग्री जब्त कर दूसरी बार रु0 5,000.00 व सामग्री जब्त तीसरी बार रु0 5,000.00 सामग्री जब्त व प्राथमिक दर्ज करायी जायेगी।

(8) लाइसेंस धारक बिक्रेता केवल भारतीय तम्बाकू उत्पादों जिस पर सचित्र चेतावनी अंकित होगी एवं भारत सरकार के आयात नियमों के अन्तर्गत आयातित तम्बाकू उत्पादों, की ही बिक्री करेगा।

#### 6-पंजीकरण प्रक्रिया-

(1) नगर निगम, अयोध्या में तम्बाकू उत्पादों के व्यापार एवं मानवीय इस्तेमाल पर निर्बन्धन और शर्तों के अनुरूप अनुज्ञप्ति लाइसेंस जारी करने के सम्बन्ध में जोनल अधिकारी नामित अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे, जो अपर नगर आयुक्त के निर्देशन में कार्य करेंगे।

(2) तम्बाकू विक्रेताओं को नगर निगम, अयोध्या के द्वारा निर्धारित आवेदन फार्म संख्या 22 पर जोनवार आवेदन करना होगा।

(3) प्राप्त आवेदनों को जांचोपरान्त सही पाये जाने पर पंजीकरण प्रमाण-पत्र दिया जायेगा।

(4) अपूर्ण आवेदन स्वतः निरस्त हो जायेंगे।

(5) प्रमाण-पत्र पर नामित अधिकारी के हस्ताक्षर के साथ बार कोड अथवा मोहर या होलोग्राम होगा।

(6) जारी प्रमाण-पत्र को दुकान पर चस्पा करना अनिवार्य होगा।

(7) पंजीकरण के संदर्भ में नगर निगम, अयोध्या द्वारा लिया गया निर्णय अन्तिम एवं मान्य होगा।

#### 7-नामित अधिकारी-

नगर निगम, अयोध्या में तम्बाकू उत्पादों के व्यापार एवं मानवीय इस्तेमाल पर निर्बन्धन और शर्तों के अनुरूप अनुज्ञप्ति लाइसेंस जारी करने हेतु पर्यावरण अभियन्ता प्रभारी अधिकारी होंगे। साथ ही जोनल अधिकारी नोडल अधिकारी के रूप में जोन स्तर पर उपरोक्त निर्बन्धन एवं शर्तों के अधीन आवेदन प्राप्त होने के 7 कार्य दिवस में अनुज्ञप्ति लाइसेंस जारी करेंगे जो अपर नगर आयुक्त के निर्देशन में कार्य करेंगे।

#### 8-वेण्डर लाइसेंस लागू करने की समयावधि-

पंजीकरण प्रणाली नगर निगम, अयोध्या के माननीय सदन में प्रेषित होने के बाद तत्काल प्रभाव से लागू मानी जायेगी।

ह0 (अस्पष्ट),  
नगर आयुक्त,  
नगर निगम, अयोध्या।

### कार्यालय नगर पंचायत कछौना पतसेनी, जनपद-हरदोई

16 अक्टूबर, 2022 ई0

सं0 387/न0पं0 कछौना/बायलॉज/2021-20-उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 128(1)व 126(10) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये नगर पंचायत कछौना पतसेनी, हरदोई ने अपनी बोर्ड बैठक 24 फरवरी, 2021 के द्वारा नगर पंचायत क्षेत्र की सीमा के अन्तर्गत आने वाले सभी भवनों, इमारतों तथा भूमियों पर गृहकर निर्धारण हेतु शासनादेश सं0-408/नौ-10-63ज/95टी0सी0 नगर विकास अनुभाग-9 दिनांक 22 फरवरी, 2010 व शासनादेश सं0-135/नौ-9-11-190-द्वि0रा0वि0आ0/04 लखनऊ दिनांक 18 मार्च, 2011 के अनुपालन में नगर पंचायत कछौना पतसेनी हरदोई की सीमान्तर्गत भवनों व सम्पत्तियों पर स्वकर प्रणाली के अंतर्गत गृहकर निर्धारण

किये जाने हेतु स्वमूल्यांकन व्यवस्था प्रभावी तथा संपत्तियों पर गृहकर निर्धारण नियमावली, 2019 बनायी गयी है जो दिनांक 17 अक्टूबर, 2021 को गुनाह का सच तथा दिनांक 18 अक्टूबर, 2021 को राष्ट्रीय सहारा में प्रकाशित की गयी है। निर्धारित अवधि में कोई भी आपत्ति नहीं प्राप्त हुई है। अतः यह उपविधि राष्ट्रीय गजट में प्रकाशन के दिनांक से प्रभावी होगी। उक्त उपविधि के सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को कोई आपत्ति/सुझाव हो तो अपनी आपत्ति/सुझाव नगर पंचायत कछौना पतसेनी, हरदोई के कार्यालय में विज्ञप्ति प्रकाशन के एक माह अर्थात् 30 दिन के भीतर लिखित रूप से प्रस्तुत कर सकते हैं। निर्धारित अवधि के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जायेगा।

### सम्पत्तियों पर गृहकर निर्धारण नियमावली, 2019

1—यह नियमावली नगर पंचायत कछौना पतसेनी, हरदोई की सीमा में स्थित भवनों तथा सम्पत्तियों पर गृहकर निर्धारण नियमावली, 2019 कही जायेगी।

2—यह नियमावली नगर पंचायत कछौना पतसेनी, हरदोई की सीमा में लागू होगी।

3—यह नियमावली राजकीय गजट में प्रकाशन के पश्चात् इसी वित्तीय वर्ष 2019-20 से लागू होगी।

4—“नगर पंचायत” से तात्पर्य नगर पंचायत कछौना पतसेनी, हरदोई से है।

5—“अधिकांसी अधिकारी” से तात्पर्य नगर पंचायत कछौना पतसेनी, हरदोई के अधिकांसी अधिकारी से है।

6—“अध्यक्ष” से तात्पर्य नगर पंचायत के अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी से है।

7—“प्रशासक/बोर्ड” का तात्पर्य नगर पंचायत कछौना पतसेनी, हरदोई के प्रशासक बोर्ड से है।

8—“अधिनियम” से तात्पर्य उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 से है।

9—“शासनादेश” का तात्पर्य उ0प्र0 भासन के आदेशों/निर्देशों से है।

10—कोई भी व्यक्ति यदि नगर पंचायत कछौना पतसेनी, हरदोई की सीमा में भवन/भूमि का स्वामी/अध्यासी है तो वे भवन/भूमि के सम्पत्ति कर निर्धारण स्वमूल्यांकन द्वारा कर लेंगे। इसके लिए नगर पंचायत गोपामऊ, हरदोई से एक आवेदन-पत्र प्राप्त कर अपने मकान का ब्यौरा देकर उपविधि में दी गयी निर्धारित दर के अनुसार स्वकर का निर्धारण करेंगे।

11—आवेदन-पत्र नगर पंचायत कछौना पतसेनी से किसी भी कार्य दिवस में प्राप्त किया जा सकता है।

12—जिन भवन/भूमि स्वामी/अध्यासी द्वारा स्वकर निर्धारण का विकल्प नहीं अपनाया जायेगा तो उसके सम्बन्ध में कर का निर्धारण व वसूली की कार्यवाही नियमानुसार नगर पंचायत कछौना पतसेनी, हरदोई द्वारा की जायेगी।

13—भवन—इसमें वह सभी अहातें, उपघर आदि एक संयुक्त परिसर में कई भवन स्थित है तो इस परिसर के सभी इमारतों के परिसर को भूमि सहित भवन कहा जायेगा और मकान का तात्पर्य उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा में अंकित परिभाषा से है।

14—“सम्पत्ति” का तात्पर्य किसी भवन/भूमि या दोनों से है।

15—“आच्छादित क्षेत्रफल” का तात्पर्य, कुर्सी के उपर जिसपर भवन निर्मित है के प्रत्येक तल के आच्छादित क्षेत्रफल से है।

16—कारपेट एरिया की गणना नियमानुसार की जायेगी—

(क) कमरे

—आन्तरिक आयाम की पूर्ण माप।

(ख) आच्छादित बरामदा

—आन्तरिक आयाम की पूर्ण माप।

(ग) बालकनी, कारीडोर, रसोई व भण्डार गृह

—आन्तरिक आयाम की 50 फीसदी माप।

(घ) गैराज

—आन्तरिक आयाम की 1/4 माप।

(ङ) स्नानगृह, शौचालय, पोर्टिको और जीने से

—कारपेट एरिया का भाग नहीं होगा।

आच्छादित क्षेत्र

अथवा

कारपेट एरिया

—आच्छादित क्षेत्र का 80 प्रतिशत भाग।

17—कर का निर्धारण—कर का निर्धारण निम्नांकित के आधार पर किया जायेगा।

(क) वार्षिक मूल्य की गणना, वार्षिक मूल्य = कारपेट एरिया × निर्धारित प्रति ईकाई का क्षेत्रफल मासिक किराया दर × 12

या

आच्छादित क्षेत्रफल का 80 प्रतिशत × निर्धारित प्रति ईकाई का क्षेत्रफल मासिक किराया दर × 12

18—करों का भुगतान—

(क) अधिशासी अधिकारी या उसके द्वारा अधिकृत कोई अधिकारी/कर्मचारी बनाये गये नियम के अधीन निर्धारित भवन/भूमि (सम्पत्ति) कर के भुगतान हेतु स्वामी/अध्यासी को बिल भेजेगा, जिसमें एक ऐसा दिनांक निर्दिष्ट होगा, नगर पंचायत कछौना पतसेनी कार्यालय अथवा उसके द्वारा अभिसूचित बैंक में कर का भुगतान किया जायेगा। गृहकर निर्धारण का भुगतान का सार्वजनिक सूचना द्वारा सूचित किये जाने पर भी निर्धारित तिथि तक किया जायेगा। निर्धारित अवधि के नियमावली में दी गयी शास्ति तथा उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 173 (क) के अनुसार कर की वसूली की जायेगी। धारा 173 (क) की कार्यवाही का खर्च तथा बकाया धनराशि पर 10 प्रतिशत वार्षिक ब्याज भी लिया जायेगा।

(ख) यह है कि नगर पंचायत की ओर से अध्यक्ष/प्रभारी अधिकारी/अधिशासी अधिकारी जैसे भी परिस्थिति हो के नगर पालिका अधिनियम की धारा 158(1)(2) के अन्तर्गत पत्र भेजकर किसी भवन/भूमि स्वामी को उनके सम्पत्ति आदि के बारे में विवरण प्रस्तुत करने तथा अन्य दस्तावेज मांगने व प्राप्त करने का अधिकार होगा।

(ग) इस उपविधि के किसी भी प्रावधान के बारे में नगर पंचायत यदि संतुष्ट है कि उपविधि के किसी प्रावधान का दुरुपयोग पंचायत द्वारा किया जा रहा है अथवा कोई प्रावधान/नियमानुसार जनहित में नहीं है, तो उक्त प्रावधान को निरस्त करने, छूट देने अथवा संशोधित करने का अधिकार नगर पंचायत को होगा।

19—किरायें पर उठे आवासीय भवनों का उपरोक्तानुसार अवधारित वार्षिक मूल्य से (ARV) जोड़ें।

(क) दस वर्ष से अधिक पुराना है तो 25 प्रतिशत अधिक होगा (+) 25 प्रतिशत

(ख) दस वर्ष से अधिक तथा बीस वर्ष से कम पुराना है तो 12.5 प्रतिशत अधिक होगा (+) 12.5 प्रतिशत

(ग) बीस वर्ष से अधिक पुराना हैं तो यथावत समझा जायेगा।

नोट—नगर पालिका अधिनियम—1916 की धारा 140(2) में यह प्रावधान है कि जहाँ नगर पंचायत किराये में किसी कारण से असाधारण परिस्थितियों में किसी भवन का वार्षिक मूल्य यदि उपर्युक्त रीति से गणना की गई हो अत्यधिक हो वहाँ नगर पंचायत किसी भी धनराशि पर जो भी न्याय संगत प्रतीत हो वार्षिक मूल्य नियमित कर सकती है।

20—व्यावसायिक सम्पत्तियों से तात्पर्य—सभी प्रकार की फुटकर दुकानें, शोरूम, बेकरी, आटाचक्की, कोयला, लकड़ी, कृषि उपकरणों के लिये केन्द्र, भीतगृह, रिजोर्ट, होटल व बेवसाइट व ऑटोमोबाइल शोरूम/सर्विस सेन्टर व भोजनालय, जलपानगृह, रेस्टोरेन्ट, कैन्टीन, सिनेमा व मल्टीप्लेक्स, अस्थाई सिनेमा, पी0सी0ओ0, पेट्रोल व डीजल फिलिंग स्टेशन, गोदाम/गैस अधिष्ठान भण्डारण तथा गोदाम, निजी कार्यालय, बैंक व अन्य अनावासीय भवनों से है।

21—औद्योगिक सम्पत्तियों से तात्पर्य—सेवा/कुटीर उद्योग, औद्योगिक कारखाने, पावरलूम कारखाना, सूचना प्रौद्योगिकी/सॉफ्टवेयर टेक्नालॉजी/एल0पी0जी0 व फिलिंग प्लाण्ट/संयंत्र/केन्द्र आदि से है।

22—इन्स्टीट्यूशनल (संस्थागत) सम्पत्तियों से तात्पर्य—राजकीय, अर्द्धराजकीय, स्थानीय निकाय कार्यालय, श्रमिक कल्याण केन्द्र, पी0ए0सी0, पुलिस लाईन, मौसम अनुसंधान केन्द्र, वायरलेस केन्द्र, अतिथि गृह, धर्मशाला, रैनबसेरा, लॉजिंग बोर्डिंग हाउस, छात्रावास, अनाथालय, सुधारालय, कारागार, हेण्डिकैप चिल्ड्रेन हाउस, शिशुगृह, एवं देखभाल केन्द्र, वृद्धावस्था केन्द्र, प्राथमिक शैक्षिक संस्थान, उच्चतर माध्यमिक इण्टर/महाविद्यालय/विश्वविद्यालय,

पोलीटेक्निक, इन्जिनियरिंग, विशिष्ट शैक्षिक संस्थान, आई0टी0आई0, डाकघर, तारघर, पुलिस स्टेशन/चौकी, अग्निशमन केन्द्र, पुस्तकालय/वाचनालय, नाट्य प्रशिक्षण केन्द्र, कलाकेन्द्र, सिलाई केन्द्र, बुनाई कढ़ाई केन्द्र, पेन्टिंग, कम्प्यूटर प्रशिक्षण केन्द्र इत्यादि, ऑडिटोरियम, नाट्यशाला, थियेटर, योगकेन्द्र, सामुदायिक केन्द्र, धर्मिक केन्द्र, बारात घर, कॉन्फेंस एवं मीटिंग हाल, प्रदर्शनी केन्द्र, रेडियो व टेलीविजन कार्यालय/केन्द्र, नर्सिंग होम व अस्पताल आदि।

नोट—जो भी सामाजिक, धर्मिक राजनैतिक संस्थायें निः शुल्क जनहित में कार्य कर रही हैं वे कर से मुक्त रहेगी परन्तु जिस धर्म/राजनैतिक संस्था का जितने भाग का उपयोग व्यवसायिक होगा उस पर कर देय होगा।

23—रेन्ट कन्ट्रोल के मकान—रेन्ट कन्ट्रोल अधिनियम, 1972 के अधीन आने वाले आवासीय भवनों पर नगर पंचायत कछौना पतसेनी, हरदोई प्रत्येक करों की गणना के लिये वार्षिक किराये का निर्धारण रेन्ट कन्ट्रोल अधिनियम के अंतर्गत नहीं होगा बल्कि गृहकर का निर्धारण उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 के प्रावधानों के अन्तर्गत शासनादेश संख्या-135/9-9-11-190-द्वि0रा0वि0आ0/04 नगर विकास अनुभाग-9 लखनऊ दिनांक 18 मार्च, 2011 के अनुसार किया जायेगा।

24—जिन भवनों/व्यावसायिक भवनों में भवन स्वामी का पता नहीं चलता है तो ऐसे भवनों में किरायेदार/अध्यासी को की गृहकर का भुगतान करना होगा।

25—करों में छूट—

(क) गृहकर की देयता वार्षिक होगी, 01 अप्रैल से 31 मार्च के मध्य संबंधित वर्ष का कर जमा करना अनिवार्य होगा।

(ख) सम्बन्धित वर्ष में कर जमा नहीं करने की दशा में आगामी वित्तीय वर्ष में गृहकर पर 10 प्रतिशत की दर से सरचार्ज देय होगा।

26—संबन्धित संसूचना प्रपत्र (क) प्राप्ति के 15 दिवस के अन्दर नगर पंचायत कार्यालय में भरकर जमा करना अनिवार्य है। भवन के क्षेत्रफल एवं दरों के सम्बन्ध में कोई त्रुटि पूर्ण विवरण होने की दशा में स्वामी अध्यासी से सम्पत्ति की देयता में होने वाले अन्तर के चार गुने धनराशि शास्ति (जुर्माना) के रूप में ली जायेगी निर्धारित अवधि तक विवरण न जमा करने की दशा में 50 वर्ग मीटर, 200 वर्ग मीटर, 400 वर्ग मीटर तथा उससे अधिक भू-खण्ड पर क्रमशः 100/500/1000/3000 रु0 तक शास्ति (जुर्माना) आरोपित करके वसूल किया जायेगा, तथा 30 दिन के विलम्ब की स्थिति में शास्ति (जुर्माना) का 5 प्रतिशत अतिरिक्त लिया जायेगा।

27—भवन किराये पर देने या रिक्त होने, भवन में निर्माण/पुनर्निर्माण होने से आच्छादित क्षेत्रफल (कारपेट एरिया) में वृद्धि होने पर तथा भवन के व्यावसायिक/औद्योगिक प्रयोग होने पर 60 दिनों के अन्दर प्रपत्र (ख) में ही पुनः विवरण भवन स्वामी/अध्यासी द्वारा कार्यालय में प्रस्तुत किया जाना अनिवार्य होगा।

28—जिन भवनों/भूमियों को नगर पंचायत कछौना पतसेनी, हरदोई द्वारा भवन/भूमि की संज्ञा दी जा चुकी है उन्हें भी प्रपत्र क और ख पर उपरोक्तानुसार सूचना भरकर जमा करना अनिवार्य है तथा उसके भवन/भूमि पर यदि कोई पूर्व का बकाया है तो प्रपत्र क के अनुसार देय कर एवं पूर्व बकाया भी जमा करेंगे।

29—मकानों को दर्ज करने सम्बन्धी—

(क) कोई भी व्यक्ति किसी भी समय यदि किसी भी भवन या भूमि पर अपना नाम अध्यासी अथवा स्वामी के रूप में करदाता सूची में अंकित कराना चाहता है तो उसे निर्धारित प्रक्रिया से आवेदन करना होगा और यदि उसके नाम के सम्बन्ध में कोई आवेदन निरस्त करते हुये विचाराधीन है तो उल्लेख लिखित रूप में किया जायेगा अन्यथा उसके बाद सूची में आवेदन के अनुसार नाम, कर निर्धारण सूची में अंकित कर दिया जायेगा।

(ख) गृहकर पंजिका में दर्ज ऐसी भूमि/भवन जो पंचायत के स्वामित्व की भूमि है जो किसी कारणवश निजी उपयोग में लायी जा रही है तो वह गृहकर पंजिका में स्वतः निरस्त/करमुक्त मानी जायेगी।

30—मकानों का हस्तांतरण सम्बन्धी नियम—

(क) यदि किसी भवन या भूमि जिस पर कर आरोपित है स्वामित्व हस्तांतरित होता है तो स्वामित्व हस्तांतरित करने वाले व्यक्ति तथा संस्था अथवा स्वामित्व पाने वाला व्यक्ति ऐसे संस्था ऐसे हस्तांतरण के 03 माह के अन्दर उसकी सूचना नगर पंचायत द्वारा निर्धारित भुल्क जमा करके निर्धारित प्रपत्र पर अध्यासी अधिकारी को प्रेषित करना अनिवार्य होगा।



(ख) यदि किसी करदाता अथवा भवन/भूमि के स्वामी की मृत्यु हो जाती है तो उसके वारिस को मृत्यु के दिनांक से 03 माह के अन्दर लिखित सूचना रु0 300.00 भुल्क जमा करके अधिासी अधिकारी को देना होगा।

(ग) यदि किसी करदाता अथवा भवन का वारिस/उत्तराधिकारी 03 माह के अन्दर सूचना देने में असफल रहता है तो 03 माह के बाद प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करते समय उसे नामान्तरण शुल्क के साथ रु0 100.00 विलम्ब शुल्क भी देय होगा तभी प्रार्थना-पत्र पर कार्यवाही किया जायेगा। यही प्रक्रिया विक्रय-पत्र के आधार पर नामान्तरण को कार्यवाही पर भी लागू होगी।

(घ) विक्रय-पत्र के आधार पर आवेदक नगर पंचायत अभिलेखों में दर्ज कराना चाहता है तो उसका शुल्क रु0 500.00 जमा करने के बाद ही कार्यवाही शुरू की जायेगी।

31-कारपेट एरिया का भाग नहीं होगा। कर निर्धारण दर-गृहकर वार्षिक मूल्य का 10 प्रतिशत तथा जलकर वार्षिक मूल्य का 10 प्रतिशत देय होगा।

32-मुख्य मार्ग का तात्पर्य-मुख्य मार्ग में सभी सड़कें आयेंगी जिसकी चौड़ाई 12 मीटर से अधिक होगी।

33-अन्य मार्ग का तात्पर्य-मुख्य मार्ग के अंदर के मार्ग व मोहल्ला/कालोनी में जाने वाली सड़क एवं समस्त गलियां अपने भागों में आयेंगी।

34-अधिशाली अधिकारी नगर पंचायत कछौना पतसेनी, हरदोई द्वारा सत्यापित मासिक किराया प्रति वर्गफुट।

35-अन्तिम निर्णय अधिशाली अधिकारी नगर पंचायत कछौना पतसेनी, हरदोई में निहित होगा।

36-अन्य व्यावसायिक भवन/मिश्रित भवन जो मुख्य मार्ग पर स्थित न हो का कर निर्धारण निर्धारित आवासीय दर का दोगुना दर पर किया जायेगा।

37-(क) किसी भी स्वामी द्वारा अध्यासित आवासीय भवन जो 30 वर्ग मी0 के माप वाले या 15 वर्ग मी0 तक कारपेट क्षेत्रफल भू-खण्ड पर निर्मित हो उसके स्वामी के स्वामित्व में नगर पंचायत कछौना पतसेनी, हरदोई की सीमा के अंतर्गत कोई अन्य भवन/भूखण्ड न हो पर वार्षिक मूल्य की गणना नहीं की जायेगी वो कर से मुक्त होंगे।

(ख) यदि आंशिक भाग का उपयोग व्यावसायिक/औद्योगिक के रूप में प्रयोग किया जा रहा है और आंशिक भाग पर निवासित है तो व्यावसायिक/औद्योगिक वाले भाग पर व्यावसायिक/औद्योगिक दर लागू होगा तथा निवासित भाग पर निवासित दर लागू होगा।

(ग) व्यावसायिक/औद्योगिक उपयोग वाले आवासों/आवासीय अंशों पर कर निर्धारण निम्न प्रकार किया जायेगा।

श्रेणी	सम्पत्ति का विवरण	अनावासीय भवन की मासिक किरायें की दर
1.	प्रत्येक प्रकार के वाणिज्यिक काम्पलेक्स, दुकानें और अन्य प्रतिष्ठान बैंक, कार्यालय, होटल, कोचिंग व प्रशिक्षण संस्थान (राज्य सरकार द्वारा सहायता प्राप्त को छोड़कर) सह दुकान की स्थिति में।	सम्बन्धित वार्ड का नियत आवासीय दर का पांच गुना
2.	टावर और होर्डिंग वाले भवन, टी0बी0 टावर दूर संचार या कोई अन्य टावर जो भवन की सतह पर या शिखर पर या खुले स्थान पर प्रतिस्थापित किये जाते हैं।	सम्बन्धित वार्ड का नियत आवासीय दर काचार गुना
3.	प्रत्येक प्रकार के क्लीनिक, पाली क्लीनिक डायग्नोस्टिक केन्द्र, प्रयोगशालायें, नर्सिंग होम, चिकित्सालय केन्द्र, मेडिकल स्टोर, स्वास्थ्य परिचर्या केन्द्र।	सम्बन्धित वार्ड का नियत आवासीय दर कातीन गुना
4.	पेट्रोल पम्प, गैस एजेन्सी, डिपो और गोदाम	सम्बन्धित वार्ड का नियत आवासीय दर कातीन गुना
5.	सामुदायिक भवन, कल्याण मण्डप शादी/बारात घर, क्लब व इसी प्रकार के भवन	सम्बन्धित वार्ड का नियत आवासीय दर कातीन गुना
6.	औद्योगिक इकाइयां सरकारी अर्धसरकारी एवं सार्वजनिक, उपक्रम कार्यालय	सम्बन्धित वार्ड का नियत आवासीय दर कातीन गुना
7.	क्रीडा केन्द्र, जिम, शारीरिक स्वास्थ्य केन्द्र, थियेटर तथा सिनेमा घर	सम्बन्धित वार्ड का नियत आवासीय दर का दो गुना
8.	अन्य प्रकार के अनावासिक भवन जो उपर्युक्त श्रेणियों में उल्लिखित नहीं हैं।	सम्बन्धित वार्ड का नियत आवासीय दर कातीन गुना
9.	छात्रावास और शैक्षणिक संस्थान जो अधिनियम की धारा 129-क के खण्ड (ग) के अधीन आच्छादित नहीं हैं।	सम्बन्धित वार्ड का नियत आवासीय दर के समान

38—अधिकासी अधिकारी नगर पंचायत कछौना पतसेनी, हरदोई द्वारा पंचायत सीमान्तर्गत स्थित भवनों/भूमियों का वार्षिक मूल्यांकन दरों पर निर्धारित किया जायेगा।

### कक्षवार (वार्डवार) निर्धारित प्रस्तावित मासिक किराया (प्रति वर्ग फीट) दरों की सूची

कक्ष/वार्ड का नाम	वार्ड संख्या	24 फीट से अधिक चौड़े मार्ग पर दर				20 फीट 24 फीट चौड़े मार्ग पर दर				12 फीट से कम चौड़े मार्ग पर दर				भूमि के सम्बन्ध में
		आर0सी0सी0	अन्य	कच्चा भवन	आर0सी0सी0	अन्य	कच्चा भवन	आर0सी0सी0	अन्य	कच्चा भवन				
		छत सहित पक्का भवन	छत सहित पक्का भवन		छत सहित पक्का भवन	छत सहित पक्का भवन		छत सहित पक्का भवन						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12 फीट से 24 फीट चौड़े मार्ग पर दर	12 फीट से कम चौड़े मार्ग पर दर		
अम्बेडकर नगर	1	0.40	0.30	0.20	0.30	0.25	0.10	0.25	0.15	0.10	0.07	0.05		
काशी नगर	2	0.40	0.30	0.20	0.30	0.25	0.10	0.25	0.15	0.10	0.07	0.05		
सदर बाजार	3	0.40	0.30	0.20	0.30	0.25	0.10	0.25	0.15	0.10	0.07	0.05		
रेलवेगंज पश्चिमी	4	0.40	0.30	0.20	0.30	0.25	0.10	0.25	0.15	0.10	0.07	0.05		
ठाकुरगंज नटपुरवा	5	0.40	0.30	0.20	0.30	0.25	0.10	0.25	0.15	0.10	0.07	0.05		
कछौना पतसेनी चौराहा पश्चिमी	6	0.40	0.30	0.20	0.30	0.25	0.10	0.25	0.15	0.10	0.07	0.05		
तिलक नगर	7	0.40	0.30	0.20	0.30	0.25	0.10	0.25	0.15	0.10	0.07	0.05		
रेलवेगंज पूर्वी	8	0.40	0.30	0.20	0.30	0.25	0.10	0.25	0.15	0.10	0.07	0.05		
इमलीपुर	9	0.40	0.30	0.20	0.30	0.25	0.10	0.25	0.15	0.10	0.07	0.05		
कछौना पतसेनी चौराहा पूर्वी	10	0.40	0.30	0.20	0.30	0.25	0.10	0.25	0.15	0.10	0.07	0.05		
कछौना बाजार पश्चिमी	11	0.40	0.30	0.20	0.30	0.25	0.10	0.25	0.15	0.10	0.07	0.05		
कछौना बाजार पूर्वी	12	0.40	0.30	0.20	0.30	0.25	0.10	0.25	0.15	0.10	0.07	0.05		

### अर्थदण्ड

उ0प्र0 नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा 299(1) में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये नगर पंचायत कछौना पतसेनी, हरदोई निश्चित करती है कि उपविधि के किसी भी नियम का उल्लंघन करना दण्डनीय अपराध होगा जो रु0 1000.00 एक हजार जुर्माना हो सकता है और निरन्तर बने रहने की दशा में अतिरिक्त अर्थदण्ड देय होगा जो सर्वप्रथम दोष सिद्ध के दिनांक या अधिकासी अधिकारी द्वारा दिये गये नोटिस के दिनांक से प्रत्येक दिवस के लिये जिसके बारे में सिद्ध हो जाये कि जिसमें अपराधी अपराध करता है, रु0 25.00 (पच्चीस रुपये) मात्र प्रतिदिन अर्थदण्ड लिया जायेगा।

ह0 (अस्पष्ट),  
अधिकासी अधिकारी,  
नगर पंचायत कछौना पतसेनी,  
हरदोई।

## कार्यालय नगर पंचायत मखनपुर, जनपद फिरोजाबाद

29 नवम्बर, 2022 ई0

सं0 430/न0 पं0 मखनपुर/2022-23—सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि नगर पंचायत मखनपुर जनपद फिरोजाबाद में केवल वही ठेकेदार/फर्म नगर पंचायत मखनपुर में सार्वजनिक निर्माण कार्यों की निविदा में प्रतिभाग कर सकेंगे, जो मान्यता प्राप्त किसी भी सरकारी संस्था में या नगर पंचायत मखनपुर जनपद फिरोजाबाद में निर्माण कार्यों को करने हेतु ठेकेदारों की सूची में पंजीकृत होंगे। नगर पालिका अधिनियम, 1916 यू0पी0एक्ट सं0-(2) सन् 1916 के अन्तर्गत जिसका प्रकाशन कराया गया था जो नगर पंचायत मखनपुर के नोटिस बोर्ड पर चस्पा की गयी थी एवं दैनिक समाचार-पत्र हिन्दुस्तान एवं सांध्य पहल में प्रकाशित कर 15 दिन की अवधि में आपत्ति/सुझाव मांगे गये थे। किन्तु कोई आपत्ति/सुझाव प्राप्त नहीं हुई।

अतः उक्त उपविधि को अन्तिम मानते हुये मात्र इसकी सूचना प्रकाशित की जा रही है जो उत्तर प्रदेश सरकार के गजट में प्रकाशन की दिनांक से लागू होगी।

### ठेकेदार पंजीकरण उपविधियाँ

#### संक्षिप्त नाम एवं प्रारम्भ—

1—यह उपविधि उत्तर प्रदेश नगर पालिका अधिनियम, 1916 की धारा-(2) के अधीन प्रदत्त शक्ति का प्रयोग करके नगर पंचायत मखनपुर जनपद फिरोजाबाद में अपनी सीमा में परियोजनाओं के विधिवत् संचालन हेतु ठेकेदारी पंजीकरण उपविधि बनायी है।

2—परिभाषाएँ—विषय या प्रसंग में कोई बात प्रतिकूल न होने पर इन उपविधियों में—

(क) अधिनियम का तात्पर्य संयुक्त प्रान्त नगर पालिका अधिनियम 1916 यू0पी0एक्ट सं0-(2) सन् 1916 से है।

(ख) नगर का तात्पर्य नगर पंचायत मखनपुर से है।

(ग) अध्यक्ष/प्रशासक का तात्पर्य नगर पंचायत मखनपुर जनपद फिरोजाबाद के अध्यक्ष/प्रशासक से है।

(घ) समिति—का तात्पर्य नगर पंचायत मखनपुर जनपद फिरोजाबाद के अन्तर्गत गठित/निर्वाचित समिति से है।

(ङ) अधिशासी अधिकारी का तात्पर्य नगर पंचायत मखनपुर जनपद फिरोजाबाद के अधिशासी अधिकारी से है।

3—केवल वही ठेकेदार नगर पंचायत मखनपुर जनपद फिरोजाबाद में सार्वजनिक निर्माण कार्यों की निविदा में प्रतिभाग करने पर कर सकेंगे, जो किसी संस्था में रजिस्टर्ड हो तथा निविदा स्वीकृत होने के पश्चात् नगर पंचायत मखनपुर जनपद फिरोजाबाद में नियमानुसार रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होगा।

4—विभिन्न सामग्रियों के आपत्तिकर्ता भी नियमानुसार रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।

5—कार्यालय नगर पंचायत मखनपुर जनपद फिरोजाबाद में ऐसे ठेकेदारों के नाम पंजीकृत किये जाने हेतु एक पंजिका सुरक्षित रखी जायेगी। जिसमें अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष/प्रशासक नगर पंचायत मखनपुर से प्रमाणित पंजीकृत ठेकेदारों के नामों की प्रविष्टियाँ अंकित होंगी।

6—यह उपविधि नगर पंचायत मखनपुर जनपद फिरोजाबाद के अन्तर्गत क्रियान्वित की जाने वाली समस्त परियोजनाओं पर लागू होंगी। उपविधि के अन्तर्गत पंजीकृत ठेकेदार फर्म एवं उद्योग, लघु उद्योग आदि विद्युत् सुरक्षा उ0प्र0 शासन द्वारा निर्मित प्रमाण-पत्र धारी विद्युत् ठेकेदार आदि। जो इस उपनियम की अन्य शर्तों को पूरा करते हैं, नगर पंचायत मखनपुर जनपद फिरोजाबाद में निविदाएं डालने हेतु अधिकृत होंगे।

7—पंजीकृत ठेकेदारों के पंजीकरण की कार्यवाही 03 (तीन) भागों में नियमानुसार अंकित होंगी।

**वर्ग अ—**ठेकेदार जिसकी क्षमता किसी भी सीमा तक निर्माण कार्यों व मरम्मत कार्यों को करने की हो व स्वयं करना उचित समझता हो।

**वर्ग ब**—ठेकेदार जो रु0 25,00,000/— तक के निर्माण कार्य व मरम्मत कार्य करने की क्षमता हो या ऐसे समस्त कार्यों को करने के लिए अधिकृत/मान्य समझा जायेगा।

**वर्ग स**—ठेकेदार जो रु0 15,00,000/— तक के निर्माण कार्य व मरम्मत कार्य करने की क्षमता हो या ऐसे समस्त कार्यों को करने के लिए अधिकृत/मान्य समझा जायेगा।

**8**—ठेकेदार/फर्म पंजीकरण हेतु प्रार्थना-पत्र अपनी 02 (दो) प्रमाणित फोटो, जिलाधिकारी द्वारा निर्गत चरित्र प्रमाण-पत्र एवं हैसियत प्रमाण-पत्र व आयकर, जी0एस0टी0 अदेयता प्रमाण-पत्र संलग्न कर आवेदन प्रस्तुत करेगा। साथ ही साथ (वर्ग अ के लिए रु0 15,000/— वर्ग ब के लिए रु0 10,000/—, वर्ग स के लिए रु0 5,000/— जमा करने होंगे) बिना पंजीकरण शुल्क के प्रमाण-पत्र पर विचार नहीं होगा। पंजीकरण अवधि प्रत्येक वित्तीय वर्ष 01 अप्रैल से आगामी 03 (तीन) वर्ष अथवा हैसियत, चरित्र प्रमाण-पत्र की मान्य अवधि तक वैध मानी जायेगी। ठेकेदार पंजीकरण का नवीनीकरण कराना चाहता हो, तो नवीनीकरण शुल्क के रूप में वर्ग अ के लिए रु0 5,000/— वर्ग ब के लिए रु0 3,000/— तथा वर्ग स के लिए रु0 1,500/— जमा कराने होंगे।

**9**—ठेकेदार/फर्म का नाम पंजीकृत होने के पश्चात् नियम में वर्णित (वर्ग अ के लिए रु0 50,000/—, वर्ग ब के लिए रु0 30,000/—, तथा वर्ग स के लिए रु0 15,000/—) जमानत धनराशि अधिशासी अधिकारी, नगर पंचायत मखनपुर के पक्ष में डिपॉजिट के रूप में कार्यालय में जमा करनी होगी। ऐसी धनराशि सामान्य रूप से 05 (पाँच) वर्ष तक या ठेकेदार/फर्म का पंजीकरण वैध रहने तक (नवीनीकरण को सम्मिलित करते हुए) जमा रहेगी। साथ ही ठेकेदार/फर्म द्वारा अपना पंजीकरण निरस्त कराने पर जमानत धनराशि प्रार्थना-पत्र प्रस्तुत करने पर वापस की जायेगी, परन्तु ऐसी जमानत धनराशि को वापस करने का पूर्ण अधिकार अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष/प्रशासक, नगर पंचायत मखनपुर जनपद फिरोजाबाद को होगा। ऐसी जमानत धनराशि सम्बन्धित ठेकेदार/फर्म के निर्माण कार्यों के सन्तोषजनक रहने व किये जाने वाले किसी भी निर्माण कार्यों के लिए विचारणीय कार्यवाही तक स्थगित व जब्त की जा सकती है।

**10**—ठेकेदार/फर्म को पंजीकरण के समय कार्यालय जिलाधिकारी द्वारा जारी हैसियत प्रमाण-पत्र वर्ग अ के लिए रु0 100,00,000/— वर्ग ब के लिए रु0 50,00,000/— तथा वर्ग स के लिए रु0 25,00,000/— प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।

**11**—ठेकेदार के नाम स्वीकृत निर्माण कार्य यदि ठेकेदार/फर्म के द्वारा कार्य प्रारम्भ न किया गया हो तो या अपनी इच्छा से निर्माण कार्य न करना चाहता हो तो ठेकेदार/फर्म को साधारण जमानत व कार्य के निमित्त जमा की गयी धनराशि का भुगतान नहीं होगा और ऐसी धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

**12**—दुर्घटना व मृत्यु की स्थिति में ठेकेदार/फर्म से सम्बन्धित किसी ऐसे व्यक्ति को भुगतान व जमानत धनराशि देय होगी, जिसके सम्बन्ध में स्वामित्व होने का अधिकार-पत्र सक्षम अधिकारी/न्यायालय से देय होगा।

**13**—निर्माण कार्य करने के बीच में यदि कोई ठेकेदार/फर्म अपनी इच्छा से कार्य बन्द करें या जानबूझ कर विलम्ब करना चाहता है तथा ऐसा अधिशासी अधिकारी, अध्यक्ष/प्रशासक को विदित हो जाये तथा संतुष्ट हो तो ठेकेदार/फर्म के नाम स्वीकृत निर्माण कार्य अस्वीकृत किया जायेगा व ऐसे ठेकेदार/फर्म के द्वारा किये गये अधूरे कार्य का भुगतान नहीं होगा। ऐसी स्थिति में भी ऐसे अधूरे निर्माण कार्यों को पंजीकृत ठेकेदारों/फर्मों में से किसी भी ठेकेदार/फर्म से स्वीकृत दरों पर निर्माण कार्य करवाया जायेगा तथा निर्माण कार्य के लिए पुनः निविदाएँ आमंत्रित की जायेंगी।

**14**—प्रत्येक ठेकेदार/फर्म को निर्माण कार्य से सम्बन्धित समस्त जानकारी, निर्माण स्थल का निरीक्षण आदि के सम्बन्ध में निविदा लेने से पूर्व पूर्ण रूप से प्राप्त करनी होगी।

**15**—निर्माण कार्य के प्रावन्कलन नगर निगम फिरोजाबाद जिले के लिए अधिकृत या स्थानीय निकाय के लिए अधिकृत निर्माण कार्यों के लिए नामित अवर अभियन्ता द्वारा निर्मित होंगे तथा किसी भी कार्य को करवाने में स्वीकृत माप पुस्तिका में वर्णित दरों के अन्तर्गत ही ठेकेदारों का भुगतान किया जायेगा।

**16**—निर्माण कार्य सम्पन्न करते समय या निर्माणाधीन स्थिति में कार्य रूप में परिवर्तन करने का अधिकार अधिशासी अधिकारी, प्राविधिक अधिकारी, अध्यक्ष/प्रशासक तथा जिला मजिस्ट्रेट में ही निहित होगा। ठेकेदार/फर्म की इच्छा से, स्वीकृत प्लान से बाहर या किसी प्रकार के परिवर्तन किये जाने की स्थिति में उक्त वर्णित किसी भी अधिकारी को निर्णय लेने का पूर्ण अधिकार होगा कि ऐसे निर्माण कार्य को ठेकेदार/फर्म को आदेशित करते हुए तुड़वा दिया जाये या रहने दिया जाये। ठेकेदार/फर्म द्वारा कार्य अपनी इच्छा से कराये जाने की स्थिति में ठेकेदार/फर्म से कार्य की कुल आगणन धनराशि के 10 प्रतिशत की धनराशि जुर्माने के रूप में वसूल की जायेगी तथा ठेकेदार की स्वेच्छा से किये गये निर्माण कार्य का किसी भी दशा में भुगतान नहीं होगा।

**17**—स्वीकृत निर्माण कार्य छल-कपट या किसी अन्य प्रकार से ठेकेदार/फर्म द्वारा अपने हितों में जिससे की उसे अधिक लाभ हो रहा हो या होना पाया जाये, तो ऐसी स्थिति में अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष/प्रशासक व प्राविधिक अधिकारी को लागत निर्माण का 10 प्रतिशत तक जुर्माना करने का अधिकार होगा और कार्य भी करावाने के बावत नोटिस भी जारी किया जायेगा। पुनः अवहेलना करने पर 10 प्रतिशत कटौती उसके अग्रिम भुगतान या अन्तिम भुगतान बिल से काट ली जायेगी, जो किसी भी स्थिति में उसे देय नहीं होगा।

**18**—ठेकेदार/फर्म का निर्माण कार्य सन्तोषजनक न पाये जाने की स्थिति में या निर्माण कार्य के दौरान पूरे उपकरणों/सामग्रियों की वांछित मात्रा का प्रयोग न करने व पाये जाने पर अधिशासी अधिकारी को अधिकार होगा कि तत्काल ठेकेदार को नोटिस देकर काम रूकवा देगा।

**19**—ठेकेदार/फर्म के नाम प्रशासकीय स्वीकृति किसी भी निर्माण कार्य को करवाने के लिए दिये जाने से पूर्व प्रत्येक ठेकेदारों/फर्मों को आवश्यक होगा कि कार्य को पूरा करने हेतु अनुबन्ध-पत्र के लिए वांछित स्टाम्प पेपर को स्वयं क्रय कर कार्यालय में प्रस्तुत करेगा।

**20**—यदि किसी ठेकेदार/फर्म का कार्य एवं आचरण असन्तोषजनक पाया गया या पाया जाये कि ठेकेदार/फर्म ने नियमों का उल्लंघन किया है या निर्धारित शर्तों का पालन प्राविधिक स्तर से नहीं किया गया तो उसका नाम ठेकेदारी से ही नहीं बल्कि अनुमोदित सूची में से भी काट कर अधिशासी अधिकारी उसे ब्लैक लिस्टेड कर सकता है तथा भविष्य में उसे निविदा प्रपत्र प्रस्तुत करने के अधिकार से वंचित कर सकता है।

**21**—ठेकेदार/फर्म को अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष/प्रशासक/अवर अभियन्ता नगर पंचायत मकखनपुर जनपद फिरोजाबाद आदि के निर्देशों को पूर्ण पालन करना होगा या अधिकारी व प्राविधिक अधिकारी निर्माण कार्य का निरीक्षण कर सकते हैं। त्रुटियों के अनुपालन हेतु निर्देश दे सकते हैं, कार्य को घटा या बढ़ा सकते हैं या वांछित परिवर्तन हेतु लिख सकते हैं। जिसका अनुपालन ठेकेदार/फर्म को करना होगा।

**22**—निविदा प्रपत्र में वर्णित व उल्लिखित शर्तों का अनुपालन जैसे भी सामूहिक या परिवर्तन की शर्तों का अनुपालन करना अंकित होगा, ठेकेदार/फर्म को मान्य होगा।

**23**—नगर पंचायत मकखनपुर जनपद फिरोजाबाद के समस्त प्रकार के निर्माण कार्यों के लिए प्रयुक्त उपकरण, साज सामग्री, या निर्माण स्थल पर लायी जाने वाली निर्माण सामग्री जैसे ईंट पत्थर, बजरी आदि यदि पहले से पड़ी है तो उसका प्रयोग करने की स्थिति में अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष/प्रशासक को अधिकार हो कि उसकी कीमत निर्धारित कर, ठेकेदार/फर्म के बिलों में से धनराशि काट लें, जिसमें ठेकेदार/फर्म को कोई आपत्ति नहीं होगी। इसके अतिरिक्त निर्माण स्थल से जो उपकरण आदि हटवाने की आवश्यकता होगी और जिसका प्रयोग करना ठेकेदार/फर्म को करने की स्वीकृति नहीं होगी, सामग्री व निकाली हुई सम्पत्ति को ठेकेदार/फर्म को कार्यालय में जमा कराना होगा, अन्यथा ऐसी सामग्री, उपकरण आदि की कीमत जो नियत की जायेगी उसकी वसूली ठेकेदार से की जायेगी या उसके अग्रिम या नवीनतम भुगतान बिलों से काटी जायेगी।

**24**—निर्माण कार्य प्रारम्भ करने के पश्चात् किये गये निर्माण कार्य के मूल्यांकन लागत जिसका निर्धारण प्राविधिक अधिकारी के द्वारा किया जायेगा व माप पुस्तिका में अंकित होगा के कार्य का भुगतान जैसी की उचित समझा जायेगा ठेकेदार/फर्म की कार्य को प्रगति देने व सुविधा की दृष्टि से अग्रिम भुगतान भी देय होगा।

**25**—यदि ठेकेदार/फर्म कार्य को निर्धारित अवधि में पूरा नहीं करता है तो अधिशासी अधिकारी/अध्यक्ष/प्रशासक को अधिकार होगा कि ठेकेदार को कार्य का जनहित में प्रतिदिन आर्थिक दण्ड प्रस्तावित कर कराया जायेगा, लेकिन किन्हीं परिस्थितियों में समया वृद्धि भी मान्य समझी जायेगी।

**26**—प्रत्येक निर्माण कार्य के अन्तिम भुगतान के लिए संस्तुति एवं प्रस्तुतीकरण करने के पूर्व ठेकेदार द्वारा सम्पन्न किये कार्य को प्राविधिक अधिकारी द्वारा ही कार्य ठीक हुआ है तथा गुणवत्ता एवं मानक का पूर्ण रूप से पालन किया गया है के आशय का प्रमाण-पत्र दिया जायेगा। प्रमाण-पत्र के अभाव में अंतिम भुगतान बिल की प्रशासकीय स्वीकृति नहीं ली जायेगी और न ही भुगतान देय होगा।

**27**—कार्य ठीक पाये जाते रहने व टूट-फूट न होने की स्थिति में कार्य में निमित्त जमा की गयी जमानत की धनराशि जो वित्तीय हस्त पुस्तिका अनु0-365 के अधीन ठेकेदार/फर्म को जमा करनी होगी। यदि एन0एस0सी0 जमा करते हैं तो 05 प्रतिशत छुट समयानुसार अनुमान्य होगी, जो ठेकेदार द्वारा या बिलों के माध्यम से उपरोक्तानुसार काटी जायेगी, जमा करायी गयी धनराशि ठेकेदार/फर्म देय होगी, जब की उसकी अवधि 06 (छः) माह की न हो जाये। 06 (छः) माह की अवधि से तात्पर्य ठेकेदार को अंतिम भुगतान दिये जाने की तिथि से मानी जायेगी। निर्माण कार्य असन्तोषजनक पाये जाने की दशा में धरोहर/जमानत धनराशि तभी देय होगी जब ठेकेदार/फर्म त्रुटिपूर्ण कार्य को ठीक करा देता है। अन्यथा ऐसे समस्त मरम्मत कार्य नगर पंचायत मकखनपुर जनपद—फिरोजाबाद द्वारा करा दिया जायेगा। जमा धरोहर/जमानत धनराशि जब्त कर ली जायेगी।

**28**—निर्माण कार्य तकनीकी दृष्टिकोण से मानक के अनुरूप में सुनिश्चित हो इसके लिए नामित अवर अभियन्ता तथा ठेकेदार/फर्म दोनों जिम्मेदार होंगे तथा ठेकेदार कार्य प्रारम्भ से पूर्व नगर पंचायत मकखनपुर जनपद—फिरोजाबाद एवं सम्बन्धित अवर अभियन्ता से सम्पर्क कर अवगत करायेगा। अवर अभियन्ता द्वारा स्थल निरीक्षण समय-समय पर किया जाना अनिवार्य होगा जिससे कार्य में गुणवत्ता का पूर्ण रूप से पालन हो सकें।

अमर बहादुर सिंह,  
अधिशासी अधिकारी,  
नगर पंचायत, मकखनपुर,  
फिरोजाबाद।

### NOTICE

I Alqamah Adil son of Mohammad Adil Husain R/o H. N. 887 Chatari Compound Opp. Malkhan Singh Hospital Rasalganj, Aligarh. Hereby solemnly affirm that in 10th Class Marksheet my name is written as AL-QAMAH ADIL and my Father's name written as MOHD. ADIL but my correct name is ALQAMAH ADIL and my Father's correct name is MOHAMMAD ADIL HUSAIN for all purpose in future.

Alqamah Adil.

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मे0 मोहनका एजेंसीज ग्राम अहमदपुर जट GT रोड, तहसील सिधौली सीतापुर में साझेदार श्री पंकज अग्रवाल पुत्र प्रेम नारायण अग्रवाल निवासी गुलाब वाटिका अलीगंज लखनऊ एवं श्रीमती बबिता अग्रवाल पुत्री मुकुट प्रसाद अग्रवाल निवासी गुलाब वाटिका अलीगंज लखनऊ एवं श्रीमती कमला देवी पुत्री श्री काशी प्रसाद निवासी जेल रोड सीतापुर, फर्म में साझेदार थी। श्रीमती कमला देवी

की मृत्यु 12 दिसम्बर, 2017 को हुई थी जिसके बाद फर्म में अब दो साझेदार हैं श्री पंकज अग्रवाल एवं बबिता अग्रवाल। यह घोषणा करता हूँ कि एतद्वारा यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त के सम्बन्ध में समस्त विधिक औपचारिकताएं स्वयं मेरे द्वारा पूर्ण की गयी हैं। पंकज अग्रवाल, साझेदार, मे0 मोहनका एजेंसीज, ग्राम अहमदपुर जट GT रोड सिधौली सीतापुर।

पंकज अग्रवाल,

### सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरी पत्नी का सही नाम ममता है जो मेरे सर्विस रिकार्ड के डिस्चार्ज बुक के हस डाक्यूमेन्ट में अंकित है। त्रुटिवश मेरी पत्नी के पैनकार्ड संख्या आईएचकेपीएस 0678 पी में ममता सोनकर अंकित हो गया जो कि गलत है। उपरोक्त दोनों नाम मेरी पत्नी का ही हैं। भविष्य में मेरी पत्नी को उनके सही नाम ममता पत्नी प्रमोद कुमार सोनकर के नाम से जाना और पहचाना जाय। प्रमोद कुमार सोनकर पुत्र श्री राम कैलाश सोनकर परसिनपुर फूलपुर, प्रयागराज है।

प्रमोद कुमार सोनकर।

**NOTICE**

It is hereby informed that the name of my Father has been Wrongly transcribed as MOHAMMED AWAIS instead of his real name MOHAMMAD VAISH in C.B.S.C. 10<sup>th</sup> and 12<sup>th</sup>.

Syed Mohamed Asim  
S/o Mohammed Vaish,  
18E/3K/R Karamat Ki Chowki,  
Kareli, Allahabad.

**सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स नोएडा इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज पता एफ 35 सैक्टर 8 नोएडा जिला गौतमबुद्धनगर उत्तर प्रदेश के परिवर्तन के सम्बन्ध में आपको सूचित करना है कि संशोधित पार्टनरशिप डीड दिनांक 10 मई, 2019 के अनुसार फर्म में दो पार्टनर थे (1) श्री नरेन्द्र कुमार महेन्द्र, पुत्र स्व0 रघवीर सिंह महेन्द्र (2) श्रीमती मीना महेन्द्र पुत्री श्री राम आसरे वर्मा थे। यह कि फर्म की संशोधित साझीदारीनामा डीड दिनांक 15 फरवरी, 2021 के अनुसार फर्म में दिनांक 15 फरवरी, 2021 में साझेदार नं0-1 श्री नरेन्द्र कुमार महेन्द्र पुत्र स्व0 श्री रघवीर सिंह महेन्द्र जी का निधन हो गया है। तथा अब इनके स्थान पर दिनांक 15 फरवरी, 2021 को नई साझीदार नं0-1 कु0 नंदेका महेन्द्र पुत्री स्व0 नरेन्द्र कुमार महेन्द्र जी व साझीदार नं0 2 कु0 निहारीका महेन्द्र पुत्री स्व0 नरेन्द्र कुमार महेन्द्र जी स्वेच्छा से इस फर्म में नई साझेदार आई है व साझीदार की आपसी सहमती से फर्म में क्रमशः तीन साझेदार हो गये हैं। अब क्रम से (1) श्रीमती मीना महेन्द्र पुत्री श्री राम आसरे वर्मा (2) कु0 नंदेका महेन्द्र पुत्री स्व0 नरेन्द्र कुमार महेन्द्र (3) कु0 निहारीका महेन्द्र पुत्री स्व0 नरेन्द्र कुमार महेन्द्र साझेदार हो गये हैं।

साझेदार,  
श्रीमती मीना महेन्द्र।

**सूचना**

मेरे शैक्षणिक, अन्य समस्त अभिलेखों में मेरे पिता का नाम एस0आर0 भास्कर दर्ज है, पूर्ण नाम साहब राम भास्कर है, दोनों नाम एक ही व्यक्ति के हैं भविष्य में मेरे समस्त शैक्षणिक, अन्य अभिलेखों में उनका नाम साहब राम भास्कर पढ़ा लिखा जाना जाये।

राहुल देव भास्कर,  
पुत्र श्री साहब राम भास्कर,  
16ए, कृष्णापुरी, गढ़ी भदौरिया,  
आगरा।

**NOTICE**

It is to inform that the partnership firm "M/s Mohibullapur Bharat Gas Service" in which Rachna Kesarwani and Surya Kumar Gupta were partners, has been dissolved with the effect from August 25, 2022. And all the assets and liabilities will be of Surya Kumar Gupta after the said date.

It is hereby further informed that all the legal proceedings in this regard have been done by me.

Surya Kumar Gupta,

**सूचना**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मेरा वास्तविक नाम चंद्रप्रभा जायसवाल पत्नी राकेश कुमार जायसवाल है जो मेरे शैक्षणिक अभिलेखों में, आधार कार्ड, पैनकार्ड, पासपोर्ट में अंकित है। त्रुटिवश मेरे पुत्र के हाईस्कूल प्रमाण-पत्र सह अंक-पत्र में मेरा घर का नाम शालू जायसवाल अंकित हो गया है। उपरोक्त दोनों नाम मेरे ही हैं। भविष्य में मुझे चंद्रप्रभा जायसवाल पत्नी राकेश कुमार जायसवाल के नाम से जाना व पहचाना जाये। चंद्रप्रभा जायसवाल पत्नी राकेश कुमार जायसवाल निवासिनी 128/117 एच-2 ब्लॉक किदवई नगर, कानपुर नगर।

चंद्रप्रभा जायसवाल।

**शुद्धि-पत्र**

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं रूबी सिंह पत्नी राजीव कुमार सिंह निवासिनी एन-14/49 ए-1 कृष्ण देव नगर सरायनन्दन जिला वाराणसी मे0 एस0आर0जी0 इन्फ्राटेक जिसका पंजीकरण सं0 वी ए आर/0010364 दिनांक 20 अक्टूबर, 2021 सं0 01437/2021-2022 है फर्म के नाम परिवर्तन से सम्बन्धित सूचना राजकीय राज-पत्र में दिनांक 10 दिसम्बर, 2022 को प्रकाशित करायी थी जिसे त्रुटिवश एस जी आर इन्फ्राटेक की जगह एस जी आर इन्फ्राटेक मुद्रित हो गया था जो गलत है। मे0 एस जी आर इन्फ्राटेक की जगह मे0 एस जी आर इन्फ्राटेक पढ़ा व समझा जाय।

रूबी सिंह,  
एन 14/49ए-1 कृष्ण देव नगर,  
सरायनन्दन, जिला-वाराणसी।